चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

05 जनवरी–11 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

ऋण की रेवड़ियां बांट रहा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अरबों रुपये डूबे

घोटालेबाजों का बैंक..!

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ में तैनात अफसरों की ऋण आवंटन घोटाले में अहम भूमिका रही है. लखनऊ में भी ऋण बांटने में घोर अनियमितताएं की गई हैं. दिवालिया होने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों, घोटालेबाज कंपनियों और फर्जी फर्मों को ऋण की रेवड़ियां बांटने में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नाम अव्वल रूप से सामने आया है. ऋण लेकर फरार हो जाने वाली कंपनियों या ऋण लेने के बाद खुद को दिवालिया घोषित कर देने वाली फर्मों से वसूली में नाकाम होने के बाद वसूली ट्रिब्यूनल के समक्ष मत्था टेक देने का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने चलन बना लिया है. चौथी दुनिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.

प्रभात रंजन दीन

सारधा चिटफंड घोटाले से भी जुड़े हैं तार

बैंक ने झेंप मिटाने के लिए 27 अफसरों के ख़िलाफ़ जारी की चार्जशीट

सीबीआई ने की कई अफसरों से पूछताछ

नुक़सान के बोझ तले दबे बैंक के बंद होने के आसार

सारधा चिटफंड घोटाले से जुड़ी फर्म से लेकर फर्जी एविएशन कंपनियों तक को अरबों रुपये का ऋण बांटने और सरकारी ज़मीनों को भी गिरवी रखने में कोई संकोच न करने वाले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जांच–पड़ताल शुरू कर दी है. सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कोलकाता मुख्यालय के कुछ आला अफसरों से सख्त पूछताछ भी की है. इससे अफरातफरी में आए बैंक प्रबंधन ने दो दर्जन से अधिक आला अफसरों के ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी की है और उनका तबादला कर दिया है. लेकिन, यह कार्रवाई भी धोखा है. ऋण आवंटन का घोटाला करने वाले अफसरों को बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई है. इसमें भी प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों ने खुद को बचा लिया है. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ में तैनात अफसरों की ऋण आवंटन घोटाले में अहम भूमिका रही है. लखनऊ में भी ऋण बांटने में घोर अनियमितताएं की गई हैं. दिवालिया होने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों, घोटालेबाज कंपनियों और फर्जी फर्मों को ऋण की रेवड़ियां बांटने में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नाम अव्वल रूप से सामने आया है. ऋण लेकर फरार हो जाने वाली कंपनियों या ऋण लेने के बाद खुद को दिवालिया घोषित कर देने वाली फर्मों से वसूली में नाकाम होने के बाद वसूली ट्रिब्यूनल के समक्ष मत्था टेक देने का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने चलन बना लिया है. रद्दी ऋण (बैड–लोन) के कारण यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ग़ैर उत्पादक आस्तियां (एनपीए) इतनी अधिक हो चुकी हैं कि वे उत्तर प्रदेश के समूचे बजट से भी बहुत ऊपर चली गई हैं. ऋण घोटाले के बोझ से दबे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बंद होने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है.

हेलिकॉप्टर खरीदने के नाम पर ऋण देने का तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को शौक है. लखनऊ हो या कोलकाता, हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए ऋण का प्रस्ताव दें और ऋण फौरन हाजिर. फिर ऋण लेकर बड़े आराम से फरार हो जाएं. बैंक भी खुश और आप भी खुश. बैंक के सीएमडी और सीआरएम, यानी चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक और चीफ रीजनल मैनेजर सेवा–भक्ति से प्रसन्न हुए नहीं कि ऋण जारी हुआ. ऋण लेकर फरार होने के बाद भी लंबे अर्से तक उस ऋण को अनुत्पादक आस्तियों में डालने या ट्रिब्यूनल में जाने की बैंक को फुर्सत नहीं रहती. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सीएमडी रहीं अर्चना भार्गव के स्वैच्छिक अवकाश की वजहें अब भी रहस्य में हैं. लेकिन, उन वजहों पर खुफिया एजेंसियां काफी सक्रियता से काम कर रही हैं. अब धीरे–धीरे यह बात खुल रही है कि अर्चना भार्गव का स्वैच्छिक अवकाश पूर्व नियोजित था और बैंक के शीर्ष प्रबंधन और तत्कालीन सत्ता के शीर्ष गलियारे की इसमें सहमति थी. उनके इस्तीफ़े के पीछे लगातार बढ़ता हुआ वह सारा ऋण भी प्रमुख कारण था, जिसकी वसूली नहीं की गई. दिसंबर 2013 के अंत तक यूबीआई का वसूल न हो पाने वाला ऋण (एनपीए) रिकॉर्ड 8,546 करोड़ रुपये पर था. यह कौन–सा ऋण था, जिसकी वसूली नहीं की गई? वसूली क्यों नहीं की गई? या कुछ ऋणों को नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट वाले खाते में डालने से शातिराना तरीके से रोक लिया गया? इसी वजह से तो नहीं अर्चना भार्गव इस्तीफ़ा देकर दृश्य से अचानक गायब हो गईं? तब सत्ता कांग्रेस की थी और कांग्रेस के नेता भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उपकृत थे, लिहाजा अर्चना भार्गव के विभिन्न बैंकों में लिए गए विभिन्न फ़ैसलों या यूबीआई के ही खातों की सीबीआई से जांच कराई गई. नहीं तो ऐसे–ऐसे ऋणों का भेद खुल जाता, जो विजय माल्या हों या रॉबर्ट वाड्रा या पवन बंसल या सारधा चिटफंड कंपनी के सुदीप्तो सेन या सुब्रत राय सहारा जैसे कई लोगों को हल्के–फुल्के तरीके से बांट दिए गए थे.

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों की पहले लखनऊ की करतूतें देखते चलें. लखनऊ की हिंद इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी मास्टर डाटा के मुताबिक, इसका पता 194/18/4, लक्ष्मण प्रसाद रोड, लखनऊ है. सैयद रईस हैदर व राना रिजवी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं. इसमें राना रिजवी का पता कंपनी वाला और रईस हैदर का पता हुंदरही, गंगौली, ज़िला गाजीपुर, यूपी लिखा है. इस कंपनी की पेड–अप कैपिटल (प्रदत्त पूंजी) आठ लाख रुपये है. महज आठ लाख रुपये की पूंजी वाली कंपनी को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सौ करोड़ रुपये का ऋण दे दिया. कंपनी ऋण लेकर फुर्र हो गई. इस ऋण को मंजूर करने की इतनी आपाधापी थी कि यूबीआई लखनऊ के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर विनोद बब्बर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अर्चना भार्गव

दीपक नारंग

लखनऊ की हिंद इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी मास्टर डाटा के मुताबिक, इसका पता 194/18/4, लक्ष्मण प्रसाद रोड, लखनऊ है. सैयद रईस हैदर व राना रिजवी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं. इसमें राना रिजवी का पता कंपनी वाला और रईस हैदर का पता हुंदरही, गंगौली, ज़िला गाजीपुर, यूपी लिखा है. इस कंपनी की पेड-अप कैपिटल (प्रदत्त पूंजी) आठ लाख रुपये है. महज आठ लाख रुपये की पूंजी वाली कंपनी को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सौ करोड़ रुपये का ऋण दे दिया.

बैंक में घोटाले बेइंतिहा, ईडी कुछ जानते ही नहीं

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग से यह पूछा गया कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा में रॉयल एविएशन या एयर रॉयल एविएशन नामक कंपनी का खाता है कि नहीं और अगर है, तो यह खाता स्ट्रेस्ड अकाउंट है या उसे एनपीए घोषित किया जा चुका है? तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह क्या इनमें से किसी फर्म के मालिक हैं? सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों से पूछताछ क्यों की है? बैंक ने सरकारी ज़मीनों के एवज में जो ऋण दे रखे हैं, उनकी वसूली के क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ईडी दीपक नारंग ने ये सारे सवाल तसल्ली से सुने, लेकिन जवाब में कहा, आई एम नॉट अवेयर (मेरी जानकारी में नहीं है). विडंबना ही तो है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में घोटाले बेइंतिहा हो रहे हैं, लेकिन बैंक के ईडी कहते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं. उल्लेखनीय है कि हेलिकॉप्टर खरीदने के नाम पर लखनऊ की हिंद इंफ्राटेक कंपनी रही हो या कोलकाता की एविएशन कंपनी, उसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण दिए, जिसे लेकर उक्त कंपनियां फरार हो गईं. इसी तरह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

धर्मांतरण विवाद : क्या कहता है भारतीय क़ानून पेज-04

सशक्त विपक्ष मजबूत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है पेज-05

बिहार : आरोप-प्रत्यारोप में फंसा विकास पेज-07

साई की महिमा पेज-12

घोटालेबाजों का बैंक..!

पृष्ठ एक का शेष

ने प्रस्ताव को क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत करते हुए उसे मुख्यालय भेज दिया और बैंक बोर्ड की आपत्ति के बावजूद अर्चना भार्गव ने चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक रहते हुए मंजूरी की मुहर लगा दी. इन्हीं विनोद बब्बर के ख़िलाफ़ बैंक प्रबंधन ने चार्जशीट जारी की है और इनका तबादला पश्चिम बंगाल के हुगली में कर दिया है, लेकिन डीजीएम की तरक्की देने के साथ.

खैर, यूबीआई के सूत्रों ने कहा कि हिंद इंफ्रा के ऋण लेने का कारण हेलिकॉप्टर खरीदना बताया गया था. इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए इस संवाददाता ने विनोद बब्बर को फोन किया. जैसे ही हिंद इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के ऋण के बारे में उन्होंने सवाल सुना, वैसे ही बोले, मैं तो मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं. आप इस बारे में मुख्यालय से बात करिए. ऋण तो आपने सैंक्शन किया था, फिर उसकी वसूली में कोताही क्यों की गई? इस सवाल को भी उन्होंने कोलकाता मुख्यालय पर टालने की कोशिश की, लेकिन इतना तो बोल ही दिया कि यह तो पुरानी कहानी हो गई. उनसे पूछा गया कि साल-दो साल के दरम्यान जारी ऋण पुरानी कहानी कैसे हो गई और ऋण वसूली की कार्रवाई नहीं हुई, तो उसे एनपीए खाते में क्यों नहीं डाला गया? इस सवाल पर बब्बर को अचानक मीटिंग की याद आ गई. बोले, मैं ज़रूरी मीटिंग में हूं, अभी बात नहीं कर पाऊंगा. और उन्होंने फोन काट दिया. अब तो बब्बर की तरक्की हो चुकी है और उनका तबादला भी हो चुका है. अर्से बाद जब बैंक प्रबंधन के अधिकारियों को अपना गला फंसता हुआ दिखा, तब उस ऋण की वसूली के लिए बैंक प्रबंधन ने ट्रिब्यूनल की शरण ली है.

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी ही करतूतों के कारण उत्तर प्रदेश का एक बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान करोड़ों रुपये का ऋण लेकर फरार हो गया है. फरारी की वजह ऋण वसूली में बैंक की कोताही रही है. व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से उपकृत होकर बैंक के अधिकारी ऋण जारी करते हैं और जब उनकी नौकरी ख़तरे में पड़ती है, तब वे बकाया वसूली के लिए सक्रिय होते हैं. आगरा की वरुण इंडस्ट्रीज के साथ यही हुआ. आख़िरकार आगरा पुलिस को देश के बड़े स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्टर वरुण इंडस्ट्रीज के दो प्रमोटरों और एक डायरेक्टर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करना पड़ा. वरुण इंडस्ट्रीज के प्रमोटर किरण मेहता, कैलाश अग्रवाल और डायरेक्टर वरुण मेहता के ख़िलाफ़ आगरा के सीजेएम कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी है. वरुण इंडस्ट्रीज ने एसई इंवेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी से 70 करोड़ रुपये का ऋण तो लिया ही था. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया समेत 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर दो हज़ार करोड़ रुपये का ऋण ले रखा था. इन बैंकों के कंसोर्सियम ने भी वसूली के लिए वरुण इंडस्ट्रीज के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है. बैंकों के कंसोर्सियम में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं. लेकिन, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उन बैंकों के आला अफसरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, जो विभिन्न तरीकों से प्रभावित होकर ऋण की रेवड़ियां बांटते हैं और फंसने पर ट्रिब्यूनल के समक्ष आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में आ जाते हैं. देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बांटे गए रद्दी ऋण के कारण 10 खरब 44 अरब रुपये का बकाया हो गया है. डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के पास ये मामले वसूली के लिए लंबित हैं. आप समझ ही सकते हैं कि इतनी विशाल धनराशि की वसूली में कितना विशाल समय लगेगा और फिर भी वसूली हो पाएगी, इसमें संदेह ही है.

बहरहाल, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जिन 27 आला अफसरों के ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी हुई है, उनमें पूर्व सीएमडी अर्चना भार्गव या मौजूदा एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग का नाम शामिल नहीं है. चार्जशीट जारी किए जाने में भी बैंक प्रबंधन ने दोगला रवैया अख्तियार किया. कुछ आला अफसरों को तरक्की देकर उनका तबादला कर दिया गया, तो कुछ अफसरों को बलि का बकरा बनाकर हलाल कर दिया गया. लखनऊ के पास के ज़िले में अपना पेट्रोल पंप चलाने वाले बैंक अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. बैंक से पांच लाख रुपये निकाल कर बनारसी साड़ी खरीद कर दिल्ली में प्रमुख महिला हस्ती को भेंट करने वाले अफसर विनोद बब्बर को तरक्की देकर हुगली भेज दिया गया. इससे यह सवाल अधूरा ही रह गया कि पांच लाख रुपये की साड़ियां आख़िर किस हस्ती को भेंट की गईं? इस पर बैंक प्रबंधन भी चुप्पी साधे है. 50 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राजेश एक्सपोर्ट्स से 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने की ऑडियो-सीडी बैंक प्रबंधन को दिए जाने के बावजूद अर्चना भार्गव के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान लैंको को वक्फ की ज़मीन पर करोड़ों रुपये का ऋण देने वाले तत्कालीन सीएमडी मधुकर रहे हों या किंग फिशर के लिए विजय माल्या को करोड़ों का ऋण देने वाले विनोद नारंग, बैंक प्रबंधन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता. जबकि ऐसी अंधेरगर्दियों से बैंक को अरबों रुपये का नुक़सान हुआ है. इसी तरह कोलकाता की एक कथित एविएशन कंपनी को ऋण देकर बैंक ने अपने सैकड़ों करोड़ रुपये डुबो दिए हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन इस पर चुप्पी साधे है. उक्त एविएशन कंपनी को तीन हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सौ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दे दिया. जबकि उस एविएशन कंपनी का ज़मीन पर कोई अता-पता नहीं है. इस तरह सैकड़ों करोड़ रुपये डूब जाने के बावजूद बैंक प्रबंधन ने दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है. किंग फिशर की तरह स्पाइस जेट एविएशन कंपनी के डूबने की आशंका गहराती जा रही है. स्पाइस जेट भी डूबी, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया तक़रीबन पांच सौ करोड़ रुपये का ऋण भी डूब जाएगा. इस संवाददाता ने बैंक द्वारा दिए गए अराजक ऋण से संबद्ध कुछ लिखित सवाल बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग से पूछे, लेकिन उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ एक का शेष

...ईडी कुछ जानते ही नहीं

बैंक के कर्ता-धर्ता होते हुए नारंग ने किंग फिशर को अनाप-शनाप ऋण दिए और सुनियोजित तरीके से किंग फिशर के मालिक विजय माल्या ने कर्ज के रुपये बैंक को नहीं लौटाए. लैंको या कई अन्य फर्मों को दिए गए ऋण के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनमें सरकारी ज़मीनों को भी गिरवी रखकर करोड़ों रुपये के ऋण हासिल कर लिए गए और बैंक उन ऋणों की वसूली नहीं कर पाया. इस तरह के ऋणों की रेवड़ियां बांटने में बैंक के अधिकारी खुद ही लिप्त रहते हैं और बाद में वे सुनियोजित रूप से ऋण लेकर भागने वाली फर्मों को दिवालिया, डिफॉल्टर या फरार घोषित कर देते हैं. इससे बैंक अधिकारियों की खुद की नौकरी बची रहती है और सारा नुक़सान बैंक को झेलना पड़ता है. ऐसी मिलीभगत के चलते अभी कुछ ही अर्सा पहले दिल्ली में भी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का आठ सौ करोड़ रुपये का ऋण घोटाला उजागर हो चुका है. डूबे हुए या डुबाए गए कर्जों की वजह से बैंक का अस्तित्व ख़तरे में पड़ा और इससे बचने के लिए बैंक की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अर्चना भार्गव इस्तीफ़ा देकर चलती बनीं. दिल्ली ऋण घोटाले में भी वही तौर-तरीका अख्तियार किया गया था, जो लखनऊ या कोलकाता में अपनाया गया था. दिल्ली में तक़रीबन डेढ़ सौ अकाउंट्स को 800 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट मंजूर की गई और खाताधारकों के माल की जांच किए बगैर उनके बिल को डिस्काउंट किया गया. दिल्ली की एक ही ब्रांच में इन खातों पर लगभग 300 करोड़ रुपये का ऋण बकाया पाया गया. इस तरह आठ सौ करोड़ रुपये के ऋण फर्मों की वित्तीय सच्चाई जांचे बगैर बांट दिए गए. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किंग फिशर एयरलाइंस के विजय माल्या एवं तीन अन्य निदेशकों को ऋण लेकर जान-बूझकर फरार घोषित करने वाला पहला बैंक है. वह इसलिए, क्योंकि किंग फिशर एयरलाइंस को दिया गया करोड़ों रुपये का ऋण खुद में एक घोटाला है, जिसकी निष्पक्षता से जांच हो जाए, तो शायद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बंद हो जाएगा. पश्चिम बंगाल के सारधा चिटफंड घोटाले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम आ रहा है. सारधा कंपनी को बैंक ने करोड़ों रुपये का ऋण दे रखा है. जिस एविएशन कंपनी को हेलिकॉप्टर के लिए बैंक द्वारा ऋण दिए जाने की बात सामने आ रही है, उसके भी सारधा चिटफंड मामले से लिंक हैं. यह भी बताया जा रहा है कि उसी एविएशन कंपनी के विमान चुनाव प्रचार अभियान में ममता बनर्जी के काम आते रहे हैं. वैसे, एलकेमिस्ट नामक कंपनी के चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल करने में ममता बनर्जी का नाम सामने आ चुका है. सारधा चिटफंड मामले से एलकेमिस्ट के भी जुड़े होने की ख़बरें हैं. एलकेमिस्ट कंपनी के मालिक केडी सिंह हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं. एलकेमिस्ट कंपनी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेकर फरार हुई एविएशन कंपनी के बीच कोई सूत्र जुड़ते हैं कि नहीं, यह पता लगाना तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी का काम है. बहरहाल, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित शाखा में रात के ढाई बजे सारधा चिटफंड कंपनी के मालिक के 13 लॉकर किसके आदेश पर खुलवाए गए थे, यह रहस्य आज तक बना हुआ है. हालांकि, जो लोग जानकारियां रखते हैं, उन्हें देर रात को लॉकर खोले जाने का रहस्य पता है... ■

कई और भी धंधे हैं इस राह में...

सहारा समूह की कंपनी सहारा फाइनेंस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिये कॉल मनी और नोटिस मनी का धंधा भी करती रही है. कॉल मनी के धंधे से हज़ारों करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन एक ही दिन में हो जाता है. कॉल मनी के धंधे की प्रक्रिया जानते चलें. मुद्रा बाज़ार मुख्यत: बैंक और प्राथमिक डीलर (पीडीएस) जैसी संस्थाओं के बीच धन उधार देने और उधार लेने की प्रक्रिया को सुलभ बनाता है. बैंक और पीडीएस अपनी निधियों की स्थिति के असंतुलन को दूर करने के लिए रात भर के लिए अथवा अल्प अवधि के लिए उधार लेते और देते हैं. यह उधार लेना और देना ग़ैर-प्रतिभूत आधार पर होता है. एक दिन के लिए निधियां उधार लेने अथवा देने को कॉल मनी कहा जाता है. जब दो दिन से 14 दिन के बीच की अवधि के लिए धन उधार लिया अथवा दिया जाता है, तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है. 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए निधियां उधार लेने या देने को टर्म मनी कहा जाता है. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिये सहारा फाइनेंस कॉल मनी का बड़ा धंधा करता रहा है. यूबीआई सूत्रों का ही कहना है कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के बहनोई अशोक रॉय चौधरी यूबीआई के कर्मचारी रहे हैं, इसलिए सहारा से बैंक की काफी नज़दीकियां हैं. ऋण घोटाले में खुद को फंसता देखकर स्वैच्छिक अवकाश लेकर परिदृश्य से गुम हो जाने वाली यूबीआई की चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक अर्चना भार्गव के भी सहारा प्रबंधन से मधुर रिश्ते रहे हैं. इस नज़दीकी रिश्ते के कारण ही यूबीआई के शीर्ष अधिकारी भी अपने बायोडाटा में सहारा के लिए काम करने का विशेष जिक्र करते हैं. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 44

दिल्ली, 05 जनवरी-11 जनवरी 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक

संतोष भारतीय

संपादक समन्वय

डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक

सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

जेसीए का बेजा इस्तेमाल

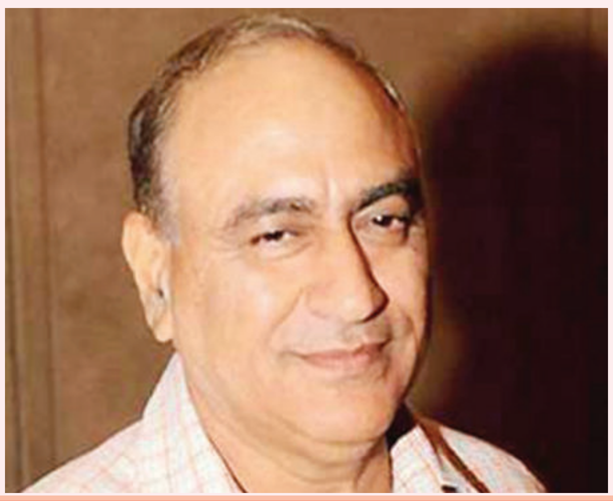

एजीएमयूटी कैडर के बाबुओं का स्थानांतरण हमेशा से केंद्रीय गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. मंत्रालय अब एक समाधान के साथ आगे आया है, जिस पर राज्यों की भी सहमति है. इसके तहत एक संयुक्त कैडर अथॉरिटी (जेसीए) होगी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, इन राज्यों के मुख्य सचिव और प्रशासक शामिल होंगे. यह अथॉरिटी ही संवर्ग के भीतर सभी तबादले और तैनातियां तय करेगी. वैसे नई योजना को लेकर, सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी को महसूस हो रहा है कि योग्य लोगों की क़ीमत पर अपने बाबुओं को पुरस्कृत करने के लिए कुछ शक्तिशाली मुख्य सचिवों द्वारा जेसीए का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तंत्र का उद्देश्य यह नहीं था. यह एक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में उभर रहा है. अब मुख्य सचिवों की ताकत कम करना एक कठिन काम है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जल्द ही कुछ करना पड़ेगा. ■

मुख्य सचिव की खोज

उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक हरियाणा को एक नया मुख्य सचिव मिल जाए, शायद 1982 बैच से. वर्तमान मुख्य सचिव पीके गुप्ता का कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा हो गया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए दुविधा यह है कि वह राज्य की प्रभावशाली बिल्डर लॉबी के दबाव का विरोध कैसे करें. सूत्रों का कहना है कि खट्टर मुख्य धारा के राजनेता की बजाय एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं. बिजनेस लॉबी सरकार में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए आरएसएस रूट से कोशिश कर रही है. अब उसके प्रयासों का विरोध कैसे होता है, यह खट्टर पर निर्भर करता है. पर्यवेक्षकों के मुताबिक, चूंकि गुप्ता 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, इसलिए उनके साथी अशोक लवासा, मधुसूदन प्रसाद और संजय कोठारी इस दौड़ से बाहर हैं. अब 1982 बैच के तीन अधिकारियों के लिए मैदान खुला हुआ है. ये हैं, डीएस धेसी, केके जालान और डॉ. दलीप सिंह. लेकिन, इन सबके बीच कोई और नाम भी उभर कर सामने आ सकता है. ■

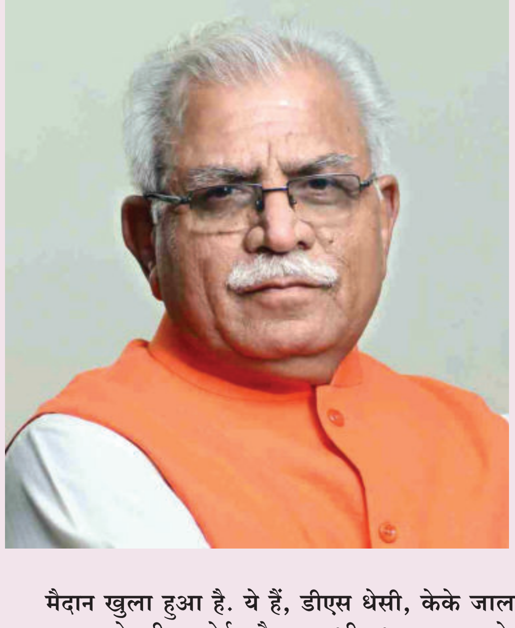

नए प्रमुखों की नियुक्ति

वर्ष के अंत तक खुफिया और सुरक्षा संगठनों में शीर्ष स्तर की नियुक्तियों से लगता है कि मोदी सरकार अपने चुने हुए लोगों के साथ 2015 में प्रवेश करेगी. इसमें निदेशक-आईबी के रूप में सक्षम दिनेश्वर शर्मा का नाम सबसे प्रमुख है. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ की खोज राजिंदर खन्ना के नाम साथ ख़त्म हुई. वहीं रवींद्र सक्सेना को रॉ से ही संबंधित संस्था विमानन अनुसंधान केंद्र का मुखिया बनाया गया है. निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद सरकार ने एक आईपीएस या आईएएस की जगह रॉ सेवा के अंदर से ही किसी अधिकारी को रॉ प्रमुख चुना है, जो एक स्टेट कैडर से है. इस समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का मुखिया बनना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी इस अर्द्धसैनिक बल की माओवादी विद्रोहियों के साथ लड़ाई जारी है. ऐसे में ओडिशा कैडर एवं 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रकाश मिश्रा को इसका मुखिया बनाया गया है. ■

dilipcherian@gmail..com

लद्दाख में भी भाजपा को निराशा का सामना करना पड़ा. वहां की कुल चार सीटों में से तीन सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. दूसरी ओर जम्मू क्षेत्र में भाजपा को जो भी सीटें मिलीं, वे वहां कांग्रेस की गिरती हुई साख के कारण मिलीं. भाजपा को अनुमान था कि वह जम्मू की सभी 37 सीटें, लद्दाख की चार और घाटी की तीन सीटें जीतकर अपना मिशन-44 पूरा करने में कामयाब हो जाएगी और इस तरह जम्मू-कश्मीर में पहली बार अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन उसका अनुमान ग़लत साबित हुआ. उसे न तो जम्मू की सभी सीटें मिलीं.

झारखंड

मोदी लहर का जादू

मंगलानंद

झारखंड में मोदी लहर ने जमकर काम किया. नतीजतन, भाजपा को सबसे अधिक सीटें मिलीं. लोकसभा चुनाव के दौरान जितनी विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी, उसे वह इस विधानसभा चुनाव के दौरान जीत में तब्दील नहीं कर सकी. लोकसभा चुनाव में भाजपा को 56 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, जो विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर आकर ठहर गई. झामुमो ने लोकसभा चुनाव में नौ विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी, जो विधानसभा चुनाव में बढ़कर 19 हो गई. इसी तरह कांग्रेस ने तीन की जगह दोगुनी सीटें हासिल कीं. इसके साथ ही संपूर्ण विकास और पूर्ण बहुमत के नारे ने भी काम किया. जनता गठबंधन से त्रस्त थी, इसलिए अधिकतर सीटें भाजपा को मिलीं. जनता विकास के लिए तरस रही है, इसलिए इस बार चुनाव से पहले ही भाजपा की सरकार तय मानी जा रही थी. केंद्र में भाजपा की सरकार ने असर दिखाया. मोदी और अमित शाह के आक्रामक प्रचार ने भाजपा को अधिक सीटें दिलाने में मदद की. अधिकतर युवाओं ने भाजपा को वोट दिया. युवाओं ने तय किया कि छोटे मुद्दों से परे हटकर संपूर्ण विकास की बात होनी चाहिए. भाजपा ने यहां विकास का ही नारा दिया था, क्योंकि बिहार से अलग होने के बाद से झारखंड पिछड़ा हुआ है. राज्य की विकास दर 7 से 8 फ़ीसद है, लेकिन योजना आयोग के मुताबिक, देश के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ़ 1.72 फ़ीसद है. क़रीब 35 लाख परिवार ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं. जबकि छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड भी प्राकृतिक संसाधनों के मामले में खासा समृद्ध है.

14 वर्षों के इतिहास में झारखंड में कभी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं रही. इस दौरान राज्य को नौ मुख्यमंत्री मिले और तीन बार राष्ट्रपति शासन रहा. निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा तक मुख्यमंत्री बने. क़रीब साढ़े नौ वर्षों तक भाजपा के ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दूसरे दलों के समर्थन से. भाजपा ने इस बार स्थिर सरकार का नारा दिया था. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें जीत लीं. 56 विधानसभा क्षेत्रों में उसे बढ़त मिली. विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के साथ गठबंधन किया था. आजसू ने पिछली बार पांच सीटें जीती थीं. भाजपा ने इस बार उसे आठ सीटें लड़ने के लिए दीं. बदले में आजसू ने भाजपा उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे. इससे पिछड़े वर्गों के वोट नहीं कटे. सभी दलों के लिए सबक यही है कि वे विकास के नारे पर ही चुनाव जीत सकते हैं. नई सरकार को अब राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में व्याप्त बदइंतजामी ख़त्म करनी होगी, रोज़गार के अवसर पैदा करने होंगे, क्योंकि राज्य की क़रीब आधी आबादी ग़रीब है. झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ़ राज्य के गठन का श्रेय लेता रहा. उसने भ्रष्टाचार कम करने और राज्य को संवारने के बारे में नहीं सोचा. झामुमो ने पिछले पांच साल भाजपा और कांग्रेस दोनों के समर्थन से सरकार चलाई. इस वजह से अपना रुख साफ़ नहीं कर पाई कि वह आख़िर किस विचारधारा के साथ है. जेवीएम से गठबंधन की चर्चा हुई, लेकिन पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने सीधे मना कर दिया था. इसलिए भाजपा के पास केवल एक विकल्प आजसू था.

हेमंत सोरेन ने 14 माह बनाम 14 साल का नारा दिया था, लेकिन उसकी हवा निकल गई. हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ा झटका दुमका में उनकी पराजय रही. दुमका झामुमो का परंपरागत गढ़ रहा है, जहां भाजपा की डॉ. लुईस मरांडी के हाथों हेमंत सोरेन को हार का सामना करना पड़ा. भाजपा से समर्थन वापस लेकर अपनी सरकार बनाने में सफल हुए हेमंत सोरेन चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए. विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटों के लिहाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ. ग़ौरतलब है कि हेमंत ने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज़्यादा वक्त दुमका और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिया था. हेमंत को उम्मीद थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समेत अन्य दलों का साथ मिलेगा, जो सरकार बनाने में मददगार थे. कांग्रेस के इंकार से यह भ्रम टूट गया और झामुमो का परंपरागत किला संथाल परगना भी हेमंत सोरेन बचा नहीं सके. यहां पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए, जबकि भाजपा ने आश्चर्यजनक रूप से जीत हासिल की. ■

चौंकाने वाले नतीजे

- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका से हारे.
- आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली से हारे.
- राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवर और गिरिडीह से हारे.
- पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावा से हारे.
- पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंझगांव से हारे.
- स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह बेरमो से हारे.
- कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से हारीं.
- शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव सिसई से हारीं.
- मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से जीतीं.

कौन कहां से जीता

दुमका- डॉ. लुईस मरांडी-भाजपा
गिरिडीह- निर्भय शाहाबादी-भाजपा
खरसावां- दशरथ गागराई-झामुमो
रांची- सीपी सिंह-भाजपा
सिल्ली- अमित महतो-झामुमो
हज़ारीबाग- मनीष जायसवाल-भाजपा
बाघमारा- ढुलू महतो-भाजपा
बगोदर- नागेंद्र महतो-भाजपा
बहरागोड़ा- कुणाल षाडंगी-झामुमो
बरहेट- हेमंत सोरेन-झामुमो
बरही- मनोज यादव-कांग्रेस
बड़कागांव- निर्मला देवी-कांग्रेस
बरकट्ठा- जानकी यादव-जेवीएम
बेरमो- योगेश्वर महतो-भाजपा
भवनाथपुर- भानु प्रताप शाही-नवजवान संघर्ष मोर्चा
विश्रामपुर- रामचंद्र चंद्रवंशी-भाजपा
विशुनपुर- चमरा लिंडा-झामुमो
बोकारो- विरंची नारायण-भाजपा
बोरिया- ताला मरांडी-भाजपा
चाईबासा- दीपक बिरुआ-झामुमो

चक्रधरपुर- शशिभूषण सामाड़-झामुमो
चंदनकियारी- अमर बाउरी-झाविमो
चतरा- जयप्रकाश सिंह-भाजपा
छतरपुर- राधाकृष्ण किशोर-भाजपा
डाल्टनगंज- आलोक चौरसिया
देवघर- नारायण दास-भाजपा
धनबाद- राज सिन्हा-भाजपा
धनवार- राजकुमार यादव-कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट-लिबरेशन)
डुमरी- जगन्नाथ महतो-झामुमो
गाडेय- जयप्रकाश वर्मा-भाजपा
गढ़वा- सत्येंद्र तिवारी-भाजपा
घाटशिला- लक्ष्मण टुडू-भाजपा
गोड्डा- रघुनंदन मंडल-भाजपा
गोमिया- योगेंद्र प्रसाद-झामुमो
गुमला- शिवशंकर उरांव-भाजपा
हटिया- नवीन जायसवाल-झाविमो
हुसैनाबाद- शिवपूजन मेहता-बसपा
इचागढ़- साधु चरण महतो-भाजपा

जगन्नाथपुर- गीता कोड़ा-जय भारत समानता पार्टी
जामा- सीता मुर्मू उर्फ सीता सोरेन-झामुमो
जमशेदपुर पूर्वी- रघुवर दास-भाजपा
जमशेदपुर पश्चिमी- सरयू राय-भाजपा
जामताड़ा- डॉ. इरफान अंसारी-कांग्रेस
जमुआ- केदार हाजरा-भाजपा
जरमुंडी- बादल-कांग्रेस
झरिया- संजीव सिंह-भाजपा
जुगसलाई- रामचंद्र सहिस-आजसू
कांके- डॉ. जीतू चरण राम-भाजपा
खिजरी- रामकुमार पाहन-भाजपा
खूंटी- नीलकंठ सिंह मुंडा-भाजपा
कोडरमा- नीरा यादव-भाजपा
कोलेबिरा- एनोस एक्का-झारखंड पार्टी
लातेहार- प्रकाश राम-झाविमो
लिट्टीपाड़ा- डॉ. अनिल मुर्मू-झामुमो
लोहरदगा- कमल किशोर भगत-आजसू
मधुपुर- राज पलिवार-भाजपा
महागामा- अशोक कुमार-भाजपा
महेशपुर- स्टीफन मरांडी-झामुमो
मझगांव- निरल पूर्ति-झामुमो

मांडर- गंगोत्री कुजूर-भाजपा
मांडू- जयप्रकाश पटेल-झामुमो
मनिका- हरिकृष्ण सिंह-भाजपा
मनोहरपुर- जोबा मांझी-झामुमो
नाला- रवींद्र नाथ महतो-झामुमो
निरसा- अरूप चटर्जी-मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन
पाकुड़- आलमगीर आलम-कांग्रेस
पांकी- विदेश सिंह-कांग्रेस
पोड़ैयाहाट- प्रदीप यादव-झाविमो
पोटका- मेनका सरदार-भाजपा
राजमहल- अनंत ओझा-भाजपा
रामगढ़- चंद्रप्रकाश चौधरी-आजसू
सरायकेला- चंपई सोरेन-झामुमो
सारठ- रणधीर कुमार सिंह-झाविमो
शिकारी पाड़ा -नलिन सोरेन-झामुमो
सिमरिया- गणेश गंझु-झाविमो (प्रजातांत्रिक)
सिमडेगा- विमला प्रधान-भाजपा
सिंदरी- फूलचंद मंडल-भाजपा
सिसई- दिनेश उरांव-भाजपा
तमाड़- विकास मुंडा-आजसू
तोरपा- पौलुस सुरीन-झामुमो
टुंडी- राजकिशोर महतो-आजसू

जम्मू-कश्मीर

जनता के फ़ैसले से सब हैरान

डॉ. क़मर तबरेज़

जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम बीते 23 दिसंबर को सामने आए. जनता के फ़ैसले ने सभी राजनीतिक दलों को परेशान कर दिया. राज्य में किसी भी पार्टी को जनता ने इतनी सीटें नहीं दीं, जिससे वह आसानी से सरकार का गठन कर सके. 87 सदस्यीय राज्य विधानसभा में पीडीपी को जहां सबसे अधिक 28 सीटें मिलीं, वहीं भाजपा को 25, नेशनल कांफ्रेंस को 15 और कांग्रेस को केवल 12 सीटें मिल सकीं, शेष सात सीटें अन्य के खाते में गई हैं. 2008 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस को 28 सीटें मिली थीं, जबकि पीडीपी को 21, कांग्रेस को 17 और भाजपा को 11 सीटें मिली थीं. इस बार जहां मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) 28 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भले ही अपनी उम्मीदों के अनुरूप मिशन-44 का लक्ष्य हासिल कर पाने में असफल रही हो, लेकिन उसकी सीटें 11 से बढ़कर 25 ज़रूर हुई हैं. इसी तरह 15 सीटों के साथ नेशनल कांफ्रेंस तीसरे और 12 सीटों के साथ कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच गई. हैरानी की बात तो यह है कि उमर अब्दुल्लाह, जो पिछले 6 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सोनावार सीट से चुनाव हार गए. इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि श्रीनगर के अमीराकदल और हब्बाकदल से उसके उम्मीदवारों का जीतना तय है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में कश्मीरी पंडितों की बड़ी आबादी रहती है. लेकिन, अमीराकदल से डॉक्टर हिना भट्ट और हब्बाकदल से मोती कौल के हार जाने से पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया. यही नहीं, श्रीनगर की हब्बाकदल सीट को छोड़कर भाजपा ने घाटी की जिन 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उन सबकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई. घाटी में भाजपा को केवल 3 प्रतिशत वोट मिले.

लद्दाख में भी भाजपा को निराशा का सामना करना पड़ा. वहां की कुल चार सीटों में से तीन सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. दूसरी ओर जम्मू क्षेत्र में भाजपा को जो भी सीटें मिलीं, वे वहां कांग्रेस की गिरती हुई साख के कारण मिलीं. भाजपा को अनुमान था कि वह जम्मू की सभी 37 सीटें, लद्दाख की चार और घाटी की तीन सीटें जीतकर अपना मिशन-44 पूरा करने में कामयाब हो जाएगी और इस तरह जम्मू-कश्मीर में पहली बार अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन उसका अनुमान ग़लत साबित हुआ. उसे न तो जम्मू की सभी सीटें मिलीं, बल्कि लद्दाख और कश्मीर में उसका खाता तक नहीं खुला. हालांकि, वोट प्रतिशत की बात करें, तो 23 प्रतिशत वोटों के साथ भाजपा पहले नंबर पर रही, जबकि 22.7 प्रतिशत वोटों के साथ पीडीपी दूसरे नंबर पर, 20.8 प्रतिशत वोटों के साथ नेशनल कांफ्रेंस तीसरे नंबर पर और 18 प्रतिशत वोटों के साथ कांग्रेस चौथे नंबर पर रही. दरअसल, भाजपा को लग रहा था कि अलगाववादियों की ओर से इस बार भी मतदान का बहिष्कार किया जाएगा. लिहाजा, अगर कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में उसे वोट देते हैं, तो उसके उम्मीदवारों का हर जगह जीतना तय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. हैरानी की बात तो यह रही कि खुद कश्मीरी पंडितों ने उतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं डाले, जितनी भाजपा उम्मीद कर रही थी. शायद इसका एक कारण यह भी था कि धारा 370 पर भाजपा के रुख से कश्मीरी पंडित भी कहीं न कहीं उससे नाराज़ थे. दूसरे यह कि पहले की तरह इस बार कट्टर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने चुनाव बहिष्कार का आह्वान नहीं किया था. उन चुनाव क्षेत्रों में कश्मीरियों ने बड़ी संख्या में मतदान किया, जो अतीत में हुर्रियत कांफ्रेंस के प्रभाव वाले माने जाते थे.

अगर पीडीपी की बात करें, तो उसने 28 में से 25 सीटें घाटी में जीतीं, जबकि शेष तीन सीटें उसे जम्मू के राजोरी, पूंछ और दरहाल से मिलीं. जम्मू के ये तीनों क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य हैं. लद्दाख के लोगों ने इस बार भाजपा के साथ-साथ पीडीपी को भी अपना समर्थन नहीं दिया, यहां की चार में से तीन सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली, जबकि एक सीट स्वतंत्र उम्मीदवार के खाते में गई. कांग्रेस को पांच सीटें जम्मू से, चार सीटें घाटी से और तीन सीटें लद्दाख से मिलीं. शायद इसीलिए कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो राज्य के तीनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है. जहां तक नेशनल कांफ्रेंस की बात है, तो उसे 11 सीटें घाटी से और शेष चार सीटें जम्मू से मिलीं. उमर अब्दुल्लाह इस बात से खुश हैं कि मीडिया ने जिस तरह उनकी पार्टी को अपने एग्जिट पोल में पांच से अधिक सीटें नहीं दी थीं, उतनी खराब हालत चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी पार्टी की नहीं हुई. कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस को इतनी सीटें मिलने का एक बड़ा कारण वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का अपने घरों से निकलना रहा. अगर मतदान प्रतिशत में बढ़ोत्तरी न हुई होती, तो शायद इन दोनों ही पार्टियों की हालत आज इतनी अच्छी न होती और पीडीपी के साथ-साथ भाजपा भी सरकार बनाने के नंबर के क़रीब होती.

इस चुनाव की एक दिलचस्प बात यह रही कि 2008 में 87 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में जहां 1,344 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, वहीं इस बार यह संख्या 39 प्रतिशत घटकर केवल 821 रह गई. इस दृष्टि से भी देखा जाए, तो जम्मू-कश्मीर में इस बार विभिन्न उम्मीदवारों के बीच वोटों का विभाजन कम हुआ. दूसरी ओर मतदान प्रतिशत में भी जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई, जिसकी उम्मीद किसी भी राजनीतिक दल को नहीं थी. राज्य में केवल 1987 में औसत मतदान 76 प्रतिशत हुआ था. इसके बाद पहली बार 2014 के विधानसभा चुनाव में औसत मतदान 66 प्रतिशत हुआ. आम तौर पर यह सोचा जा रहा था कि इस बार पूरा कश्मीर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए मतदान केंद्रों तक कम ही लोग पहुंच पाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट. इसका एक कारण यह भी था कि राज्य में खुफिया रूप से जनता को कहीं न कहीं यह संदेश देने की भी कोशिश की गई कि अगर वे वोट नहीं डालेंगे, तो वहां भाजपा की सरकार बन सकती है.

राज्य के चुनाव परिणाम को अगर सामूहिक रूप से देखा जाए, तो वहां पर एक भी ऐसी पार्टी नहीं है, जो राज्य के तीनों हिस्सों यानी जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सके. इसके उलट चुनाव परिणाम यही बता रहे हैं कि भाजपा जम्मू की सबसे बड़ी पार्टी है, पीडीपी कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस लद्दाख की सबसे बड़ी पार्टी है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री जो भी शख्स बनेगा, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह राज्य के इन तीनों हिस्सों के लोगों का विश्वास हासिल कर सके और कह सके कि वह किसी एक हिस्से का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का प्रतिनिधि है. ■

एनडीएफबी-एस अभी भी अरुणाचल प्रदेश और भूटान सीमा के पास अधिक सक्रिय है और पृथक बोडोलैंड की मांग करते रहते हैं. .यहीं से वे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं. असम की हालिया वारदात के पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं है. इस वारदात को केवल लोगों के बीच आतंक और खौफ का माहौल बनाने के लिए अंजाम दिया गया था. यदि पूर्व में असम में हुई इस तरह की घटनाओं पर नज़र डाली जाए तो इससे पहले यहां मुसलमानों और बोडो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक संघर्ष हुए हैं.

धर्मांतरण विवाद

क्या कहता है भारतीय कानून

शफीक आलम

आगरा के तकरीबन 200 लोगों के कथित रूप से राशन कार्ड का लालच देकर कराए गए धर्मांतरण से उठा विवाद अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. कई हिन्दू संगठन यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद यह ऐलान कर चुके हैं कि वे देश के दूसरे इलाकों में भी मुसलमानों और ईसाईयों के लिए घर वापसी का अभियान चलाने वाले हैं. धर्म जागरण समिति ने हर साल एक लाख मुसलमानों और ईसाईयों का धर्मांतरण करने का लक्ष्य रखा है. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने संसद में हंगामा किया और लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न किया. विपक्ष के विरोध के जवाब में भाजपा धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की बात कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस समस्या का एक मात्र समाधान धर्मांतरण विरोधी कानून है. संघ तो बहुत पहले से इस कानून की मांग करता आ रहा है. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या धर्म परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए किसी नए कानून की ज़रूरत है? क्या धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना संवैधानिक है? और धर्म मानने की आज़ादी के प्रश्न पर देश का संविधान और कानून क्या कहते हैं?

जहां तक आगरा प्रकरण का सवाल है तो इसमें लिप्त धर्म जागरण समिति के नेताओं पर आगरा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने) और धारा 415 (धोखाधड़ी से काम लेने) के तहत एफ़आईआर दर्ज कर लिया है. इसलिए ऐसे मामलों के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है. आम तौर पर हिन्दू संगठन ईसाई संगठनों पर यही आरोप लगते हैं कि वे ग़रीब आदिवासियों और दलितों को लालच दे कर और धोखे से उनका धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं.

जहां तक धर्म मानने और अपनाने का सवाल है अपने उद्देशिका (प्रेएम्बले) में ही संविधान अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी देता है. हालांकि धर्म की स्वतंत्रता किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की बुनियादों में से एक है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान ने इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है. संविधान की धारा 25 (1) के मुताबिक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का सामान हक होगा. धर्मांतरण और धर्म मानने की आज़ादी का मामला संविधान सभा में भी उठा था. के एम मुंशी ने अपने वक्तव्य में कहा था की इस धारा 25 में शामिल शब्द प्रचार आर्य समाज को शुद्धिकरण और ईसाईयों, मुसलमानों और दूसरे धर्म के लोगों को अपने-अपने धर्म के प्रचार की आज़ादी देता है. पवन खेड़ा लिखते हैं संसद में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के लिए तीन प्रयास किए गए. वे लिखते हैं कि 1955 में इस तरह के पहले प्रयास में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था इस बिल से ग़लत तरीके से धर्मांतरण को नहीं रोका जा सकता, जबकि इस की वजह से बहुत सारे लोगों का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा. नेहरू ने कहा था डरा धमका कर, लालच दे कर या धोखे दे कर कराए गए धर्मांतरण को आम कानून के जरिये निपटा जा सकता है.

हालांकि मध्यप्रदेश (1968), उड़ीसा (1967), राजस्थान (2006 राष्ट्रपति की सहमति अभी नहीं मिली है), छत्तीसगढ़ (2006) और गुजरात (2003)जैसे राज्यों ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए, लेकिन धर्मांतरण के संवैधानिक औचित्य पर भी अक्सर सवाल खड़े किये जाते हैं. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों अपने फैसले दिए हैं. यह सवाल अक्सर उठता है कि संविधान धर्मांतरण की इजाज़त नहीं देता बल्कि धर्म के प्रचार की इजाजत देता है, और वह भी शर्तों के साथ यानि लोक व्यवस्था और सदाचार बनाए रखते हुए. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 और उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1967 पर एक मामले की सुनवाई करते हुए शब्द प्रचार की व्याख्या इस तरह की थी कि इसका अर्थ अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना न कि किसी दूसरे व्यक्ति का अपने धर्म में धर्मांतरण करना. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कानूनों को संवैधानिक करार दिया था. अब इस फैसले पर सवाल खड़े किये जा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का अपने धर्म के प्रचार में अगर धर्मांतरण के उद्देश्य को हटा दिया जायेगा तो इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जायेगा.

भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, दूसरे धर्म को अपने की पूरी आज़ादी देता है. लेकिन यह आज़ादी किसी को यह अधिकार नहीं देता कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करके अपने धर्म का प्रचार करे. ठीक है अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम है लेकिन आलोचना और अपमान में भेद होना चाहिए वह भी तब जब आलोचना या अपमान करने वाला व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ हो. मिसाल के तौर पर वर्ष 2006 में राजस्थान सरकार ने ईसाई मिशनरीयों द्वारा वितरित की जा रही दो किताबों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. जिसमें से एक किताब का नाम था: वे शर्म से हिन्दू कहते हैं क्यों? इन किताबों को लेकर राजस्थान में उस समय ईसाईयों पर हमले हुए थे. ईसाई मिशनरीयों पर प्रलोभन देकर भी धर्मांतरण कराने का आरोप है. लेकिन प्रलोभन बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि प्रलोभन की बात उस वक़्त बाहर आएगी जब धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति इसकी शिकायत करे, और जब कोई व्यक्ति केवल प्रलोभन की वजह से दूसरे धर्म को अपना रहा है वह इस की शिकायत क्यों करेगा. एायद इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने धर्मांतरण के सवाल पर कहा था कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम इन मामलों (धर्मांतरण) को चाहे जितनी सावधानी से परिभाषित करने की कोशिश करें इनके लिए उचित शब्द नहीं ढूंढ पाएंगे.

जहां तक घर वापसी अभियान का सवाल है तो इस में धर्म से कम और राजनीति से अधिक सरोकार है. यह एक तरह का राजनितिक शक्ति प्रदर्शन है, जिसमें संघ सरकार की हिमायत चाहता है. लेकिन वहीं इस हकीक़त से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि धर्मांतरण के बहुत सारे मामलों में कहीं न कहीं प्रलोभन ज़रूर रहता है. ऐसे में नया कानून बनाने की बजाय जो कानून पहले से मौजूद हैं उन्हें ही कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिए और धर्म को व्यक्तिगत मामला ही रहने देना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

असम नरसंहार

आंतरिक सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत

चौथी दुनिया ब्यूरो

पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य असम के सोनितपुर और कोकराझार जिले में 23 दिसंबर को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सोंगबिजीत धड़े ने आदिवासी समुदाय के 37 लोगों की हत्या कर दी. खबर लिखे जाने तक इस हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 83 तक पहुंच गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग आदिवासी थे. ये लोग चाय के बागानों में काम करते थे. असम में शुरू हुई इस ताजा हिंसा को एनडीएफबी-एस के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है. पुलिस की हालिया कार्रवाई में इस गुट के कई नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे. इसके बाद एनडीएफबी-एस ने धमकी दी थी कि यदि ऐसा होता रहा तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे. इसके बाद उग्रवादी संगठन ने आदिवासी समुदाय के लोगों को मारना शुरू कर दिया. इन लोगों ने बच्चों और औरतों को भी अपना शिकार बनाने से गुरेज नहीं किया. गौरतलब हो कि यह धड़ा शांति वार्ता का विरोध करता रहा है. असम के निर्दोष आदिवासी बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को मारना मानवता के खिलाफ अपराध है. इस घटना को पाकिस्तान के पेशावर में हुई आतंकवादी घटना की तरह देखा जा रहा है. यह घटना पाकिस्तान में हुई आंतकी वारदात जितनी ही खतरनाक है.

सरकार ने इस घटना के बाद एनडीएफबी-एस के खिलाफ और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इन गुटों को आतंकी संगठन करार दिया जाएगा और इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, इनके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी. एनडीएफबी-एस का कृत्य एक आतंकवादी वारदात है. सरकार इस गुट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी. उनके मुताबिक उग्रवादियों के सफाये के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार असम सरकार को हर तरह की मदद करेगी.

इसके बाद सरकार ने इस मामले के की जांच एनआईए को सौंप दी है. सेना ने भी उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑलआउट शुरू कर दिया है. सेना के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन की शुरुआत फुलबरी से की गई है. सुरक्षा बलों के निशाने पर एनडीएफबी-एस के 74 उग्रवादी हैं जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया है. सेना के ऑपरेशन की जानकारी पड़ोसी देशों म्यांमार और चीन को भी दी गई है. केंद्र सरकार

वर्तमान में असम में बोडो लोगों की एक स्वायत्त परिषद है. जिसे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट चलाती है. लेकिन प्रवासियों के वहां जमीन लेने पर बोडो लोगों के बीच खासा असंतोष है. लोग चाहते हैं कि जिस ज़मीन पर आदिवासी हैं वे वहां से हट जायें. वर्तमान विवाद का यह भी कारण हो सकता है.

एनडीएफबी-एस के खिलाफ कार्रवाई के लिए भूटान से भी मदद लेने पर विचार कर रही है, जिससे कि युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की तरह का अभियान चलाया जा सके.

इस तरह के गुटों से निपटना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा से लगे हल्की गश्त किये जाने वाले इलाकों के जंगलों में डेरा डालकर रहते हैं. साल 2003 तक असम में तीन प्रमुख उग्रवादी संगठन एनडीएफबी, युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और कामतापुर लिब्रेशन ऑर्गनाइजेशन थे, जो इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे और यहां रहकर ही अपनी गतिविधियां चलाते थे. लेकिन साल 2003 में ही भूटानी सेना ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें तबाह कर उस क्षेत्र से खदेड़ दिया. इसके बाद यह खबर आई कि ये संगठन घने जंगल और कम आबादी वाले क्षेत्रों में चले गये हैं.

एनडीएफबी-एस अभी भी अरुणाचल प्रदेश और भूटान सीमा के पास अधिक सक्रिय है और पृथक बोडोलैंड की मांग करते रहते हैं. .यहीं से वे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं. असम की हालिया वारदात के पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं है. इस वारदात को केवल लोगों के बीच आतंक और खौफ का माहौल बनाने के लिए अंजाम दिया गया था. यदि पूर्व में असम में हुई इस तरह की घटनाओं पर नज़र डाली जाए तो इससे पहले यहां मुसलमानों और बोडो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक संघर्ष हुए हैं. आदिवासियों और बोडो लोगों के बीच संघर्ष की बहुत कम घटनायें हैं. 20 साल पहले बोडो इलाके में इस तरह की वारदातें हुई थीं. तब मुख्य रूप से संथाल आदिवासियों को निशाना बनाया गया था. उस घटना में हताहत हुए आदिवासी आज भी शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं. यह विवाद अब तक नहीं सुलझ सका है. वर्तमान हिंसक वारदात के बाद इलाके के हजारों लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है. लोग बेघर हो गए हैं.

वर्तमान में असम में बोडो लोगों की एक स्वायत्त परिषद है. जिसे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट चलाती है. लेकिन प्रवासियों के वहां जमीन लेने पर बोडो लोगों के बीच खासा असंतोष है. लोग चाहते हैं कि जिस ज़मीन पर आदिवासी हैं वे वहां से हट जायें. वर्तमान विवाद का यह भी कारण हो सकता है. एक कारण बदले की कार्रवाई भी हो सकती है. निचले असम में आदिवासियों और बोडो लोगों के बीच संघर्ष की खबरें भी आ रही हैं. हाल ही में हुए चुनाव में एक गैर-बोडो उम्मीदवार ने बोडो उम्मीदवार को हरा दिया था क्योंकि सारे गैर बोडो लोग इकट्ठा हो गए थे. यह भी इस विद्रोह की जड़ में मूल कारणों में से एक है. इसके बाद उग्रवादियों को लगने लगा था कि क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई है. असम में जातीय हिंसा का पुराना और खूनी इतिहास है. मोदी सरकार सरकार इस तरह की जातीय हिंसा पर रोक लगाने के लिए गंभीर दिखाई पड़ रही है. यदि शुरूआती दौर में ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाये तो यहां के हालात और गंभीर हो जायेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

महा-गठबंधन को लेकर कुछ सवाल भी खड़े किये जा रहे हैं. मसलन, क्या यह अवसरवादी गठबंधन है, इसका नेतृत्व जो कोई भी करे, क्या वह सबको स्वीकार्य होगा? मसलन, क्या बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार की लीडरशीप मानेंगे आदि. एक सवाल यह भी कि जब 1977 में इस तरह का प्रयोग सफल नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि इस बार यह प्रयोग सफल होगा? 1977 में जनता पार्टी, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, 1996 में एचडी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की सरकारें बनी और गिरी. कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी.

जनता परिवार

सशक्त विपक्ष मजबूत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है

फोटो-प्रभात पाण्डेय

जनता परिवार की भूमिका भी तभी सार्थक मानी जायेगी जब वह एक मजबूत विपक्ष के रूप में संसद से सड़क तक सक्रियता से काम करेगा. जनता परिवार को बदलते राजनीतिक माहौल में खुद को भी ढालने की जरूरत होगी. नई पीढ़ी को साथ लाने के लिए उसे नई पीढ़ी के लोगों की आकांक्षाओं को समझना होगा. पुराने फॉर्मूले के साथ-साथ इसे नये जमाने की आहट को भी सुनना-समझना होगा. तभी ये जनता का विश्वास जीतने में सफल होंगे. जनता परिवार को एक पार्टी, एक झंडे और एक निशान के साथ खुद को जनता के सामने भाजपा के मुकाबले मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना होगा

शशि शेखर

क्रिकेट, राजनीति और भारत के मौसम के बारे में एक चीज सामान्य है. आप इन तीनों के बारे में कोई सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकते. क्रिकेट में अंतिम गेंद फेंके जाने तक जीत-हार का फैसला आप नहीं कर सकते. भारत के मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने में मौसम विज्ञानी भी फेल हो जाते हैं, रही बात राजनीति की तो चुका हुआ तीर भी कुछ समय बाद तुरुप का इक्का बनकर सामने आ जाता है. इस तरह के कई उदाहरणों से भारतीय राजनीति का इतिहास भरा पड़ा है. इन बातों का उल्लेख करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे ही बात जनता परिवार की आती है तो सबसे पहले इसमें शामिल दलों के लिए ये लोग चूके हुए तीर हैं जैसे जुमले का इस्तेमाल किया जाता है. अब भला इनसे क्या निशाना लगेगा. बदलते सामाजिक-राजनीतिक मुहावरे और खास कर युवा भारत की आकांक्षाओं को देखा जाये तो इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज भी नहीं किये जा सकते हैं. लेकिन, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसदीय राजनीति में सत्ता पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता देश को नहीं है? देश को सही ढंग से चलाने के लिए जितनी आवश्यकता एक मजबूत सरकार की है ठीक उतनी ही आवश्यकता एक मजबूत विपक्ष की भी है. इस वक्त संसद में विपक्ष बिखरा हुआ है. सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस हतोत्साहित है. उसके 44 सांसद हैं. याद करने वाली बात यह है कि जब नेहरू सत्ता में थे तब भी किसी एक विपक्षी पार्टी के पास इतना संख्या बल नहीं होता था कि उसे लीडर अपोजीशन यानी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके. लेकिन उस दौर में भी विपक्ष में ऐसे लोग मौजूद थे जो अपने तर्कों और आंकड़ों के आधार पर सरकार को को घेर लेते थे. आज कांग्रेस के पास न वैसा कोई नेता है और न ही कांग्रेस ऐसा उत्साह भी प्रदर्शित नहीं कर रही है जिससे लगे कि वह संसद के भीतर और बाहर सरकार के गलत निर्णयों की आलोचना कर सके, उसका विरोध कर सके.

ऐसे में यदि मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एचडी देवेगौड़ा जैसे नेता एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अब इस पहल का अंजाम क्या होगा, यह प्रयोग कितना सफल होगा, यह तो बाद की बात है,यदि इस तरह की कोई पहल हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? ये सभी नेता मिलकर अगर एक पार्टी और एक निशान के साथ एक झंडे के तले आना चाहते हैं तो इसमें किसका नुक़सान है? दरअसल, जनता परिवार से जुड़े छह दल समाजवादी पार्टी (एसपी), समाजवादी जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल(इनेलो), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल (युनाइटेड)और जनता दल (सेकुलर) बिखरे हुये जनता परिवार को एकबार फिर से एक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. तकरीबन बीस साल बाद लालू यादव और नीतीश कुमार फिर से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं. मुलायम सिंह के घर पर हुई दो बैठकों के बाद इनलोगों ने 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महाधरना किया. संख्या के लिहाज से यह सफल रहा क्योंकि इस धरना में सपा के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे. मंच पर जनता परिवार के तकरीबन सभी बड़े नेता उपस्थित थे. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के हालात ऐसे हो गये हैं जिसकी वजह से जनता परिवार के सभी दलों के एकजुट होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को उसके वादों की याद दिलाई और कहा कि अब तक लोगों के खातों में कालाधन के हिस्से का पंद्रह लाख रुपये नहीं पहुंचे हैं? नीतीश कुमार ने तो बकायदा आडियो क्लिप सुनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि भाजपा सत्ता में आते ही उन वादों को भूल गई है जो उसने जनता से चुनाव प्रचार के दौरान किये थे. लालू प्रसाद यादव अपनी शैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते नज़र आये और कहा कि मैंने अपने बेटे तेजस्वी यादव से कहा कि बाबा रामदेव को ट्वीट करो और बताओ कि मोदी जी का हिसाब गड़बड़ हो गया है. काले धन पर बाबा कुछ कह रहे थे और अब सरकार कुछ और कह रही है. नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया. इनके मुताबिक जनता ने नरेंद्र मोदी के वादों पर पूरा विश्वास किया था. लेकिन, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने, काला धन वापस लाने, सबका विकास करने और सुशासन देने जैसे नारों के साथ सत्ता में आई भाजपा जनता से जुड़े कई मुद्दों पर अब तक ठोस पहल नहीं कर सकी है. महाधरना में इस बात की भी घोषणा की गई कि जनता परिवार से जुड़ी सभी पार्टियों का विलय समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में हो रहा है.

बहरहाल, ऐसे समय में यह महाधरना अयोजित हुआ जब देश में कुछ संगठन धर्मांतरण और घर वापसी जैसी बहसों को जन्म दे रहे थे, और प्रधानमंत्री इस पर संसद में कुछ नहीं बोल रहे थे. ऐसे में सपा, जदयू, राजद, जद (सेकुलर), इनेलो और सजपा के संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन को एक सकारात्मक राजनीतिक कदम कहा जा सकता है. जनता परिवार से जुड़े नेता यह समझ रहे हैं कि यदि हिंदू वोटर एक होकर बीजेपी की ओर चले जाएंगे तो यह उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरनाक है. इसलिए इनकी कोशिश होगी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वे किसी भी तरह अपने जातीय गणित को फिर से जोड़कर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक दें.

लेकिन इस महा-गठबंधन को लेकर कुछ सवाल भी खड़े किये जा रहे हैं. मसलन, क्या यह अवसरवादी गठबंधन है, इसका नेतृत्व जो कोई भी करे, क्या वह सबको स्वीकार्य होगा? मसलन, क्या बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार की लीडरशीप मानेंगे आदि. एक सवाल यह भी कि जब 1977 में इस तरह का प्रयोग सफल नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि इस बार यह प्रयोग सफल होगा? 1977 में जनता पार्टी, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, 1996 में एचडी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की सरकारें बनी और गिरी. कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी. इस वजह से भी जनता परिवार की विश्सनीयता पर लोग शक करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं.

बहरहाल, 2014 के आम चुनाव में मिले झटके के बाद जनता परिवार के ये नेता सीख लेंगे और आगे उन गल्तियों को दोहराने से बचेंगे जो वे अतीत में कर चुके हैं. जनता परिवार की भूमिका भी तभी सार्थक मानी जायेगी जब वह एक मजबूत विपक्ष के रूप में संसद से सड़क तक सक्रियता से काम करेगा. जनता परिवार को बदलते राजनीतिक माहौल में खुद को भी ढालने की जरूरत होगी. नई पीढ़ी को साथ लाने के लिए उसे नई पीढ़ी के लोगों की आकांक्षाओं को समझना होगा. पुराने फॉर्मूले के साथ-साथ इसे नये जमाने की आहट को भी सुनना-समझना होगा. तभी ये जनता का विश्वास जीतने में सफल होंगे. जनता परिवार को एक पार्टी, एक झंडे और एक निशान के साथ खुद को जनता के सामने भाजपा के मुकाबले मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना होगा. इन्हें महज जातीय राजनीतिक खांचे से आगे निकल कर युवाओं और जन आकांक्षाओं को समझते हुए नई नीतियां और नए कार्यक्रम पेश करने होंगे. इसके साथ जनता परिवार को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अन्य छोटे दलों, यहां तक कि वामदलों से भी सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिए. आज जरूरत है कि समान सोच वाले लोग और सभी बड़ी-छोटी पार्टियां एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ें, ताकि देश को एक मजबूत सरकार के साथ-साथ एक मजबूत विपक्ष भी मिल सके.■

shashishekhar@chauthiduniya.com

जब नेहरू सत्ता में थे तब भी किसी एक विपक्षी पार्टी के पास इतना संख्या बल नहीं होता था कि उसे लीडर अपोजीशन यानी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके. लेकिन उस दौर में भी विपक्ष में ऐसे लोग मौजूद थे जो अपने तर्कों और आंकड़ों के आधार पर सरकार को को घेर लेते थे. आज कांग्रेस के पास न वैसा कोई नेता है और न ही कांग्रेस ऐसा उत्साह भी प्रदर्शित नहीं कर रही है जिससे लगे कि वह संसद के भीतर और बाहर सरकार के गलत निर्णयों की आलोचना कर सके, उसका विरोध कर सके.

इस महा-गठबंधन को लेकर कुछ सवाल भी खड़े किये जा रहे हैं. मसलन, क्या यह अवसरवादी गठबंधन है, इसका नेतृत्व जो कोई भी करे, क्या वह सबको स्वीकार्य होगा? मसलन, क्या बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार की लीडरशीप मानेंगे आदि. एक सवाल यह भी कि जब 1977 में इस तरह का प्रयोग सफल नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि इस बार यह प्रयोग सफल होगा? 1977 में जनता पार्टी, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, 1996 में एचडी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की सरकारें बनी और गिरी. कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी. इस वजह से भी जनता परिवार की विश्सनीयता पर लोग शक करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं.

इस सरकार ने युवाओं, किसानों और आम आदमी के साथ वादाखिलाफी की है. आज यहां भारी संख्या में युवा आये हैं. युवा अगर एक साथ आगे आयें तो कोई सरकार मनमानी नहीं कर सकती. मैं चाहता हूं कि युवा गांव-गांव जाकर सरकार की इस वादाखिलाफी के बारे में लोगों को बतायें.

- मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी.

एक दल बनाने की शुरुआत है यह कार्यक्रम. सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है. जनधन योजना में 8 करोड़ खाते खुले हैं जिसमें से 5 करोड खातों में अब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. अब ये कह रहे है कि जिस खाते में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है उनको दुर्घटना बीमा का लाभ भी नहीं मिलेगा.

- नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार और जद(यू) नेता.

सबका साथ-सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी धर्मांतरण करवा कर किसका और कैसा विकास करना चाहती है. क्या तब तक विकास नहीं होगा जब तक सब के सब हिंदू न बन जाये. सरकार अगर ऐसा करना चाहती है तो फिर से इसी मुद्दे पर चुनाव लड़कर दिखाये.

- शरद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जद(यू)

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अच्छे दिन का प्रलोभन दे कर सरकार बना ली. कहा दो करोड़ नौकरी देंगे. युवा भुलावे में आ गये. अब नौकरी देने की जगह सरकार स्किल सिखाने की बात कह रही है.

- लालू यादव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल

न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर हम सबको एक साथ आगे आना चाहिए.

- रघुवंश प्रसाद सिंह, नेता, राजद

पहले नौकरी दो, रोटी दो फिर धर्मांतरण की बात करना.

- आजम खान, नेता, समाजवादी पार्टी

उत्तर प्रदेश और बिहार सियासी गणित के अनुसार काफी महत्वपूर्ण राज्य हैं तथा सरकार बनाने-बिगाड़ने में इन्हीं की मुख्य भूमिका रहती है. इन दोनों राज्यों का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग जिस दल की ओर पलटी मारता है, उसी का पलड़ा भारी रहता है. कारण यह कि उत्तर प्रदेश में यादव, जाट, गूजर, कुर्मी एवं लोधी के बाद शेष अन्य अति पिछड़ों की आबादी 34 प्रतिशत से अधिक है और बिहार में 32 प्रतिशत से अधिक. अति पिछड़ों के सामाजिक-राजनीतिक न्याय के साथ 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए पिछले डेढ़ दशक से संघर्ष कर रहे अति पिछड़ा चिंतक एवं राष्ट्रीय निषाद संघ के सचिव लौटन राम निषाद कहते हैं कि कुछ भी हो.

अब गंगा विश्वविद्यालय पर जोर

वैष्णवी वंदना

देश भर में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का भाजपाई अभियान अब गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना पर आकर टिक गया है. अब गंगा की सफाई की व्यवहारिकता पर काम करने की बजाय सफाई पर शोध किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गंगा की सफाई पर सबसे अधिक बोलने वाली केंद्रीय जल संसाधन एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं. इस संदर्भ में उन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव से मुलाकात की. ग़ौरतलब है कि साध्वी उमा भारती ने कहा था कि तीन साल में गंगा नदी को स्वच्छ बना दिया जाएगा. मुख्यमंत्री अखिलेश और वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई. उमा भारती और शिवपाल यादव ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की. उमा भारती ने कहा कि गंगा की स्वच्छता एवं उसके संरक्षण पर शोध के लिए उक्त विश्वविद्यालय खोला जा रहा है और यह निर्मल गंगा के उद्देश्य में शामिल है. गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की पड़ताल के बाद उनके पुनर्जीवन के लिए भी सरकार कई क़दम उठाने जा रही है.

उमा भारती ने कहा कि गंगा विश्वविद्यालय जल शोधन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा. इसमें जल शोधन की नई तकनीक पर शोध होगा. गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की वास्तविक स्थिति की पड़ताल के लिए तीन सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. गंगा विश्वविद्यालय में देश-विदेश के छात्र दुनिया भर के पानी की किस्मों, पर्यावरण और अन्य विषयों की पढ़ाई करेंगे. उन्होंने दावा किया कि आगामी डेढ़ साल में गंगा में सफाई का एहसास होने लगेगा. इस बारे में उन्होंने उन मुख्यमंत्रियों से सकारात्मक बातचीत की है, जिनके राज्यों से होकर गंगा बहती है. उनमें भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के किसी घटक की सरकार नहीं है. बावजूद इसके गंगा के निर्मलीकरण में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आश्वस्त किया है कि गंगा की सफाई में राज्य सरकार केंद्र को पूरा सहयोग देगी. केन-बेतवा लिंक परियोजना पर मिलकर कार्य करने पर केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सहमति बन गई है. यह परियोजना दस हज़ार करोड़ रुपये की है.

उमा भारती ने बताया कि लखनऊ में बाढ़ नियंत्रण आयोग का कार्यालय खोलने की प्रदेश सरकार की मांग मंजूर कर ली गई है. वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित हुआ था, जिसका मुख्यालय पटना में बनाया गया था. अखिलेश ने कहा कि केंद्र द्वारा गंगा की सफाई के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, राज्य सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी. उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए ज़रूरी है कि सहायक नदियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाए. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कानपुर, मथुरा एवं वृंदावन में नालों को डायवर्ट किया जाएगा. यह भी तय किया जाएगा कि इनका पानी शोधन के बाद ही नदी तक पहुंचे. गंगा के किनारे स्थित गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी सहित दूसरे शहरों की रीवर फ्रंट विकास परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजी जाएंगी. बैठक में यह भी तय हुआ कि माघ स्नान के लिए गंगा में एक हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. एसटीपी के ज़रिये पानी को शोधित करके उसे सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे नदियों में जलस्तर बरकरार रहे. राज्य सरकार से कहा गया है कि वह बुंदेलखंड के लिए स्पेशल सिंचाई पैकेज का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे. केंद्र उस पर विचार करेगा.

राजनीति और गंगा

नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि गंगा के शुद्धिकरण के लिए हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करके जनता को बेवकूफ बनाया जाता रहा, अब जनता उसका हिसाब चाहती है, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि गंगा क्षेत्र के बाहर के लोगों को गंगा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं. संयोग से नरेंद्र मोदी गंगा क्षेत्र से ही सांसद चुन लिए गए. अब चुनौती वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है. केवल उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में प्रतिदिन 20 करोड़ लीटर मल-मूत्र और औद्योगिक कचरा गंगा नदी में गिरता है. घाटों के किनारे दिन-रात लाशें जलती हैं. राख, अधजली लकड़ियां, अधजली लाशें और मृत जानवर उसमें तैरते रहते हैं. दूसरी तरफ़ कानपुर में गंगा चमड़ा कारखानों के कारण काली और ज़हरीली हो चुकी है. कानपुर में 372 पंजीकृत टेनरियां हैं और 500 से अधिक ग़ैर-पंजीकृत. दर्जनों नाले हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में कचरा गंगा में जाता है. आईआईटी कानपुर की जांच में बताया गया है कि चमड़ा कारखानों के गंदे पानी में क्रोमियम की मात्रा लगभग 124 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो निर्धारित मात्रा से 62 गुना अधिक है. कानपुर के पुरातन ट्रीटमेंट प्लांट की तकनीक क्रोमियम को साफ़ करने में सक्षम नहीं है. यहां पर क़रीब 16 करोड़ लीटर शहरी सीवेज के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है. इस सीवेज में भी क्रोमियम की मात्रा करीब 17 मिलीग्राम प्रति लीटर यानी ख़तरनाक स्तर तक पाई गई. कई चमड़ा कारखानों का ज़हरीला कचरा शहर की सीवर लाइन में डाला जा रहा है.

1985 में राजीव गांधी की पहल पर गंगा एक्शन प्लान बना था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल किया गया था. बाद में गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया. देश की एक बड़ी आबादी गंगा के सहारे ही जीती है. अब जब केंद्र की नई सरकार ने गंगा की सफाई को लेकर एक नई पहल की, तो राजनीति फिर अड़ंगे डालने लगी. केंद्र सरकार भी एकसूत्रीय अभियान चलाने की जगह गंगा सफाई के नाम पर कई लक्ष्य साधने लगी. यहां ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा का गंगा सफाई अभियान राजनीति से प्रेरित और कम्युनल एजेंडे पर आधारित है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

चुनाव के पहले समीकरण दुरुस्त करने की कवायद

सी. लाल

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी देर है, लेकिन भाजपा और सपा अभी से अपने-अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई हैं. राज्य में लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा एवं दलित कार्ड खेलकर अप्रत्याशित सफलता हासिल करने के बाद भाजपा अति पिछड़ों एवं अति दलितों को हर हाल में विधानसभा चुनाव 2017 तक अपने साथ जोड़े रखने की जुगत भिड़ा रही है. राज्य में राजपूत, ब्राह्मण, यादव, निषाद, लोधी, कुर्मी, मौर्य-कुशवाहा थान वाली जातियां हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में जाट, सैनी एवं गूजर, तो पूर्वांचल के लगभग एक दर्जन ज़िलों में राजभर, भूमिहार, चौहान जैसी जातियां हैं. पाल, बघेल, धनगर भी राजनीतिक दृष्टि से कई क्षेत्रों में प्रभावी हैं. उत्तर प्रदेश के सियासी-जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ब्राह्मण वर्ग से कलराज मिश्र, डॉ. महेश शर्मा एवं मनोहर पार्रिकर, राजपूत वर्ग से राजनाथ सिंह एवं जनरल वीके सिंह, उमा भारती (लोधी), संजीव वालियान (जाट), मनोज सिन्हा (भूमिहार), संतोष गंगवार (कुर्मी), साध्वी निरंजन ज्योति (निषाद), मेनका गांधी (सिक्ख-ब्राह्मण) डॉ. राम शंकर कठेरिया (धानुक), डॉ. मुख्तार अब्बास नकवी (मुस्लिम) को 66 मंत्रियों में स्थान मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति मोढ़-घांची है. मोदी ने बिहार के 2015 और उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जातियों का ताना-बाना बुनने की हरसंभव कोशिश की है. उत्तर प्रदेश से दलित के नाम पर डॉ. राम शंकर कठेरिया को मंत्री बनाकर जाटव, पासी एवं वाल्मीकि जैसी मजबूत आधार वाली जातियों को नकार दिया गया है, जिससे इनमें असंतोष भी उभरा है, क्योंकि धानुक जाति की संख्या उत्तर प्रदेश में 0.5 प्रतिशत से भी कम है. 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाने का श्रेय ब्राह्मण वर्ग ने लिया, परंतु अब मायावती का इनसे मोहभंग होता दिख रहा है और वह राजाराम एवं वीर सिंह (जाटव) को पुन: राज्यसभा भेजकर अपना आधार वोट मजबूत और दलितों की नाराज़गी दूर करने के प्रयास में जुट गई हैं. अब मोदी का खौफ तमाम क्षेत्रीय एवं सूबाई क्षत्रपों को सता रहा है. इसीलिए बिहार उपचुनाव में धुर विरोधी लालू एवं नीतीश पुन: एक हो गए और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े. अब मुलायम सिंह यादव भी ख़तरा भांपते हुए पुराने जनता परिवार को इकट्ठा करने में जुट गए हैं. 1989 में कांग्रेस के विरुद्ध जनता पार्टी और वामपंथी दलों के विभिन्न कुनबे भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे. अब ऐसा लगता है कि भाजपा के विरुद्ध सभी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष एवं वामपंथी दल कांग्रेस के साथ महा-गठबंधन का खाका खींच सकते हैं.

उत्तर प्रदेश और बिहार सियासी गणित के अनुसार काफी महत्वपूर्ण राज्य हैं तथा सरकार बनाने-बिगाड़ने में इन्हीं की मुख्य भूमिका रहती है. इन दोनों राज्यों का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग जिस दल की ओर पलटी मारता है, उसी का पलड़ा भारी रहता है. कारण यह कि उत्तर प्रदेश में यादव, जाट, गूजर, कुर्मी एवं लोधी के बाद शेष अन्य अति पिछड़ों की आबादी 34 प्रतिशत से अधिक है और बिहार में 32 प्रतिशत से अधिक. अति पिछड़ों के सामाजिक-राजनीतिक न्याय के साथ 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए पिछले डेढ़ दशक से संघर्ष कर रहे अति पिछड़ा चिंतक एवं राष्ट्रीय निषाद संघ के सचिव लौटन राम निषाद कहते हैं कि कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश-बिहार में चुनाव परिणाम जातियां ही निर्धारित करेंगी. ऐसे में पिछड़ों, अति पिछड़ों की खासी भूमिका रहेगी. उत्तर प्रदेश में निषाद संवर्गीय जातियों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक है, तो वहीं बिहार में 16.5 प्रतिशत. यह काफी निर्णायक है. उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में ब्राह्मण-5.5, राजपूत-6, वैश्य-2, कायस्थ, खत्री, त्यागी, भूमिहार-2, यादव-8.60, कुर्मी-4.5 जाट-3.75, लोधी-3.5, केवट-मल्लाह-निषाद-7.5, कश्यप-कहार-धीवर-2.5, खागी-तंवर-0.75, बियार-0.25, तेली-साहू-भुर्जी-2.75, माली-सैनी-1.0, नोनिया-चौहान-1.15, नाई-सविता-0.75, राजभर-1.10, प्रजापति-1.05, लोहार-विश्वकर्मा-1.5, पाल-बघेल-2.60, कंडेरा-0.25, बरई-0.35, मौर्य-कुशवाहा-शाक्य-कोयरी-मुरांव-3.50, गूजर-0.90, अल्पसंख्यक-14.5, अनुसूचित जाति-जनजाति-23.50 प्रतिशत हैं. बिहार के जातिगत समीकरण में ब्राह्मण-4.10, राजपूत-4, भूमिहार-2.10, वैश्य-2.60, कायस्थ-1.50, यादव-11.10, निषाद-मल्लाह-केवट-बिंद-14.75, तुरहा-1.0 नोनिया-3.50, राजभर-0.70, गड़ेरिया-भेड़िहार-1.35, कुम्हार-0.90, कुर्मी-3.10, कोयरी-3.5, अन्य अति पिछड़े (नाई, ततवा, चंद्रवंशी, बेलदार)-8.30, मुस्लिम-14.80, जनजाति-1.20, जाटव-11.50, पासी-1.75, दुसाध-पासवान-2.50, मुसहर-1.50 एवं अन्य दलित-2.75 प्रतिशत हैं. बिहार में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत सर्वाधिक पिछड़ों को 28 प्रतिशत यानी स्थानीय निर्वाचन में 20 और नौकरियों में 18 प्रतिशत आरक्षण हासिल है, जिसकी मांग उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से उठ रही है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद शिवपाल, पारसनाथ, दुर्गा प्रसाद, राम गोविंद चौधरी, कैलाश नाथ एवं अंबिका चौधरी सहित सात कैबिनेट मंत्री यादव हैं, तो राजेंद्र चौधरी (जाट) एवं राममूर्ति वर्मा (कुर्मी). जबकि लोधी, निषाद, पाल, कुशवाहा, मौर्य एवं बघेल जैसी मजबूत आधार वाली जातियों को कैबिनेट में स्थान नहीं दिया गया, जिससे अति पिछड़ा वर्ग स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ चला गया. भाजपा ने 26 पिछड़ों एवं अति पिछड़ों को टिकट दिए थे, जिनमें 24 पिछड़े सांसद बन गए. अखिलेश मंत्रिमंडल में लोधी-02, शाक्य, कहार एवं पाल जाति के एक-एक विधायक को शामिल किया गया, जिससे इन वर्गों में नाराज़गी स्वाभाविक है.

सपा को पिछड़ों एवं किसानों की पार्टी कहा जाता रहा है, परंतु वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है. सपा के ज़िला-महानगर इकाई के अध्यक्षों में किसी भी पाल, बघेल, लोधी, निषाद, राजभर एवं चौहान का नाम शामिल नहीं है. सपा सरकार का मंत्रिमंडल हो या संगठन, यादव सहित कुछ ही जातियों का वर्चस्व है. भाजपा ने 35 सदस्यीय प्रदेश कमेटी में छह दलितों एवं 12 पिछड़ों-अति पिछड़ों को पदाधिकारी बनाकर सपा के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है. सपा की राष्ट्रीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें ग़ैर यादव पिछड़ों में विशंभर प्रसाद निषाद एवं रवि प्रकाश वर्मा को ही महामंत्री के तौर पर स्थान दिया गया है. प्रदेश कमेटी का गठन अभी बाकी है. भाजपा द्वारा पिछड़ा-दलित कार्ड खेले जाने के बाद सपा उसकी काट के लिए अति पिछड़ों एवं दलितों को संगठन और सरकारी संस्थाओं में सम्मानजनक हिस्सेदारी देने की कवायद में जुट गई है. बीते 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 82 दर्जाधारी मंत्रियों की लालबत्ती छीन ली थी. लेकिन, बीते 19 नवंबर से निगम, परिषद, आयोग एवं सरकारी संस्थाओं में उनके समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिन छह लोगों को समायोजित किया गया है, उनमें से जगदेव प्रसाद यादव एवं सोनी यादव पुत्री परशुराम यादव ही पिछड़े वर्ग के हैं. आत्मप्रकाश शुक्ला, सुरभि शुक्ला, मधुकर जेटली एवं रिचा उपाध्याय ऐसे नाम हैं, जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए सपा में हैं और वे किसी हाल में समाज तो दूर, अपने घर-परिवार के भी वोट सपा को नहीं दिला सकते. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

आरोप-प्रत्यारोप में फंसा विकास

बिहार की समस्याओं को लेकर इस खेल की शुरुआत तो ग़रीबों के राशन के सवाल पर हुई थी. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और बिहार में इसी से संबंधित मंत्री श्याम रजक के बीच कई दिनों तक बयान-युद्ध चलता रहा. इस बयान-युद्ध के बावजूद बिहार के ग़रीबों को कितना राशन मिला और समय पर या समय से पीछे कब-कब मिला, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है. धान ख़रीद के मामले पर तो हाल-हाल तक केंद्रीय बिहारी मंत्रियों और बिहार के मंत्रियों में बयान-युद्ध चला ही, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी भी इस बयान-युद्ध में एक कोण बनाने में पीछे नहीं रहे.

सुकांत

राजनीति का यह बहुत पुराना शगल नहीं है, अपनी कमी, गलतियां या लापरवाही का ठीकरा प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों पर फोड़ो. हालांकि, कुछ दशकों पहले तक हालात भिन्न थे, तब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकारें हुआ करती थीं. फिर भी, विकास में राज्यों की उपेक्षा के आरोप तो यदा-कदा लगते ही रहते थे. लेकिन, पिछले तीन-चार दशकों में राजनीति काफी बदली है. क्षेत्रीय दलों की ताकत काफी बढ़ी और अनेक राज्यों में वे सत्ता पर काबिज हैं. इसके बरअक्स केंद्र सरकार का नेतृत्व मुख्यत: भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के पास रहा है. इन दलों के साथ क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं और यही समीकरण विकास के बाधक तत्वों की पहचान में सबसे अहम भूमिका निभाने लगते हैं. यदि केंद्र और राज्य के शासक दल एक-दूसरे के घोर विरोधी हों, तो विकास के बाधक तत्वों की पहचान आसान हो जाती है, कथित खलनायक सामने होता है. और, चुनाव का समय आने पर तो कुछ भी कहने-सुनने की ज़रूरत नहीं. प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल को विकास विरोधी साबित कर जन-सहानुभूति हासिल कर उसे वोटों में तब्दील करने के लिए राजनेता इस नुस्खे का बेहिचक और बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं. बिहार में गत कई चुनावों से ऐसा ही हो रहा है और अब खूब तेजी से हो रहा है. ऐसे मामले तेजी से सामने आ रहे या लाए जा रहे हैं, जिन पर राज्य सरकार केंद्र को और केंद्र सरकार राज्य (इन सरकारों पर काबिज राजनीतिक दल एवं समूह) को विकास में बाधक साबित कर सकें.

केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बिहार में विकास के बाधक तत्वों की पहचान की राजनीति काफी तीखी हो गई है. आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला महीनों पहले शुरू हो गया और विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने के साथ इसमें मिर्च-मसाले की मात्रा बढ़ते जाने की हरसूरत संभावना है. सबसे ताजा मसला इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर का है. इसके लिए राज्य सरकार हरसंभव सुविधा देने का वादा सार्वजनिक मंचों से कर चुकी है, लेकिन अब तक क्या किया गया, यह बिहार नहीं जान सका है. केंद्र ने भी इस योजना को अविलंब शुरू करने का वादा किया हुआ है. अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का दावा है कि इसके लिए बिहार सरकार को उनके विभाग ने पांच पत्र लिखे हैं, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया. इस योजना से क़रीब पचास हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा और इस कलस्टर के उद्यमियों को पच्चीस प्रतिशत अनुदान. उनका आरोप है कि बिहार सरकार इस मसले पर कतई गंभीर नहीं है. इस पर बिहार सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हो सकता है, अगले कुछ दिनों में उसकी ओर से कुछ कहा जाए. इसी तरह मस्तिष्क ज्वर (जापानी इंसेफेलाइटिस) को लेकर बिहार सरकार की निष्क्रियता के केंद्र के आरोप पर भी राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बीमारी से बिहार में हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है. केंद्र का कहना है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए उसकी ओर से जो धन बिहार को मिला है, उसका एक प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है. यह तो हाल की कुछ बानगी है.

बिहार की समस्याओं को लेकर इस खेल की शुरुआत तो ग़रीबों के राशन के सवाल पर हुई थी. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और बिहार में इसी से संबंधित मंत्री श्याम रजक के बीच कई दिनों तक बयान-युद्ध चलता रहा. इस बयान-युद्ध के बावजूद बिहार के ग़रीबों को कितना राशन मिला और समय पर या समय से पीछे कब-कब मिला, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है. धान खरीद के मामले पर तो हाल-हाल तक केंद्रीय बिहारी मंत्रियों और बिहार के मंत्रियों में बयान-युद्ध चला ही, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी भी इस बयान-युद्ध में एक कोण बनाने में पीछे नहीं रहे. राज्य सरकार ने धान के घोषित समर्थन मूल्य 1360 रुपये प्रति क्विंटल को नाकाफी बताते हुए प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये बोनस मूल्य देने की घोषणा कर दी. हालांकि, इसके लिए वह अब तक धन की व्यवस्था नहीं कर सकी है. असल बात यह है कि राज्य में किसानों से धान की खरीद की स्थिति बहुत दयनीय है और किसान बिचौलियों के हाथों लुटने को विवश हैं. मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना के धन को लेकर भी केंद्र और बिहार सरकार में आरोप-प्रत्यारोप का लंबा सिलसिला चला. जिस दौर में यह मामला सरगर्म था, संयोग से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा संबंधित मंत्रालय के राज्य मंत्री थे. राष्ट्रीय उच्चपथ (एनएच) बिहार और केंद्र के बीच कटु विवाद का बड़ा मामला रहा है. बिहार सरकार पिछले कई वर्षों, जब भाजपा सरकार में शामिल थी, से कहती आ रही है कि उसने अपने खजाने से एनएच की मरम्मत कराई, लेकिन केंद्र ने अब तक उसकी भरपाई नहीं की. इस विवाद का कोई समाधान तो हुआ नहीं, पर जर्जर महात्मा गांधी सेतु को लेकर दोनों सरकारें नए सिरे से आमने-सामने आ गईं. बिहार सरकार ने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान के आधार पर महात्मा गांधी सेतु की हालत के लिए केंद्र को जवाबदेह बता दिया, तो केंद्र ने 2010 में बिहार सरकार और केंद्र के बीच हुए समझौते के तहत इसकी ज़िम्मेदारी पटना पर होने की बात कह दी. दोनों अपने-अपने स्टैंड पर कायम हैं और महात्मा गांधी सेतु धराशायी होने की प्रतीक्षा में है. उधर, महात्मा गांधी सेतु एवं मोकामा के राजेंद्र सेतु का मसला पटना हाईकोर्ट के समक्ष है और उसने सरकारों से इस बावत जानना भी चाहा है, पर सरकारें मौन हैं. इन दिनों इसे लेकर किसी तरफ़ से बयान नहीं आ रहे हैं. बिहार के विकास को समर्पित ऐसे बयानों का सिलसिला काफी लंबा है, लेकिन कई चुनावों के दौरान जिस मसले को खूब उछाला गया और जो अब सदाबहार मसला बन गया है, वह है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा. नीतीश कुमार पिछले कई चुनावों से इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं. राबड़ी शासन के अंतिम दौर में लालू प्रसाद ने भी इसे मसला बनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी राजनीति में यह मुख-शुद्धि की तरह था, लिहाजा किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2010 में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को जद (यू) का चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की. उन दिनों बिहार में एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार की अकेले की इस पहल से भाजपा आहत हो गई थी. बाद में वह भी इस मुहिम को अपनी दलीय सीमा में लेकर मैदान में आ गई. उन दिनों लालू प्रसाद और कांग्रेस विपक्ष में थे. पिछले संसदीय चुनाव के ठीक पहले और चुनाव अभियान के दौरान भी नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जद (यू) के संभावित समर्थन की पहली और एकमात्र शर्त की शक्ल दे दी, लेकिन यह मनोरथ धरा का धरा रह गया. संसदीय चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई नेताओं ने इस मांग को लेकर सूबे की जनता से वादा किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी, तो बिहार को विशेष दर्जा मिले या नहीं, विशेष पैकेज ज़रूर मिलेगा. अब नीतीश कुमार और जद (यू) इस मसले को जोर-शोर से उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो इस राज्य से टैक्स देना रोक देंगे. मांझी ने तो कभी यह भी कहा था कि बिहार के विकास में अवरोधक केंद्र के बिहारी मंत्रियों को यहां घुसने नहीं देंगे. हालांकि, उन्होंने बाद में अपने बयान वापस ले लिए थे, लेकिन इस बार टैक्स रोक देने के बयान पर वह अभी तक कायम हैं.

विशेष राज्य के दर्जे की इस राजनीति पर भाजपा फिलहाल खामोश है. उसकी राजनीति यह है कि बिहार के लिए कुछ करना है, तो चुनाव के वक्त किया जाएगा. वह इसका पूरा का पूरा लाभ खुद लेना चाहती है, जद (यू) या किसी अन्य को कोई राजनीतिक बढ़त क्यों मिले! राजनीति में तो सबको वोट का लाभ चाहिए. इसके लिए दल या नेता को कुछ करते हुए दिखना चाहिए. सो, दिखने का समय अभी आया नहीं है. आएगा, तो भाजपा कुछ न कुछ ज़रूर करेगी. फिलहाल बयानों को झेलिए. बिहार को जो मिलना होगा, वह समय पर मिल जाएगा, मनरेगा का धन हो या इंदिरा आवास या महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत या बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा... सब्र का फल मीठा होता है, कुर्सी की राजनीति कम से कम इतना तो सिखाती ही है.■

feedback@chauthiduniya.com

सुनील सौरभ

छोटी बात, बड़ी सियासत

सर्दी के दिनों में गया पूरे उत्तर भारत में तिलकुट और उसकी सोंधी महक के लिए चर्चित रहता है, लेकिन इस बार गया में हुए एक विवाद ने बिहार के राजनीतिक गलियारे में खासी हलचल मचा दी. छोटी बात पर बड़ी राजनीति हो गई. इस विवाद में हर राजनीतिक दल ने अपने नफा-नुक़सान का जोड़-घटाव करके बयानबाजी की, वहीं दूसरी तरफ़ गया के लोगों को तीन दिनों में दो-दो बार बंद झेलना पड़ा. मामला है, मगध के चर्चित राजद विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव और गया शहर के टिकारी रोड स्थित प्रसिद्ध श्रीराम तिलकुट भंडार के मालिक धीरज केशरी के बीच मारपीट का. कहा जाता है कि बीते 14 दिसंबर को विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहीं जाते समय टिकारी रोड पर रुककर अपने अंगरक्षक और चालक को उक्त दुकान से तिलकुट लाने के लिए पैसे दिए. देरी होने पर दुकान के कर्मचारियों और विधायक के अंगरक्षक के बीच कहासुनी हुई, जो अचानक मारपीट में बदल गई. मामला गंभीर होता देख विधायक स्वयं अपने वाहन से उतर कर बीच-बचाव के लिए मौक़े पर पहुंचे. आरोप है कि दुकानदार एवं कर्मचारियों ने विधायक पर चीनी की चाशनी फेंक दी, जिससे वह घायल हो गए. जबकि दुकानदार का कहना है कि विधायक दुकान में मावा की चिकनाई पर फिसल कर गिरने से घायल हुए.

अनेक संगठन नागरिक संघर्ष मोर्चा बनाकर तिलकुट दुकानदार के पक्ष में खड़े हो गए. धरना-प्रदर्शन कर मशाल जुलूस निकाला गया. 19 दिसंबर को दोबारा गया बंद किया गया. इस बीच भाजपा नेता एवं पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी गया पहुंच कर पीड़ित दुकानदार परिवार और जेल भेजे गए धीरज केशरी से मिले तथा धरने में शामिल होकर उन्होंने इस विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया.

विधायक का आरोप है कि दुकान की छत से भी उन पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया और किसी तरह जान बचाकर भागे. विधायक यादव को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया. दुकानदार धीरज ने कोतवाली थाने में विधायक के अंगरक्षक के ख़िलाफ़ मारपीट का मामला दर्ज कराया, वहीं विधायक ने दुकानदार एवं उसके कर्मचारियों के ख़िलाफ़ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने दुकानदार धीरज केशरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आनन-फानन में राजद, कांग्रेस एवं जदयू ने विधायक पर हमले के विरोध में 16 दिसंबर को गया बंद का आह्वान कर दिया. बंद के दौरान जो नजारा दिखा, वह जंगलराज-2 का साफ़ संकेत दे रहा था. यह

गया

देखकर गयावासियों, विशेषकर व्यवसायी वर्ग में अंदर ही अंदर आक्रोश पनपने लगा. भाजपा ने विधायक यादव एवं उनके अंगरक्षक की करतूत और पुलिस की एकतरफ़ा कार्रवाई के ख़िलाफ़ तथा पीड़ित दुकानदार के पक्ष में खुलकर सामने आ गई. अनेक संगठन नागरिक संघर्ष मोर्चा बनाकर तिलकुट दुकानदार के पक्ष में खड़े हो गए. धरना-प्रदर्शन कर मशाल जुलूस निकाला गया. 19 दिसंबर को दोबारा गया बंद किया गया. इस बीच भाजपा नेता एवं पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी गया पहुंच कर पीड़ित दुकानदार परिवार और जेल भेजे गए धीरज केशरी से मिले तथा धरने में शामिल होकर उन्होंने इस विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया. गया पुलिस की एकतरफ़ा कार्रवाई की जमकर आलोचना हुई. बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जब यह मामला पहुंचा, तो विधायक के तीनों अंगरक्षकों को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए गए. गया के टिकारी रोड से उठकर यह मामला बिहार विधान मंडल तक पहुंच तो गया, लेकिन गया और विधायक सुरेंद्र यादव की राजनीति को जानने-समझने वालों को यह बात पच नहीं पा रही है कि विधायक खुद कैसे तिलकुट लेने चले गए? लोगों का कहना है कि कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा है, जिसे दोनों पक्ष बताना नहीं चाहते. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में लगी है. धीरज केशरी जेल में है, वहीं उसका भाई फरार है. विधायक के अंगरक्षक को जमानत मिल चुकी है, वहीं धीरज की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. आम लोग 16 दिसंबर के राजद, कांग्रेस एवं जदयू के संयुक्त गया बंद के दौरान जंगलराज-2 का ट्रेलर देखकर भयभीत हैं. अब देखना यह है कि इस छोटी-सी बात पर हुई बड़ी सियासत से किस दल को कितना नुक़सान और कितना फ़ायदा होता है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

कमल मोरारका

कश्मीरी दलों को कश्मीर में सरकार बनानी चाहिए

पाकिस्तान की जम्मू या लद्दाख में कोई दिलचस्पी नहीं है. वह इसका स्वागत करेगा. यह पाकिस्तानी चाल भी है. भारतीय संविधान का तब क्या अर्थ रहेगा? भारत एक समग्र, समावेशी एवं धर्मनिरपेक्ष देश है और इसलिए शेख अब्दुल्ला भारत के साथ खड़े थे, उन्होंने भारत के साथ रहना पसंद किया. महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी.

पिछले हफ्ते दो राज्यों झारखंड और जम्मू-कश्मीर के चुनाव नतीजे आए हैं. नरेंद्र मोदी का प्रबल समर्थक भी इस बात को मानेगा कि मोदी लहर नाम की कोई चीज़ अब देश में नहीं है. जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान कांग्रेस के विरोध में हुआ था, क्योंकि सीएजी ने कुछ ऐसे बड़े घोटालों को बेनकाब किया था, जिन्हें देखकर लोग सकते में आ गए थे कि घोटाले इस हद तक हो सकते हैं. इसलिए लोगों के वोट सबसे मज़बूत विपक्षी पार्टी भाजपा को चले गए. भाजपा देश के अधिकांश हिस्सों में सबसे मज़बूत पार्टी थी, इसलिए उसे वोट मिल गए. जहां भी कोई विकल्प था, वहां लोगों ने उस विकल्प को चुना. उसके बाद जहां कहीं भी चुनाव हुए, यही पैटर्न दोहराए गए.

उदाहरण के लिए महाराष्ट्र को देख लें, जहां मोदी की कोई पार्टी नहीं थी. भाजपा वहां इसलिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई, क्योंकि लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे और जहां-जहां शिवसेना मज़बूत थी, लोगों ने उसे ही चुना. उसी तरह झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) न होता, तो भाजपा ने वहां भी क्लीन स्वीप कर लिया होता और लोग कहते कि मोदी लहर है. जेएमएम ने 20-30 सीटों पर अपनी मज़बूत दावेदारी पेश की. इसलिए भाजपा ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर 81 में से 42 सीटें जीतकर व्यवहारिक बहुमत हासिल कर लिया है. और, स्वाभाविक रूप से वह वहां अपनी सरकार बना लेगी, इसमें उसे कोई परेशानी नहीं होगी. अब एक नज़र जम्मू-कश्मीर पर डालते हैं, जो और भी अधिक दिलचस्प है. यहां भाजपा ने कांग्रेस के आधार पर क़ब्ज़ा किया है. जम्मू में कांग्रेस एक मज़बूत पार्टी थी और भाजपा धीरे-धीरे अपना आधार मज़बूत कर रही थी. अब लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे सारे वोट भाजपा को चले गए. पार्टी ने जो 25 सीटें जीती हैं, वे सब जम्मू क्षेत्र की हैं. घाटी से उसे एक भी सीट नहीं मिली. जबकि कांग्रेस घाटी में भी एक-दो सीटें जीतने में कामयाब होती आई है. राज्य के वोटिंग पैटर्न और बदलती हुई परिस्थितियों को समझना ज़रूरी है.

मुझे आश्चर्य है कि समीक्षक कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के चुनाव कोई रास्ता दिखाएंगे. लेकिन, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. मैं समझता हूं कि चुनाव नतीजे इस लिहाज से बुरे हैं, क्योंकि यह आर्टिकल 370 के तहत एक ऑटोनोमस राज्य है, जिसे भाजपा समाप्त करने की बात करती रही है. चुनाव प्रचार के दौरान उसने 370 की बात नहीं की. अगर ऐसा किया होता, तो उसे 25 सीटें भी न मिलतीं. फिलहाल सही राजनीतिक समाधान यह होगा कि कश्मीरी दलों को कश्मीर में सरकार बनानी चाहिए. यानी मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, जो सबसे बड़ी पार्टी है और नेशनल कांफ्रेंस को साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए. दरअसल, राजनीति में आम तौर पर यह होता है कि एक-दूसरे पर तलवारें तनी रहती हैं कि एक-दूसरे से बात नहीं करेंगे. मुफ्ती ने यह कहकर चुनाव लड़ा कि पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी है, जो भाजपा को जम्मू-कश्मीर में आने रोक सकती है. लेकिन, वह भाजपा को आने से नहीं रोक सके, क्योंकि उसके पास 25 सीटें हैं और वह अब भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं. ऐसा करना एक गलती होगी, क्योंकि वह अपना जनाधार खो देंगे. जम्मू-कश्मीर की अवाम कश्मीरियत चाहती है, जो उनका बुनियादी नारा है, वे कश्मीरी चरित्र चाहते हैं. यह हिंदू-मुस्लिम समस्या नहीं है. भाजपा जो करना चाहती है या कहती है या आरएसएस और उनके अमेरिकी दोस्त कहते हैं, उसके विपरीत जम्मू-कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 चाहते हैं. वे कश्मीर का तीन हिस्सों में बंटवारा चाहते हैं, जिसमें जम्मू भारत के साथ जाए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने और

> मुझे आश्चर्य है कि समीक्षक कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के चुनाव कोई रास्ता दिखाएंगे. लेकिन, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. मैं समझता हूं कि चुनाव नतीजे इस लिहाज से बुरे हैं, क्योंकि यह आर्टिकल 370 के तहत एक ऑटोनोमस राज्य है, जिसे भाजपा समाप्त करने की बात करती रही है. चुनाव प्रचार के दौरान उसने 370 की बात नहीं की. अगर ऐसा किया होता, तो उसे 25 सीटें भी न मिलतीं. फिलहाल सही राजनीतिक समाधान यह होगा कि कश्मीरी दलों को कश्मीर में सरकार बनानी चाहिए. यानी मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, जो सबसे बड़ी पार्टी है और नेशनल कांफ्रेंस को साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए.

कश्मीर ही एक ऐसा मसला हो, जिस पर भारत और पाकिस्तान बातचीत करें.

पाकिस्तान की जम्मू या लद्दाख में कोई दिलचस्पी नहीं है. वह इसका स्वागत करेगा. यह पाकिस्तानी चाल भी है. भारतीय संविधान का तब क्या अर्थ रहेगा? भारत एक समग्र, समावेशी एवं धर्मनिरपेक्ष देश है और इसलिए शेख अब्दुल्ला भारत के साथ खड़े थे, उन्होंने भारत के साथ रहना पसंद किया. महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी. यह तो शेख अब्दुल्ला थे, जिन्होंने कहा कि गांधी एवं नेहरू बेहतर व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति की गरिमा की गारंटी दे सकते हैं और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान जाना अच्छा नहीं होगा. जाहिर है, उनकी आशंका सच साबित हुई. आज पाकिस्तान एक परेशान देश है. मुसलमान अपने ही समुदाय के 132 बच्चों को मार रहे हैं. बदतर हालात का इससे अधिक बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? हर कोई देख सकता है कि क्या हो रहा है. लेकिन, अब जो चुनाव नतीजे आए हैं, उन्हें देखते हुए कश्मीर में सरकार बनाने का काम बहुत ही परिपक्व तरीके से किया जाना चाहिए. 44 प्लस की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए. राजनीति कॉरपोरेट की दुनिया नहीं है, जहां 2 और 2 चार होते हैं. राजनीति सिर्फ़ राजनीति है. लोगों ने सोच और विचारधारा के मुताबिक वोट किया है.

एक विचारधारा कश्मीरियत, स्वायत्तता और आर्टिकल 370 की है. मेरे हिसाब से कोई भी कश्मीरी पार्टी, चाहे वह कांग्रेस या भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए, उनसे यह वादा ले कि 370 को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा. अगर भाजपा सरकार में शामिल होती है और 370 पर चुप है, तो फिर यह इस सवाल का जवाब नहीं है. ऐसे में, मुफ्ती के लिए कांग्रेस के साथ जाना बेहतर होगा, पुरानी दुश्मनी भूल जाइए. राजनीति में शत्रुता से काम नहीं चलता. अगर चाहें, तो भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस एक साथ मिलकर भी सरकार बना सकती हैं. भाजपा केवल यहां समस्या ही खड़ी कर सकती है. भाजपा का जो एजेंडा है, वह कश्मीर को भारत से जोड़ता नहीं है. कश्मीर पर हमारा हक़ है, क्योंकि भारत के साथ उसके विलय पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भाजपा 370 की बात करके, हिंदू-मुस्लिम की बात करके इस मुद्दे को कमजोर बना देना चाहती है. भाजपा अभी भी राजनीतिक परिपक्वता के स्तर तक नहीं पहुंच सकी है, जैसी परिपक्वता सौ साल से ज़्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी की है.

अटल जी और आडवाणी जी निश्चित रूप से अलग थे. वे इन बातों को समझते थे. उन्होंने 370 पर ऐसी बातें नहीं कीं. इस चुनाव में हमने कश्मीर में 370 की बात सुनी. अच्छा यह रहा कि 370 की बात हमने प्रधानमंत्री से नहीं सुनी. सही बात तो यह है कि आर्टिकल 370 तब तक रहेगा, जब तक कश्मीरी अवाम इसे न हटाना चाहे. हम संविधान में किए गए अपने वादे को पूरा करेंगे. इस सोच के साथ ही भाजपा कश्मीर में एक बेहतर सरकार बना पाएगी. कश्मीर में भी भ्रष्टाचार है. आम तौर पर नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पसंद नहीं करते. इसलिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को सोचना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं. उन्हें भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ताकि यहां सरकार बन जाए और महबूबा को केंद्र में मंत्री पद मिल जाए. ऐसा करना दीर्घकालिक सोच वाली राजनीति की जगह अल्पकालिक राजनीति होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

खुद को ऊपर मानना मोरारजी का स्वभाव था

आपने से ऊंचा किसी को न देख पाने के आदी मोरारजी भाई के मन में अब तक बहुत कुछ इकट्ठा हो गया था. आख़िर एक दिन उन्होंने कह ही डाला, जेपी मसीहा नहीं है. उनके वक्तव्य का सार था कि जेपी का नाम नाहक लिया जाता है. मैं हूं, बस यही काफी है. मोरारजी भाई के अनुमान के विपरीत इसकी उग्र प्रतिक्रिया हुई. गुजरात में इसका इतना विपरीत प्रभाव पड़ा कि लगने लगा, चुनाव हाथ से निकल जाएगा. तब अन्य नेताओं के दबाव पर मोरारजी ने बेमन से अपने इस बयान में कि, मैं जयप्रकाश जी को आमंत्रित नहीं करूंगा, लेकिन यदि वह आना चाहें, तो उनका स्वागत है, संशोधन किया कि, मैंने जयप्रकाश नारायण से अनुरोध किया है कि वह मोर्चे के पक्ष में प्रचार करने के लिए गुजरात आएं. जयप्रकाश हरगिज न आते, वह खिन्न थे, लेकिन मोरारजी के विशेष दूत बनकर नारायण देसाई जयप्रकाश जी को साग्रह एक दिन के लिए पुन: गुजरात ले गए.

मोरारजी भाई जनांदोलन के सदैव विरोधी रहे. यद्यपि इमरजेंसी के बाद सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक नया चेहरा ओढ़ने की कोशिश यह कहकर की कि मैं गलती करूं, तो आप मेरे कान पकड़ सकते हैं. पर उनसे मिलने के बाद, विशेषकर युवकों की, एक ही प्रतिक्रिया होती कि मोरारजी भाई तो सीधा गला ही पकड़ लेते हैं. आंदोलन के मूलत: विरोधी होने के बावजूद उन्होंने कई बार अपनी व्यक्तिगत महत्ता की वृद्धि के लिए आमरण अनशन का सहारा लिया. गांधी के शिष्य कहलाने का दावा करने वाले मोरारजी भाई को गांधी का यह विचार अवश्य मालूम होगा कि आत्मशुद्धि अथवा आत्मान्वेषण के लिए उपवास एक चीज है और किसी मांग को मनवाने के लिए आमरण अनशन दूसरी चीज. आमरण अनशन एक अस्त्र है, जो बहस, जनमत, सिविल

> इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव की घोषणा कर देने के बाद मोरारजी भाई और चरण सिंह के आपसी द्वंद्व के कारण एक पार्टी का फ़ैसला नहीं हो पाया. लोकसभा चुनाव की 18 जनवरी को घोषणा हो गई. जेपी विरोधी दलों के नेताओं की गतिविधियों से खिन्न थे. संभवत: 19 की रात में एसएम जोशी ने जेपी को दिल्ली से सूचित किया कि किन छोटे कारणों को लेकर दलों के नेता पुन: देश की किस्मत से खेलना चाहते हैं. जयप्रकाश नारायण ने अपना बयान कि यदि एक दल नहीं बनता है, तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, जारी कर दिया.

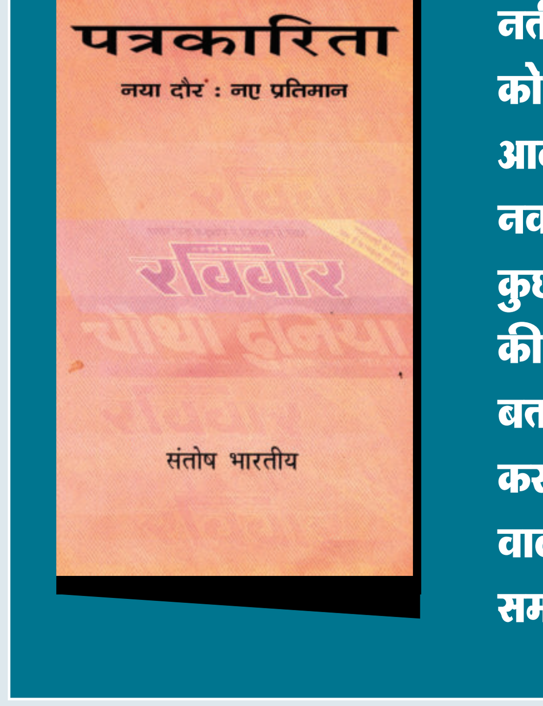

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

नाफरमानी, इन सबके चुक जाने के बाद ही इस्तेमाल करने के योग्य है और वह भी इस स्वीकार के साथ कि यथेष्ट संगठन अथवा जनांदोलन उस मांग के पक्ष में नहीं रह गया है, जिसके लिए अनशन किया जा रहा है. मोरारजी ने आज़ादी के बाद जन-राजनीति नहीं की, पर अपनी बात मनवाने के लिए अनशन ज़रूर किए. गांधी की सिविल नाफरमानी और सत्याग्रह का कितना सही और व्यापक प्रयोग जयप्रकाश ने बिहार में किया, यह देखने की आवश्यकता मोरारजी भाई को कभी नहीं हुई.

25 जून, 1975 (जब इमरजेंसी की घोषणा हुई थी) की रात की घटना भी मोरारजी भाई के मन का परिचय कराती है. रात दो बजकर कुछ मिनट पर मोरारजी भाई के टेलीफोन की घंटी बजी. फोन एक वरिष्ठ विदेशी पत्रकार का था. मोरारजी भाई को उसने बताया कि जयप्रकाश को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ विशेष घटने जा रहा है. मोरारजी भाई का ठंडा उत्तर मिला, अच्छा, ऐसा हुआ है. मैं सुबह देखूंगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं. इसके आधे घंटे के अंदर वह स्वयं पकड़ लिए गए. जब जयप्रकाश को गुर्दे खराब हो जाने के कारण सरकार ने डर की वजह से छोड़ दिया और ऑपरेशन के बाद वह बंबई में आराम कर रहे थे, उस समय उनकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरह विरोधी

> मोरारजी भाई जनांदोलन के सदैव विरोधी रहे. यद्यपि इमरजेंसी के बाद सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक नया चेहरा ओढ़ने की कोशिश यह कहकर की कि मैं गलती करूं, तो आप मेरे कान पकड़ सकते हैं. पर उनसे मिलने के बाद, विशेषकर युवकों की, एक ही प्रतिक्रिया होती कि मोरारजी भाई तो सीधा गला ही पकड़ लेते हैं. आंदोलन के मूलत: विरोधी होने के बावजूद उन्होंने कई बार अपनी व्यक्तिगत महत्ता की वृद्धि के लिए आमरण अनशन का सहारा लिया.

दल एक पार्टी बना लें. जून, 76 में उन्होंने एक ऐसा बयान भी दे दिया था, लेकिन उनके इस प्रयास का सबसे ज़्यादा विरोध मोरारजी भाई ने ही किया. मात्र जयप्रकाश ही ऐसे नेता थे, जिन्हें भरोसा था कि यदि जनता को मौक़ा मिलेगा, तो वह तानाशाही को उखाड़ फेंकेगी. इसकी प्राथमिक शर्त वह एक पार्टी का बनना मानते थे. उन दिनों एक सज्जन जेपी से मिले थे, जिन्होंने मोरारजी भाई का यह विचार कि यदि एक पार्टी बनेगी, तो इंदिरा और मजबूत होगी, बताया था.

इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव की घोषणा कर देने के बाद मोरारजी भाई और चरण सिंह के आपसी द्वंद्व के कारण एक पार्टी का फ़ैसला नहीं हो पाया. लोकसभा चुनाव की 18 जनवरी को घोषणा हो गई. जेपी विरोधी दलों के नेताओं की गतिविधियों से खिन्न थे. संभवत: 19 की रात में एसएम जोशी ने जेपी को दिल्ली से सूचित किया कि किन छोटे कारणों को लेकर दलों के नेता पुन: देश की किस्मत से खेलना चाहते हैं. जयप्रकाश नारायण ने अपना बयान कि यदि एक दल नहीं बनता है, तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, जारी कर दिया. दिल्ली में सेठ रामनाथ गोयनका को रात साढ़े बारह बजे इस बयान का उनके अख़बार के दफ्तर से पता चला. तत्काल वह उसकी प्रति लेकर मोरारजी भाई के पास भागे. अन्य नेताओं से भी तत्काल संपर्क किया गया. सुबह के अख़बार में दो प्रमुख ख़बरें छपीं, पहली जेपी के वक्तव्य की और दूसरी, जनता पार्टी के निर्माण का सर्वसम्मत फ़ैसला. मोरार जी भाई इस बार दूरदर्शी निकले. उन्होंने जेपी के बयान के महत्व को समझ लिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह आत्मावलोकन का वक्त है

पाकिस्तान के पेशावर में बच्चों की हत्या को दुनिया आसानी से नहीं भूल पाएगी. हालांकि, बच्चों की हत्या अफ़्रीकी देशों में भी की जाती है. बच्चों की हत्या का एक अभियान मैक्सिको में चला, ब्राजील में चला, लेकिन उनकी संख्या भी कम होती थी और उनके कारण अलग-अलग होते थे. पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादियों ने बच्चों की हत्याएं कीं, वह सचमुच दिल को दहला गई. आतंकवादियों ने सारे साक्ष्य छोड़े और यह साबित किया कि वे पाकिस्तान के ही हैं. जो बच्चे बच पाए, उन्होंने कहा कि वे लोग पस्तो और अरबी में बोल रहे थे. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों के फोटो भी प्रेस को सौंपे, जो इस हत्याकांड में शामिल थे.

एक मज़ाक पाकिस्तान में हुआ. जिस बात को पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री सहित किसी ने नहीं जाना, वह बात भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को पता चल गई और वही बात हाफिज सईद को पता चल गई और इन दोनों ने कहा कि इस हत्याकांड के पीछे भारत है. इतना ही नहीं, इन लोगों ने यहां तक कहा कि अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोगों से हिंदुस्तान की इंटेलिजेस एजेंसी के लोगों की बातचीत हुई, जहां पर यह योजना बनी. फिर पाकिस्तान को आईएसआई और सेना की या प्रधानमंत्री के पास उपलब्ध जानकारी की ज़रूरत ही क्या रह गई, अगर हाफिज सईद और परवेज मुशर्रफ को उस सच्चाई का पता चला, जिसकी जानकारी दुनिया में किसी के पास नहीं है? यह मज़ाक इसलिए लगता है और इससे जो चीज साबित होती है, वह यह कि पाकिस्तान में कुछ ताकतें हैं, जिन्हें सत्ता में ही कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त है और जो किसी भी क़ीमत पर नहीं चाहतीं कि पाकिस्तान से आतंकवाद का ख़ात्मा हो. जब पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो उन सारे लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, जो आतंकवाद के समर्थक हैं. शायद वे अपने देश को या तो टूटता हुआ देखना चाहते हैं या अपने देश में आतंक की एक नई फैक्ट्री पैदा करना चाहते हैं. पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के 90 प्रतिशत लोग इस समय आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है.

पर जो सवाल इस हत्याकांड ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किए, खासकर पाकिस्तानी मीडिया के सामने, वही हिंदुस्तान की मीडिया के सामने भी हैं. मैंने कुछ राजनेताओं से, कुछ टेलीविजन के पत्रकारों से एक छोटा-सा सवाल किया कि क्या आपको मालूम है कि परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? उत्तर लगभग इसके आसपास था कि जो सेना में बहादुरी का काम करते हैं, उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है. फिर मैंने पूछा, अच्छा, वीर चक्र किसे दिया जाता है? इस सवाल पर वे खामोश हो गए. हमारे देश के बच्चों को फिल्म फेयर अवॉर्ड किसे मिला, यह तो पता है और हमारे ही देश के बच्चों को किस फिल्मी फंक्शन में किसे सर्वश्रेष्ठ नायक और किसे सर्वश्रेष्ठ नायिका चुना गया, यह तो पता चलता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चलता कि हमारे देश के नायक होने के नाते किसे क्या अवॉर्ड मिला. शायद किसी को यह भी पता नहीं होगा कि हमारे पास अब तक परमवीर चक्र पाने वाले कितने लोग हैं और उनकी पहचान क्या है. यह तो निश्चित रूप से नहीं पता है कि उनके घर की हालत आज क्या है. क्या शहादत देने वाले सेना या पुलिस के जांबाजों, जिन्हें परमवीर चक्र या वीर चक्र मिल चुके हैं, उनके घरों में आज भोजन है या नहीं, उनका घर बना है या नहीं, उनकी लड़कियों की शादी हो गई या नहीं या उनके परिवार के लोग अब कहीं नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यह सब किसी को नहीं पता. न यह टेलीविजन का सब्जेक्ट है और न अख़बारों का विषय है.

> अफ़सोस इस बात का है कि हमारा पूरा मीडिया अपनी इस सामाजिक ज़िम्मेदारी से बहुत दूर चला गया है. अभी भी हमारे मीडिया को यह समझ में नहीं आ रहा कि देश के नौजवानों को देश के लिए मरने वालों के बारे में जानकारी देना उनका बुनियादी कर्तव्य है. इसे वह नहीं निभा रहा है, इसका अफ़सोस भी उसे नहीं है.

अफ़सोस इस बात का है कि हमारा पूरा मीडिया अपनी इस सामाजिक ज़िम्मेदारी से बहुत दूर चला गया है. अभी भी हमारे मीडिया को यह समझ में नहीं आ रहा कि देश के नौजवानों को देश के लिए मरने वालों के बारे में जानकारी देना उनका बुनियादी कर्तव्य है. इसे वह नहीं निभा रहा है, इसका अफ़सोस भी उसे नहीं है.

मैं एक घटना बताता हूं. विक्टोरिया क्रॉस नाम का एक गैलिन्ट्री अवॉर्ड है, जो ब्रिटेन के लिए विश्व युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों को दिया जाता था. हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिला. 60 के दशक में लंदन में जीवित विक्टोरिया क्रॉस पाने वालों को वहां की सरकार ने बुलाया. भारत में उत्तराखंड में रहने वाले विक्टोरिया क्रॉस पाए हुए एक सज्जन पहुंच गए और वह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शाम को टहलने निकले. अचानक उन्होंने देखा कि लोगों ने सड़क खाली कर दी और वे अपनी-अपनी दुकानों से सिर निकाल कर और किनारे लाइन बनाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं. और वह गुजर रहे हैं, तो तालियां बजा रहे हैं. वह सज्जन चौंक गए कि लगता है, ब्रिटेन का कोई बड़ा राजनेता यहां से निकलने वाला है, जिसके स्वागत में लोग खड़े हैं. तो बिना ध्यान दिए हुए वह सड़क पर चलते रहे. जब वह दो हज़ार गज आगे बढ़े, तब उन्हें कुछ हिंदुस्तानी नज़र आए और तब उनसे उन्होंने पूछा, ये क्यों और किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तब उन हिंदुस्तानियों ने उन्हें बताया, सर ये आप ही के सम्मान में किनारे खड़े हैं अंग्रेज और यह आप ही के सम्मान में तालियां बजा रहे हैं. दरअसल, जब वह सज्जन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर पहुंचे, तो उनके बाईं तरफ़ विक्टोरिया क्रॉस लटका हुआ था. यह देखकर पूरी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर हवा की तरह बात फैल गई कि विक्टोरिया क्रॉस पाया हुआ एक सिपाही आ रहा है और ब्रिटेन के लोगों ने उसका नेशनल हीरो की तरह स्वागत किया.

> एक मज़ाक पाकिस्तान में हुआ. जिस बात को पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री सहित किसी ने नहीं जाना, वह बात भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को पता चल गई और वही बात हाफिज सईद को पता चल गई और इन दोनों ने कहा कि इस हत्याकांड के पीछे भारत है. इतना ही नहीं, इन लोगों ने यहां तक कहा कि अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोगों से हिंदुस्तान की इंटेलिजेस एजेंसी के लोगों की बातचीत हुई, जहां पर यह योजना बनी.

यह घटना मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहां कोई भी गैलिन्ट्री अवॉर्ड पाने वाला पुलिस या सेना का जांबाज अगर किसी सरकारी दफ्तर में किसी मदद के लिए चला जाए, तो वहां आज भी उसका सम्मान नहीं होता. हमारे अंदर अपने देश के लिए शहादत देने वालों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और जो शहादत दे चुके हैं, उनके परिवार वालों के लिए भी कोई सम्मान नहीं है. मैं इन लाइनों को लिख रहा हूं और जो भी पढ़ रहे हैं, खासकर मीडिया से जुड़े हुए लोग, वे अपने मन से पूछें कि उन्हें देश के गैलिन्ट्री अवॉर्ड के बारे में कुछ पता है या नहीं? और, जब उन्हें ही नहीं पता, तो देश के नौजवानों को यह बात कहां से पता चलेगी?

पाकिस्तान के मीडिया से जुड़ी हुई यासमीन मिर्जा का लेख हम इस अंक में छाप रहे हैं. पाकिस्तान के मीडिया में इसे कोई जगह नहीं मिली, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड किया, तो दुनिया के करोड़ों लोगों ने उसे देखा और उसकी तारीफ़ की, क्योंकि उसने जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सवाल खड़े किए, वे सवाल हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हूबहू लागू होते हैं. एक गिरोह बन गया है. वही गिरोह, जिसमें कुछ दलाल हैं, कुछ पब्लिक रिलेशन वाले पत्रकार हैं, कुछ वे हैं जिन्हें जनता के दु:खों से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि वे अपने मालिकों के लिए रास्ता तैयार करते हैं. और, ये सब रात में टेलीविजन पर बैठकर देश की जनता की आकांक्षाओं के ख़िलाफ़ आचरण करते हैं. ये उसे न कोई जानकारी देते हैं, न कोई नया रास्ता बताते हैं और न कोई सपना दिखाते हैं. एंकर टेलीविजन चैनल में एक ही होता है, लेकिन शामिल होने वाले वे कभी होते ही नहीं, जिनकी तकलीफ होती है. नौजवानों के भविष्य के ऊपर बात करनी हो, तो वही चार-पांच-छह चेहरे, नौजवानों को नौकरी देनी हो, तो वही चार-पांच-छह चेहरे, ग़रीबी के ऊपर बात करनी हो, तो वही चार-पांच- छह चेहरे, अपराध की बात करनी हो, तो वही चार-पांच-छह चेहरे और अर्थव्यवस्था की बात करनी हो, तो वही चार-पांच-छह चेहरे. यासमीन मिर्जा द्वारा पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उठाए गए सवाल हिंदुस्तान के लोगों को सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए. यासमीन ने अपने यहां मौलानाओं के ऊपर, मौलवियों के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर पत्रकारों के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं, वे सवाल हमारे यहां पर भी लागू हैं. शायद हम दोनों एक ही तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं.

मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पाकिस्तान का मीडिया कोई सबक नहीं ले रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान का मीडिया भी कोई सबक न ले रहा है और न लेगा. मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि आजकल टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली ज़्यादातर ख़बरों को लोग मनोरंजन के रूप में लेते हैं. शायद इसलिए, क्योंकि ख़बरों और पैनल डिस्कशन में लोगों से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं होती. चूंकि लोगों के मतलब की कोई चीज नहीं होती, तो जिस तरह तीन घंटे सिनेमा देखते हैं, उसी तरह लोग तीन घंटे शाम को ख़बरें देख लेते हैं, क्योंकि अब ख़बरों में भी उन्हें काफी मनोरंजन मिलता है. चाहे मनोरंजन के चैनल हों या चाहे न्यूज के चैनल, बहुत ज़्यादा फ़र्क़ उनमें नहीं बचा है.

मुझे पूरा विश्वास है कि इन सवालों से, जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, हम कोई सबक नहीं लेंगे और हमारा मीडिया दिनोंदिन और ज़्यादा गिरावट की राह पर चलता चला जाएगा. देखते हैं, गिरने की सीमा कहां आती है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

देश को एक बेहतर संसद की अपेक्षा है

एक हज़ार सदस्यों पर आधारित संसद बहुत बड़ी प्रतीत होती है, लेकिन देश के आकार और जटिलता को देखते हुए कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है. मिसाल के तौर पर महिलाओं की भागीदारी का सवाल बहुत दिनों से टाला जाता रहा है, लेकिन एक बड़ी संसद में महिलाओं की उचित भागीदारी आसानी से संभव है. उसी तरह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी उनकी जनसंख्या के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सकता है.

संसद की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने की सामान्य प्रक्रिया पुन: शुरू हो गई है. और, इस पर किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए. संसद में अव्यवस्था जहां भ्रामक है, वहीं व्यवहारिक भी है. भ्रामक इस वजह से है, क्योंकि संसद के वास्तविक काम टेलीविजन कैमरों की नज़रों से दूर स्थायी समितियों में होते हैं. किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले संसद के बाहर कई समझौते करने पड़ते हैं. सबसे अधिक विवादास्पद विधेयक मिनटों में पारित करा दिए जाते हैं. तेलंगाना इसकी मिसाल है. जब विपक्ष किसी विधेयक को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता, तो वह उसमें व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर देता है. लेकिन, कार्यपालिका संसदीय कार्य निर्धारण में सबसे प्रभावशाली होती है. पीछे की सीटों पर बैठने वाले सांसद, जिनकी अपनी कोई स्वतंत्र राय नहीं होती, वे ही स्पीकर वेल में पहुंच कर हंगामा करते हैं. दरअसल, यह ताक़त की नहीं, अक्षमता की निशानी है. इन सबके बावजूद देश एक बेहतर संसद की अपेक्षा करता है. भारतीय संसद का संचालन अंग्रेजों के समय जिस तरह होता था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है. उस समय कार्यपालिका को बहुत अधिक अधिकार मिले हुए थे. ब्रिटिश संसद में पिछली बेंच पर बैठने के बावजूद मैंने अक्सर अपनी पार्टी-लाइन के ख़िलाफ़ बोला है. मैंने अनेक बार संसद में संशोधन पर अपना वोट दिया और अक्सर सरकार को हराया भी है. इसलिए, कम से कम भारतीय संसद को एक बेहतर कार्यप्रणाली की आवश्यकता है और पिछली बेंच पर बैठने वाले सांसदों को भी मुखर बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि वे शुरू के तीन दशकों में थे.

संसद के सुधार की प्रकिया में हमें लगातार चलने वाले चुनावी चक्र को भी ध्यान में रखना होगा. ऐसा लगता है, चुनाव का मौसम कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि आम चुनाव के बाद, एक के बाद एक राज्यों के चुनाव होते रहते हैं. राजनीति हमेशा चुनाव प्रचार के रंग में रंगी रहती है. प्रधानमंत्री जबसे चुनकर आए हैं, तबसे लगातार चुनावी दौरे पर हैं. पहले महाराष्ट्र एवं हरियाणा और फिर झारखंड एवं जम्मू-कश्मीर. उसके बाद दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं और यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा. अब समय आ गया है कि सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ एक तारीख पर कराए जाएं. पचास के दशक में चुनाव की शुरुआत के समय ऐसा ही होता था. उसके बाद त्रिशंकु जनादेश मिलने लगे और सरकारों के कार्यकाल कम होने लगे, जिसके कारण सामंजस्य भी बिगड़ गया. यह उम्मीद करनी चाहिए कि 2024 से हम सभी चुनाव एक साथ करा पाएंगे. इसका मतलब यह होगा कि अगर कोई सरकार पांच साल पूरा किए बगैर गिर जाती है, तो नई सरकार केवल बाकी बचे हुए समय तक ही सत्ता में रहेगी. ऐसा तभी संभव हो पाएगा, जबकि ब्रिटेन की तरह भारत में निश्चित अवधि संसद विधेयक लाया जाए. इस विधेयक की वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाने में कमी आएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जीतने वाले लोग केवल कुछ समय के लिए ही सत्ता में रहेंगे. इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी. यह कोई नया विचार नहीं है. लालकृष्ण आडवाणी ने प्रशासनिक सुधार आयोग बनाकर इस दिशा में क़दम उठाया था, अब इस काम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है.

एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मतदाताओं की संख्या है. आज मतदाताओं की संख्या 80 करोड़ हो गई है, जबकि सांसदों की संख्या केवल 545 है. मेरे विचार से हर दस लाख मतदाताओं के लिए कम से कम एक सांसद होना चाहिए. यह तर्कसंगत भी है. एक तो यह किया जा सकता है कि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करके 255 नई सीटें जोड़कर कुल संसद सदस्यों की संख्या 800 तक कर दी जाए. जब हम संसदीय प्रणाली में सुधार की बात कर रहे हैं, तो कुछ और मुद्दे हैं, जिन पर विचार होना चाहिए. छोटी पार्टियों के लिए फर्स्ट-पास्ट-पोस्ट प्रणाली ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने वोट शेयर के अनुपात में सीटें नहीं मिलती हैं. कई देशों में इस कमी को पूरा करने की व्यवस्था है. यानी पार्टियों के वोट शेयर के अनुपात में उन्हें सीटें दे दी जाती हैं. उक्त संसद सदस्य केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे 200 संसद सदस्यों का इज़ाफा भी कोई अनुचित विचार नहीं है.

एक हज़ार सदस्यों पर आधारित संसद बहुत बड़ी प्रतीत होती है, लेकिन देश के आकार और जटिलता को देखते हुए कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है. मिसाल के तौर पर महिलाओं की भागीदारी का सवाल बहुत दिनों से टाला जाता रहा है, लेकिन एक बड़ी संसद में महिलाओं की उचित भागीदारी आसानी से संभव है. उसी तरह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी उनकी जनसंख्या के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सकता है. इन सभी वर्गों को स्वतंत्र सूची से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है. दरअसल, एक बड़ी संसद के लिए एक नई इमारत की ज़रूरत होगी. इसका कोई औचित्य नहीं है कि हम अंग्रेजों की विरासत से चिपके रहें. मेरे हिसाब से उक्त इमारतें अपने ज़माने की सबसे अच्छी इमारतें थीं, ब्रिटेन की संसद से भी बेहतर थीं. लेकिन, संसद की नई इमारत में सदस्यों को हंगामा करने के लिए कोई स्पीकर वेल नहीं होना चाहिए! ■

feedback@chauthiduniya.com

आवश्यक दवाओं की सूची में नई दवाएं शामिल

मोनिशा भटनागर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 1977 में आवश्यक दवाओं को परिभाषित किया गया. ऐसी दवाएं जो बहुसंख्यक लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, 'आवश्यक दवाएं' कहलाती हैं, इसी कारण वे सदा पर्याप्त मात्रा में, समुचित रूप में और जनता द्वारा वहन करने योग्य मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए.

देखा गया है आवश्यक दवाओं की सूची हेल्थ–केयर डिलीवरी की गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता में सुधार करने में कारगर है. डब्ल्यूएचओ द्वारा चयनित दवाओं की एक सीमित सूची और अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 1996 में अपनी पहली राष्ट्री आवश्यक दवाओं की सूची प्रकाशित की जिसे 2003 में संशोधित कर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) तैयार की गई. इस सूची की दवाओं के दाम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) खुद नियंत्रित करती है, जिसके चलते मरीजों को ये दवाएं अपेक्षाकृत सस्ती मिलती हैं. आवश्यक दवाओं की सूची, अस्पताल दवा नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र में दवाओं की खरीद और आपूर्ति, चिकित्सा लागत प्रतिपूर्ति और दवा दान में मार्गदर्शक होती है. यह सूची सही खुराक के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में भी कार्य करती है. एनएलईएम सूची में शामिल दवाइयां और टीके हर समय, पर्याप्त मात्रा में और उचित खुराक के अनुसार मरीजों के लिए किफायती कीमतों पर उपलब्ध होने चाहिए.

आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के प्रयास के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 52 नई दवाओं को अपनी मूल्य नियंत्रण प्रणाली के दायरे में लेने का फैसला किया है. 10.12.2014 को दिए गए आदेश में एनपीपीए ने 52 सूत्रीकरण (फार्मूलेशन) पैक के, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 2013 के तहत दोनों उच्चतम मूल्य और खुदरा मूल्य पैक की कीमतों को संशोधित किया है. अपनी अधिसूचना में एनपीपीए ने कहा है कि वह दवाओं की कीमतें उसके फॉमूर्लेशन के आधार पर तय करती है, जिनमें पैरासिटामॉल, ब्लीचिंग पाउडर, कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिंक सल्फेट, क्लॉकासिलिन, जेंटामाइसिन, ग्लूकोज के साथ ही अन्य मिश्रण वाली कई ज़रूरी दवाइयां शामिल हैं. अपने आदेश में प्राधिकरण ने अधिूसचित फॉमूर्लेशन के विनिर्माताओं से कहा है कि अगर उनकी दवाओं की कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य तय सीमा से ज्यादा हो तो वे उसमें कटौती करें और अगर इन दवाओं की कीमतें तय सीमा से नीचे है हो तो वे अधिकतम खुदरा मूल्य को उक्त स्तर पर बनाए रख सकते हैं. देश में जरूरी दवाओं की किफायती कीमत पर उपलब्धता अहम मुद्दा है, क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी रोजाना करीब 125 रुपए से कम आय पर गुजर–बसर करती है और ऐसे में बीमारी के इलाज़ के लिए आवश्यक दवाओं का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है. बाजार में हर दवा अनेक नामों से बिकती है. उपभोक्ता चिकित्सा ज्ञान के अभाव के कारण यह निर्णय करने की स्थिति में ही नहीं होता कि अलग–अलग नामों से बिकने वाली दवा एक ही है या नहीं. इसी वजह से एक ही दवा के विभिन्न ब्रांड बाजार में बिकते हैं, जिनकी कीमतों में जमीन–आसमान का अंतर होता है. सरकार के इस कदम के बाद अब 450 से अधिक दवाएं एनपीपीए की मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अधीन आ गयी हैं.

आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के प्रयास के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 52 नई दवाओं को अपनी मूल्य नियंत्रण प्रणाली के दायरे में लेने का फैसला किया है. 10.12.2014 को दिए गए आदेश में एनप-ीपीए ने 52 सूत्रीकरण (फार्मूलेशन) पैक के, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 2013 के तहत दोनों उच्चतम मूल्य और खुदरा मूल्य पैक की कीमतों को संशोधित किया है. अपनी अधिसूचना में एनपीपीए ने कहा है कि वह दवाओं की कीमतें उसके फॉमूर्लेशन के आधार पर तय करती है, जिनमें पैरासिटामॉल, ब्लीचिंग पाउडर, कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिंक सल्फेट, क्लॉकासिलिन, जेंटामाइसिन, ग्लूकोज के साथ ही अन्य मिश्रण वाली कई ज़रूरी दवाइयां शामिल हैं.

मूल्य नियंत्रण की सूची में शामिल 52 दवाओं में पैरासिटामॉल, डायजेपम, डिक्लोफेनेक, ग्लुकोज, कोडीन फॉस्फेट, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिनऔर लोजार्टन जैसी आमतौर पर काम आने वाली दवाएं शामिल हैं. इसमें कुछ दर्दनिवारक व एंटीबायोटिक(इन्फेक्शन से लड़ने वाली) दवाएं भी हैं. इसके अलावा कैंसर और त्वचा रोगों के इलाज में काम आने वाली,आंत्रशोथ (गैस्ट्रो ड्रग) से संबंधी दवाएं और टीके भी शामिल हैं. इस सूची में पारासिटामॉल, डिक्लोफेनेक, एमोक्सिसिलिन जैसी जेनेरिक दवाइयों का होना आम जनता खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए अच्छी खबर है. जेनेरिक दवा वह दवा जो किसी ब्रांड नाम से नहीं बनाई जाती, बल्कि उस नाम से बनाई जाती है, जो इसकी विशेषज्ञ समिति ने तय किया हो या अपने रासायनिक नाम से. इसमें वही तत्व मिले होते हैं, जो एक ब्रांडेड दवा में होते हैं लेकिन यह बिना किसी पेटेंट के बनायी और वितरित की जाती है.जेनेरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है किन्तु उसके सक्रिय घटक (एक्टिव इंग्रेडिएंट) पर पेटेंट नहीं होता और यह उत्पादक से सीधे रिटेलर तक पहुंचती हैं जिसके कारण यह ब्रांडेड दवाओं से कई गुना सस्ती होती हैं.इसके बावजूद बाजार में जेनेरिक मेडिसन की खपत कुल दवा बाजार की तुलना में अभी 10 से 12 फीसदी ही है. ऐसा कम जानकारी या जानकारी के अभाव की वजह से है. जेनेरिक दवाओं के बारे में आम धारणा है कि इनकी गुणवत्ता ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के बराबर ही गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी होती हैं. जेनेरिक दवाईयां गुणवत्ता मापदंडों जैसे आइडेंटिटी और प्रभावशीलता में ब्रांडेड दवाईयों के समान होती है और उतनी ही असरकारक भी होती हैं. निहित स्वार्थ के लिए कई बार डॉक्टर भी जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठा देते हैं, जो बेबुनियाद होते हैं. जेनेरिक दवा का नाम पूरी दुनिया में एक ही होता है. जैसे बुखार और दर्द को दूर करने वाली पैरासिटामॉल की टेबलेट हर कंपनी अलग–अलग नाम से बनाती है, लेकिन अगर यह जेनेरिक होगी तो इस पर सिर्फ पैरासिटामॉल लिखा होगा. ब्रांडेड दवाओं के नाम पर निर्माता का एकाधिकार होने के कारण जेनेरिक के बजाय ब्रांडेड दवाईयां कई गुना अधिक मंहगी बिकती है, परन्तु दोनों की गुणवत्ता समान होती है. बाजार में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता से कई फायदे हैं. जैसे उच्च गुणवत्ता की दवाओं की कम कीमत पर उपलब्धता, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न ब्रांड से भ्रम की स्थिति का समाप्त होना और ब्रांड के नामों से प्रचलित दवाओं के प्रचार–प्रसार से होने वाले व्यय में कटौती.

2014 जुलाई में भी प्राधिकरण ने कई दवाओं की कीमतों में कमी की थी, इसके अलावा सितंबर में भी एनपीपीए ने 43 दवाओं को इस सूची में डाला था.प्राधिकरण के इस कदम से प्रभावित होने वाली प्रमुख दवा कंपनियों में ल्यूपिन, कैडिला व मर्क शामिल हैं. इसके अलावा फैसले प्रभावित होने वाली कुछ दवाएं निम्न हैं– पैरासीटामॉल, डायजापॉम, एम्लोडिपिन, साइक्लोस्पोरिन, डाइक्लोफिनेक, एमोक्सिसिलिन, कोडीन फॉस्फेट, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, होमपेरिडोन.■

feedback@chauthiduniya.com

हिटलर की जासूस स्टेफनी

जब 1933 में हिटलर की सरकार आई तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एमआई 16 के दस्तावेज जारी कर इस बात की जानकारी दी थी कि फांसिसी खुफिया एजेंसी को स्टीफेन के कमरे से कुछ कागजात मिले हैं जिनमें इस बात की जानकारी थी कि उन्हें जर्मनी से किसी काम को पूरा करने के आदेश मिले थे. इस काम के लिए वर्तमान समय के अनुसार 13 मिलियन डॉलर की पेशकश की गई थी. स्टेफनी को ब्रिटिश नेता रोथरमूर से आर्थिक मदद मिलती थी. वे कुछ ऐसे ब्रिटिश नेताओं में थे जो चाहते थे कि जर्मनी का समर्थन किया जाए. वे स्टेफनी को इस बात के लिए आर्थिक मदद दिया करते थे कि वे देश में जर्मनी के लिए समर्थन में बढ़ोतरी करवाएं.

अरुण तिवारी

स्टीफेन जूलियन होहेनलोह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थीं. उन्होंने राजकुमार फ्रेड्रिक फ्रेंज से शादी की थी. उनका फेमिली बैकग्राउंड यहूदियों का था. उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था. बाद में वे लंदन शिफ्ट हो गई थीं. यहीं पर उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वे जर्मनी की जासूस के तौर पर काम कर रही हैं. अपने तलाक के बाद उन्होंने नाजी अधिकारियों के संबंध प्रगाढ़ किए थे. वे हिटलर की भी करीबी मानी जाती थीं. ब्रिटिश फ्रेंच और अमेरिकन, सभी उपर जर्मनी की जासूस होने का शक किया करते थे. इस दौरान उन्होंने यह भी कोशिश की कि ब्रिटेन जर्मनी का सहयोग करे. 1930 के दशक के दौरान नाजी पार्टी ने उनकी सेवाओं के लिए गोल्ड मेडल दिया था.

जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटेन से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को भाग गईं. उन पर शक होने के कारण अमेरिका ने उन पर सर्विलांस लगा दिया. पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. ऐसा माना जाता है कि गिरफ्तारी के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी को हिटलर के बारे में कुछ ऐसी गोपनीय जानकारियां भी दी थीं जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने बाद में किया था. मई 1945 में उन्हें परोल पर छोड़ दिया गया. वे जर्मनी लौट गईं जहां उन्होंने समाज में अपना अच्छा स्थान बनाया.

अपने किशोरवय काल में का अफेयर टस्कनी के राजकुमार से भी हुआ था. उनसे वे गर्भवती भी हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने जर्मनी के होहेनलोह परिवार के राजकुमार फ्रेड्रिक फ्रेंज को इस बात के लिए मना लिया कि वे राजकुमार से ही गर्भवती हुई थीं. दोनों की शादी 12 मई 1914 को हुई थी. उन्होंने तलाक लेकर एक बार फिर शादी की और लंदन में रहने लगीं जहां उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू किए जिसका इस्तेमाल जर्मनी की नई सरकार के लिए किया जा रहा था.

जब 1933 में हिटलर की सरकार आई तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एमआई 16 के दस्तावेज जारी कर इस बात की जानकारी दी थी कि फांसिसी खुफिया एजेंसी को स्टीफेन के कमरे से कुछ कागजात मिले हैं जिनमें इस बात की जानकारी थी कि उन्हें जर्मनी से किसी काम को पूरा करने के आदेश मिले थे. इस काम के लिए वर्तमान समय के अनुसार 13 मिलियन डॉलर की पेशकश की गई थी.

स्टेफनी को ब्रिटिश नेता रोथरमूर से आर्थिक मदद मिलती थी. वे कुछ ऐसे ब्रिटिश नेताओं में थे जो चाहते थे कि जर्मनी का समर्थन किया जाए. वे स्टेफनी को इस बात के लिए आर्थिक मदद दिया करते थे कि वे देश में जर्मनी के लिए समर्थन में बढ़ोतरी करवाएं. उन्हें इस बात की उम्मीद भी रहा करती थी कि वे एक दिन रोथरमूर को बड़े नाजी नेताओं से मुलाकात करवाएंगी. लेकिन जब 1939 में युद्ध की शुरुआत हो गई तो रोथरमूर ने उन्हें पैसे उपलब्ध कराना बंद कर दिया तो स्टेफनी ने उन पर केस कर दिया. हालांकि वे अपना केस हार गईं.

स्टेफनी उन अधिकारियों को जर्मनी का संदेश देने का काम करती थीं जिन्हें जर्मनी से सहानुभूति थी. उन्होंने कई ब्रिटिश अधिकारियों की मुलाकात नाजी नेताओं से करवाईं थीं. वे इस बात की पूरी कोशिश में थीं कि ब्रिटेन जर्मनी की नाजी सरकार के प्रति विरोधी रवैया न रखे. अपने काम में वे पूरी तरह सफल भी हो रही थीं. ऐसे भी बहुत सारे सुबूत मिलते हैं कि जब नाजियों ने ऑस्ट्रिया में बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दी तो कई लोगों की संपत्ति स्टेफनी को सौंप दी गई थी.

मार्च 1941 में उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया. यहां पर उनका अफेयर एक अमेरिकी आव्रजन अधिकारी मेजर लेमुएल बी शोफील्ड के साथ हुआ. यह अफेयर कुछ महीनों तक चला. उसी साल अक्टूबर में एफबीआई ने स्टेफनी को एक्सट्रीमली इंटेलीजेंट, डेंजर और क्लेवर बताया. एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि स्टेफनी अकेले दस हजार पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं. 1945 में परोल पर छोड़ दिया गया और वे अपने देश वापस लौट गईं.

स्वदेश वापस लौटने के बाद स्टेफनी ने फिर से अपने बड़े राजनीतिक संबंध बनाए. उनके अच्छे संबंध मीडिया वालों के साथ भी थे. उन्होंने एक मैगीन ज्वाइन भी की थी और बाद में बड़े लोगों के साक्षात्कार किया. स्टेफनी ने जिन बड़ी शख्सियतों के साक्षात्कार लिए उनमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी और लिंडन बी जॉनसन शामिल थे. 1972 में उनकी मौत स्ट्रिजरलैंड में हुई. उन्हें वहीं दफनाया भी गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

मैं मां हूं, मैं जानती हूं. एक मां का मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है तो वह उसको भी नहीं भूलती मरते दम तक. ख़ुदा के लिए आज मेरा पत्रकार भाइयों से भी सवाल है. बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, ठीक है. बहुत से क्लास लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. बड़-बड़े नाम हैं हमारी मीडिया के. बड़ी अच्छी लग रही थीं मुझे उनकी बातें कि आज कोई जश्न न हो. बड़ी ख़ुशी हुई कि हमारा मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है. लेकिन क्या हुआ? समाचार चैनलों पर ब्रेक के अंदर म्यूजिक के साथ विज्ञापन चलाए गए.

प्लीज़, मेरे सवालों का जवाब दे दो

क्या वह बच्चा याद है?

आप मुझे बताइए स्वात में एक बच्चा शहीद हुआ. एक स्कूल को उड़ाने के लिए जो दहशतगर्द आ रहा था उससे लिपट कर उसने अपनी जान दे दी. क्या उस बच्चे का नाम आप को याद है? मुझे भी नहीं याद है. क्यों नहीं याद. क्योंकि दोबारा उसका ज़िक्र नही किया गया. कभी किसी ने टीवी पर उसके लिए एक शब्द नहीं कहा. तो कैसे याद रहेगी. और जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा. आज का बच्चा जो तीन साल का है जब वह 6 साल का होगा तो उसे क्या पता चलेगा कि कभी कुछ अच्छे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद थे. ■

यासमीन मिर्ज़ा

आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ चंद सवाल रखना चाहती हूं, और आप लोगों से उनके जवाब चाहती हूं. क्योंकि आप लोग इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं. आप में मैं भी शामिल हूं. आज मुझे बड़ी उम्मीद थी जब सुबह मैंने यह खबर देखी और हर बड़े एंकर को यह बोलते सुना कि अब वक्त आ चुका है, जब हमें उठकर कुछ करना है. हमें कुछ तब्दीली लाने के बारे में सोचना है. अब हमें सचमुच कुछ करके दिखाना है. लेकिन अफ़सोस! बहुत अफ़सोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वही सारी पुरानी बातें ही टेलीविजन पर हो रही हैं. बेशक मेरा भी संबंध मीडिया के साथ है, लेकिन वही पुराने मौलाना, वही पुराने मुफ़्ती, वही पुराने पत्रकार बैठे हैं. वही बातें की जा रही हैं जो दहशतगर्दी मिलते-जुलते जितने भी वाक़यात पर की जाती हैं कि दहशतगर्दी का बदला लिया जाएगा, दहशतगर्दों को मिटा दिया जाएगा. मैं उन मौकों पर भी एक छोटा सा सवाल अपने दिल से किया करती थी. वही सवाल मैं आज आप लोगों से करना चाहती हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई तरक्कीपसंद लीडर आ भी जाए तो क्या उन माओं के बच्चे वापस आ जाएंगे, जो जा चुके हैं. हर वह घर जो इस दुख को सह रहा है क्या उसके लिए पाकिस्तान में किसी परिवर्तन से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए यह हमारा मीडिया उन नेताओं को क्यों दिखा रहा है जिनकी बातें हम रोजाना सुनते हैं. वह उन मांओं को क्यों नहीं दिखा रहा है जिनके कलेजे फटे हैं आज? सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग बर्दाशत नहीं कर पाएंगे? क्या हम अभी बर्दाशत कर पा रहे हैं? हम से वे चीज़ें छिपाई जा रही हैं. मैं कहती हूं कि आज अगर मीडिया वाले वह सबकुछ दिखा देते तो हमें किसी लीडर को आवाज देनें की जरूरत नहीं पड़ती, हम सब खुद सड़कों पर होते. हम खुद उनके गिरेबां पकड़ते. ये कौन होते हैं बच्चों को दहशतगर्दों के आगे डालने वाले? आप मुझे बताइए! जब वह मां सुबह उठ कर अपने बच्चे की आलमारी खोलेगी, वह मरते दम तक नहीं भूलेगी अपने बच्चे को. वह जब उसकी पसंदीदा डिश बनाएगी तो उस दिन वह रोएगी.

मैं मां हूं, मैं जानती हूं. एक मां का मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है तो वह उसको भी नहीं भूलती मरते दम तक. खुदा के लिए आज मेरा पत्रकार भाइयों से भी सवाल है. बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, ठीक है. बहुत से क्लास लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. बड़-बड़े नाम हैं हमारी मीडिया के. बड़ी अच्छी लग रही थीं मुझे उनकी बातें कि आज कोई जश्न न हो. बड़ी ख़ुशी हुई कि हमारा मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है. लेकिन क्या हुआ? समाचार चैनलों पर ब्रेक के अंदर म्यूजिक के साथ विज्ञापन चलाए गए. जबकि आप लोगों से जश्न मनाने के लिए या गाने बजाने के लिए मना कर रहे हैं. क्या आप अपने चैनल को विज्ञापन बंद करने पर मजबूर कर सकते हैं? जिन घरों के बच्चे गए हैं वो तो टीवी देख नहीं रहे हैं. न वो टीवी देख सकते हैं. यह हम लोग देख रहे हैं. और हम से वह सब चीज़ें छिपाई जा रहीं हैं कि आप लोग बर्दाशत नहीं कर पाएंगे. मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी एक भी घटना की तस्वीर पहले दिखाई गई होती तो यह घटना घटती ही नहीं. हम सोचते हैं कि बच्चों को कुछ उल्टा सीधा नहीं दिखाएंगे. लेकिन हमारे ही मुल्क में इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट मौजूद है जो बच्चों के लिए नहीं है. पाकिस्तान नंबर एक पर आता है, पूरी दुनिया में पोर्नोग्राफी देखने में. क्या वह सब चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी हैं? क्या वो बच्चे देख सकते हैं और ये नहीं देख सकते? मेरे ख्याल से आप अगर आज ये दिखाएं तो वे हमारे मां बाप की तरह गलतियां नहीं करेंगे. दोस्तों ये हमारे मां-बाप हैं जिन्होंने आज हमें इस हाल तक पहुंचाया है. किस तरह की हुकूमतें मेरे मुल्क में आती रहीं हैं, मुझे नहीं मालूम. मैंने तो बचपन से पाकिस्तान को ऐसे ही देखा है.

हम लोग बड़े-बड़े हीरो को रोजाना टीवी पर देखते हैं. लेकिन असल हीरो को हम नहीं जानते हैं और न ही हमारे बच्चे जानते हैं. हमें आप बताइए आज कितने बच्चे हैं जो निशाने हैदर लेने वाले फौजियों को जानते हैं? हम आठ फौजियों को जानते हैं क्योंकि हमने अपने कोर्स में उन्हें पढ़ा है. आठ से वे बारह हो गए लेकिन बाकी के नाम मुझे भी नहीं मालूम. मीडिया पर कभी दिखाया नहीं गया उनको, कभी वे बार-बार रिपीट नहीं हुए. हम अपने समय में ऐसे ड्रामे देखा करते थे जो राशीद मीनार से ताल्लुक रखते हों, मेजर अज़ीज़ भट्टी को दिखाया गया हो उसमें. क्या हम आंसूओं से नहीं रोते थे? आज तक हम उस दुख और दर्द को महसूस करते हैं लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता कि निशान-ए-हैदर है क्या चीज़? उन्हें ऑस्कर का पता होगा. नोबेल का पता होगा, लेकिन निशान ए हैदर नहीं पता, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया. इसके अलावा जब सरहद पर कोई जवान शहीद होता है तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया जाता.तनख्वाह तो हर नौकरी में मिलती है. क्या आपने कभी सोचा आर्मी के बड़े-बड़े लीडर के नाम तो आप जानते होंगे. और आज मैंने किसी के बयान में थोड़ी सी ताक़त देखी है तो वह हमारे डीजीआई थे आईएसपीआर के. इसीलिए मैं आर्मी की दिल से इज्जत करती हूं. नेवी के जवान कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, यह बात शायद ही किसी को पता हो. अमेरीका के दो टावर्स गिरे थे तो उसने दो मुल्क उड़ा दिए. उसे आप क्या कहेंगे? इसको आप गैरत नहीं कहेंगे. कितनी मांओं की गोद उजाड़ने के बाद आपकी गैरत जोश मारेगी? मेरा तो कहना है कि लोग उन दहशतगर्दों को उन मांओं के हवाले कर दें जिनके बच्चे हमले में शहीद हुए हैं. ताकि उनकी बोटी-बोटी नोची जा सके.

> **मेरी आपलोगों से इल्तजा है कि सबकुछ भूल जाएं सिर्फ ये याद रखें कि हमारे पाकिस्तान के सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन हैं. हमें उन दुश्मनों से इकट्ठे हो कर लड़ना है. हमें कोर्स में सिखाया जाता है कि एकता में बहुत ताकत है. लेकिन ये कोर्स बनाने वाले ही इस पर अमल नहीं करते. मेरा आपलोगों से सवाल है, ये सब कब खत्म होगा? एक फिरके के लोग फेसबुक पर कुछ लगाते हैं, दूसरे फिरके के लोग गालियां देते हैं. किसको दी जाती है वो गालियां.**

मैं यकीन से कहती हूं जिस किसी ने भी अपने की मौत को देखा हो वो बर्दाशत नहीं कर सकता. मेरा भी अपना मरा है लेकिन वो दुख मुझे कम लग रहा है. यहां तो मां ने सुबह बच्चे को तैयार कर के भेजा था. वो इंतजार अर रही थी कि वो दोपहर को आएगा. उससे पूछेगी कि उसके स्कूल में पेपर था, कैसा हुआ,

मैं आपलोगों के आगे हाथ जोडती हूं. आप सच्चे मुसलमान बन जाइए, हमारे नबी ने जो बोला है, उस पर अमल करें. मैं नहीं जानती किसी मुफ्ती, किसी मौलाना को. मैं उनकी शक्लें देख-देख कर तंग आ गई हूं. जो बच्चे मरे हैं वो शिया नहीं थे, वो सुन्नी नहीं थे. वो सिर्फ बच्चे थे. उन्हें तो दहशतगर्दी का मतलब भी नहीं पता. उन्हें ये भी नहीं पता कि जेहाद के नाम पर उनके साथ क्या किया जा रहा है? हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, जब मैं कहती हूं कि हमारे बचपन में लाइट नहीं जाती थी. वो हैरान होते हैं कि पाकिस्तान कभी ऐसा था. कौन सी पॉलिसी है पाकिस्तान की? मैं नहीं जानती? पाकिस्तान किसे खुश करना चाहता है? लेकिन आज अगर आप (मीडिया) उन बच्चों की लाशें दिखा देते तो शायद ये लोग अपनी नफरतें भूल जाते. उनको भी अपने बच्चे याद आ जाते.

मेरी आपलोगों से इल्तजा है कि सबकुछ भूल जाएं सिर्फ ये याद रखें कि हमारे पाकिस्तान के सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन हैं. हमें उन दुश्मनों से इकट्ठे हो कर लड़ना है. हमें कोर्स में सिखाया जाता है कि एकता में बहुत ताकत है. लेकिन ये कोर्स बनाने वाले ही इस पर अमल नहीं करते. मेरा आपलोगों से सवाल है, ये सब कब खत्म होगा? एक फिरके के लोग फेसबुक पर कुछ लगाते हैं, दूसरे फिरके के लोग गालियां देते हैं. किसको दी जाती है वो गालियां. औरत को, मां को. आज एक मां ही तड़प रही है. प्लीज छोटी-छोटी बातों पर लड़ना छोड दें. छोटे मसले को बड़ा और बड़े मसले को छोटा बना के पेश करते हैं.

आज मीडिया को बहुत बड़ी खबर मिली है. सब पुरजोश है. मीडिया के एंकर अपनी तकरीरें तैयार कर रहे हैं. सब को बोलना है. सबको मज़म्मत करना है. लेकिन, मैं इन चीजों को नहीं मानती. आज मीडिया का दिन था. आज उनलोगों का दिन था जिनके बच्चे मरे हैं. आज उनको टीवी पर लाया जाता, वो जिस हाल में भी थे. दिखाया जाता कि वो किस हाल में हैं. दिखाया जाता उनका गम. लोगों को होश आता कि वो हमारे भी बच्चे हो सकते थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसकी जगह वही लोग, वही अल्फाज. वही सब कुछ सुन-सुन के मेरे कान पक चुके हैं. मौलाना साहब बैठे हुए है आईपैड ले कर के. एक बंदा बैठा हुआ है फोन ले कर के. एक से बात हो रही है दूसरा बंदा मैसेज पढ़ रहा है. मैंने बहुत कोशिश की कि किसी चैनल पर मेरी लाइव कॉल मिल जाए. लेकिन नहीं. ना ही तो कोई चैनल मुझे इतना टाइम देता और न ही किसी चैनल में इतना हौसला है कि वो मेरी इतनी बातें सुनता. इसलिए मैं मजबूर हुई कि आज के दिन आपलोगों को जगाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करूं. मुझे नहीं पता मेरी बात किसी के दिल पर असर करेगी या नहीं. क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर औरतों को सिर्फ औरत होने की वजह से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती. लेकिन मैं औरत नहीं सिर्फ एक मां बन कर बात कर रही हूं. प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे दें. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाडे धोती लाए और काकासाहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, लेकिन माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं.

साई सद्‌गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

चौथी दुनिया ब्यूरो

हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि हमें अपनी मां अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके आदेशों का पूर्णत: पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है. बाबा के इन वचनों को हृदयपटल पर अंकित कर लो. इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता (गुरु) ही सच्चा पिता (सच्चा गुरु) है. दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपने गुरु का उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए.

आगे पढ़े इसी पर आधारित कथा.....

साई बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ श्रीमद्‌भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी. काकासाहेब इन ग्रंथों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधि लेने के उपरांत भी वह उसी प्रकार अध्ययन करते रहे. एक समय चौपाटी (मुंबई) में काकासाहेब प्रात:काल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे. माधवराव देशपांडे (शामा) और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे. ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे. उस समय 11वें स्कंध के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोर्त्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझायी थी. राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान भी किया था. पठन समाप्त होने पर काकासाहेब बहुत निराशा-पूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है. नाथ तो सिद्ध थे, लेकिन हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए कोई आशा ही नहीं है.

माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी. वह कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साई सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तब फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है. यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है, तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं. क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है. तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहां रह जाता है. परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काकासाहेब का समाधान न हुआ. वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही रहे. दरअसल, यह विचार उनके मस्तिष्क में बार-बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी.

एक महाशय, जिनका नाम आनंदराव पाखाडे था, माधवराव को ढूंढते-ढूंढते वहां आ पहुंचे. उस समय भागवत का पठन हो रहा था. श्री पाखाडे भी माधवराव के समीप जाकर बैठ गए और उनसे धीरे-धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे. वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे. इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा. अतएव काकासाहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है. कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वप्न दिया है, उसे उनसे ही सुनो. उसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है. सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काकासाहेब को. सभी के कहने पर श्री पाखाडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है. मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूं. पानी मेरी कमर तक है और अचानक जब मैंने ऊपर देखा, तो साईबाबा के श्री-दर्शन हुए. वे एक रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री-चरण जल के भीतर थे. यह दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ. इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा. मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री-चरणों पर गिरो. मैंने उत्तर दिया कि मैं भी यही करना चाहता हूं. परंतु उनके श्री-चरण तो जल के भीतर हैं. अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं. मैं तो निस्सहाय हूं. इन शब्दों को सुनकर शामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपाकर अपने चरण बाहर निकालिए. बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया. बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ. घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अब तुम्हारा कल्याण होगा. उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक ज़री के किनारों की धोती मेरे शामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा.

बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाडे धोती लाए और काकासाहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं. कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेशसूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया. काकासाहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता, तो वे काग़ज़ की दो पर्चियों पर स्वीकार-अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते थे और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था, उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे. इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही दो पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रख दिया और एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा. बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई, तो वह स्वीकारसूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी. इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काकासाहेब का संदेह भी दूर हो गया.■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए हैं? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

भारत न बरते ढ़िलाई

विदेशी आपूर्तिकर्ता कंपनियां भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु सहयोग के मार्ग में भारत के परमाणु उत्तर दायित्व कानून को सबसे बड़ा रुकावट मानती है, क्योंकि इस कानून के मुताबिक यदि किसी संरचनात्मक त्रुटि के कारण रिएक्टर में विस्फोट होता है, तो रिएक्टर आपूर्तिकर्ता कंपनी को उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसे मुआवजा देना होगा. जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के बाद भारत की आंखें खुल जानी चाहिए. गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी कारण दशकों से अपनी भूमि पर एक भी नया रिएक्टर स्थापित नहीं किया है. इस कानून में तनिक भी नर्मी भारत को बहुत भारी पड़ेगी.

-राजकिशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

फिल ह्यूज को श्रद्धांजली

कौन जानता था की क्रिकेट का एक बाउंसर भी दुनिया में बहुत चर्चित हो जाएगा और किसी खिलाड़ी के मौत का कारण बना जएगा. आस्ट्रेलिया का उभरता क्रिकेट का एक सितारा बाउंसर का शिकार हो गया. फिल ह्यूज की मौत के बाद क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों में शोक की लहर दौड़ गई और उनकी याद में सभी की आंखें नम हो गई. बहुत से खिलाड़ी बाउंसर एक ओवर में दो-दो बाउंसर फेका करते थे और बहुत से खिलाड़ी बाउंसर नहीं खेल पाते. भारत की बात करें तो मोहिन्दर अमरनाथ बाउंसर नहीं खेल पाते थे और कुछ खिलाड़ियों को बाउंसर खेलने में अच्छा लगता था. सुनील गावस्कर ने तो बाउंसर के विरोध में आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ बिना हेलमेट के खेला था और कई शतक लगाए थे. फिल फ्यूज तो कोई विश्व रिकार्ड नहीं बना पाए, लेकिन उनका नाम क्रिकेट की दुनिया में अमर रहेगा. इसलिए सभी खिलाड़ियों को आत्मरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर ही खेलना चाहिए.

-विनोद तिवारी, *फारबिसगंज, बिहार.*

देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़

कवर स्टोरी-यूआईडी कार्ड खतरनाक है, देश में कानून का राज खत्म हो गया है(15 दिसंबर-21 दिसंबर 2014) पढ़ा. तथ्यपरक है. मनीष कुमार से सहमत हूं कि यूआईडी कार्ड खतरनाक है. मनीष कुमार ने कहा कि आधार कार्ड के जरिए हमारे देश के नागरिकों की जानकारियां विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास जा रही है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. इसलिए आधार कार्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए. पहले यही भाजपा सरकार में नहीं थी, तो आधार कार्ड का विरोध कर रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि एनडीए की सरकार के आते ही इसे हर जगह जरूरी बनाया जा रहा है. यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. मनीष कुमार ने सही कहा है कि अब समय आ गया है कि सरकार को आधार कार्ड पर विचार करना चाहिए.

-अनुराधा सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

काबिले तारीफ है

चौथी दुनिया समाचार पत्र (15 दिसंबर-21 दिसंबर 2014) का अंक पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. कवर स्टोरी के साथ संपादकीय पेज पर प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित हैं और नई जानकारी देने वाले हैं. संतोष भारतीय का द्वारा लिखा गया संपादकीय जब तोप मुकाबिल हो, संसद को देशद्रोह के कलंक से बचाइए, कमल मोरारका का आलेख अब वक्त काम करने का है, मेघनाथ देसाई का आलेख क्या भाजपा मुंबई को शंघाई बनाएगी और आलेख लाजवाब टीम और धारधार लेखन सभी आलेखों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. चौथी दुनिया समाचर पत्र को जब से मैं पढ़ रहा मुझे इस समाचार पत्र में कोई कमी नहीं मिली. इसके प्रत्येक अंक में नए विषयों पर और तथ्यों पर आधारित आलेख होते हैं.

-अंकुर त्रिपाठी, *बक्सर, बिहार.*

चकित रह गया

चौथी दुनिया सामाचार पत्र का मैं दो वर्ष से पाठक हूं. चौथी दुनिया की कवर स्टोरी से लेकर सभी आलेख नई-नई घटनाओं पर आधारित होते हैं, जो इसे सबसे अलग बनाता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र में हेल्थ पर प्रकाशित जानकारी बहुत अच्छी लगती है. चौथी दुनिया में सभी खबरें सही घटनाओं और तथ्यों पर आधारित होती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में एक औरत के हांथों मारा गया था ओसामा और अपनी मां के नाम रेहाना का खत मेरी मौत के बाद मेरे अंग दान कर दीजिए पढ़ा दोनो बहुत अच्छे आलेख हैं. कवर स्टोरी-मोदी के लिए नई चुनौती जनता परिवार, मनीष कुमार का आलेख मोदी का आदर्श ग्राम, कमल मोरारका का आलेख एवं चौथी दुनिया के अंक(24 नवंबर-30 नवंबर 2014) में प्रकाशित सभी आलेख नई जानकारियों पर आधारित है. चौथी दुनिया एक नई जानाकरियों वाला और तथ्यों पर आधारित समाचार पत्र है.

-गौरव कुमार यादव, *समस्तीपुर, बिहार.*

कब आएगा कालाधन

चौथी दुनिया समाचार पत्र (08 दिसंबर-14 दिसंबर 2014) का अंक पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित सभी आलेख विचारोत्तेजक है. इस अंक में कालाधान पर प्रकाशित आलेख पढ़ा जो काफी अच्छा है. यह बिल्कुल सही है कि समय से ज्यादा नीति महत्वपूर्ण है. सरकार कितने समय में कालाधन लाती है यह अलग बात है, लेकिन उसकी नीति सही हो तभी कालाधन देश में आ पाएगा. अगर एनडीए सरकार भी यूपीए की नीति कालाधन पर अपनाती है, तो कालाधन आना से रहा.

-रविशंकर मौर्या, *ग्वालियर, मध्यप्रदेश.*

कहानी

सद्‌भावना और प्रेम

एक राजा ने एक दिन स्वप्न देखा कि कोई परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि बेटा! कल रात को तुझे एक विषैला सर्प काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जायेगी. उक्त पेड़ पर रहता है, वह पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए तुम्हें काटेगा. राजा स्वप्न की बात पर विचार करने लगा. वह विचार करने लगा कि अब आत्म-रक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सोचते- सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है. उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया. राजा ने पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शय्या तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगन्धित जलों का छिड़काव करवाया और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न न करे. रात को ठीक बारह बजे सर्प अपनी बांबी में से फुफकारता हुआ निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया. वह जैसे- जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख-देखकर आनन्दित होता गया. कोमल बिछौने पर लेटता हुआ मनभावनी सुगन्ध का रसास्वादन करता हुआ आगे बढ़ता था. क्रोध के स्थान पर सन्तोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे.

राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, लेकिन उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते. यह देखकर सर्प के मन में स्नेह उमड़ आया. सद्‌व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मन्त्र-मुग्ध कर लिया था. हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न उससे हल न हो सका. राजा के पलंग तक जाने तक सर्प का निश्चय पूर्ण रूप से बदल गया. सर्प के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर रहा था. नियत समय से कुछ विलम्ब में वह पहुंचा. सर्प ने राजा से कहा-हे राजन्! मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, लेकिन तुम्हारे सौजन्य और सद्‌व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया. अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र हूं. मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं. लो इसे अपने पास रखो. मणि राजा के सामने रखकर सर्प उलटे पांव अपने घर वापस चला गया.■

शिक्षा-सद्‌भाव और प्रेम से दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

मगन दास की तबियत आज तरह-तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट-सी हो रही थी. जब कोई नौकर आता, तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची. शाम के वक्त जनानखाने में जोर-शोर से गाने की आवाज़ ने बहू के पहुंचने की सूचना दी. सुहाग की सुहानी रात थी. दस बज चुके थे. खुले हुए हवादार सहन में वह चांदनी छिटकी हुई थी.

हाय हुसैन, हम न हुए!

अनंत विजय

छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन दिनों का रायपुर साहित्य महोत्सव आयोजित किया था. यह एक सरकारी आयोजन था. इसमें हिंदी के वरिष्ठ कवियों एवं लेखकों की भागीदारी रही. इसमें विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना, अशोक वाजपेयी, मैत्रेयी पुष्पा से लेकर हृषिकेश सुलभ जैसे दिग्गज लेखक शामिल हुए. पत्रकारिता के अच्युतानंद मिश्र एवं रमेश नैयर जैसे वरिष्ठ स्तंभों ने भी इस साहित्योत्सव में शिरकत की. साहित्य के समकालीन कथाकारों-कवियों ने भी अपनी उपस्थिति से इस साहित्योत्सव को जीवंत बना दिया. इन दिनों साहित्य में जिस एक प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा है, वह यह है कि सभी तरह के आयोजनों की समीक्षा फेसबुक पर होती है. लिहाजा, रायपुर साहित्य महोत्सव के आयोजन के पहले, उसके दौरान और उसके बाद उसे लेकर पक्ष-विपक्ष में विमर्श प्रारंभ हो गया. विरोध में यह तर्क दिया जाने लगा कि चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के ख़िलाफ़ सख्ती से पेश आ रही है, लिहाजा उसके आयोजन में जनपक्षधरता की पैरोकारी और वामदलों में अपनी आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वालों को शिरकत नहीं करनी चाहिए. जैसा कि आम तौर पर फेसबुक पर होता है कि वहां विमर्श के दौरान हर तरह की मर्यादा का उल्लंघन होता है. इस बार भी हुआ. हिंदी के वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल और कोलकाता के लेखक जगदीश्वर चतुर्वेदी के बीच हुई तीखी बहस गाली-गलौच तक पहुंच गई. व्यक्तिगत हमले हुए. इसके अलावा साहित्य जगत में जुगनू की तरह चमकने वाले कुछ लेखक, कवि एवं कुछ छद्म लेखक भी फेसबुक पर रायपुर साहित्य महोत्सव में शामिल होने वाले लेखकों को घेरने में जुटे. वहां मैत्रेयी पुष्पा और अन्य लोगों को सफाई देनी पड़ी. फेसबुक के विमर्श की अराजकता एक बार फिर उजागर हो गई. लोगों ने एक-दूसरे पर लाभ-लोभ लेने का सस्ता और घटिया आरोप जड़ा.

दरअसल, रायपुर साहित्य महोत्सव का विरोध करने वालों में ज़्यादातर लोग हाय हुसैन, हम न हुए सिंड्रोम के शिकार नज़र आए. ज़्यादातर फेसबुकिया साहित्यकारों की पीड़ा यह थी कि उन्हें वहां आमंत्रित क्यों नहीं किया गया. उनकी यह पीड़ा बार-बार झलक रही थी. हिंदी के एक कवि ने अपने न बुलाने के दर्द को अपनी कविता के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया. छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाने वाले लेखकों को यह नहीं मालूम था कि साहित्य महोत्सव के दौरान मुक्तिबोध की कविता-अंधेरे में की अर्द्धशती पूरे होने पर एक पूरा का पूरा सत्र रखा गया था, जिसमें इस कविता और मुक्तिबोध की जनपक्षधरता पर जमकर विमर्श हुआ. कवि नरेश सक्सेना, प्रभात त्रिपाठी एवं लीलाधर मंडलोई ने इस कविता को नए सिरे से व्याख्यायित करने का उपक्रम किया था. नरेश सक्सेना ने तो इस कविता पर बोलते हुए एक नई स्थापना दी. उनका कहना था कि अंधेर में के प्रकाशन के बाद कविता की धुरी उत्तर प्रदेश से हटकर मध्य प्रदेश पहुंच गई. उन्होंने अपनी इस स्थापना के पीछे कवियों की पूरी सूची गिनाई. उनका तर्क था कि अंधेर में की ताकत ने कवियों को ताकतवर बनाया. विरोध करने वालों को यह तक नहीं मालूम कि एक सत्र-प्रतिरोध का साहित्य में हिंदी की वरिष्ठ लेखिका रमणिका गुप्ता ने तो आदिवासियों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को कठघरे में खड़ा कर दिया था. इस साहित्य महोत्सव में इस तरह के कई सत्र आयोजित किए गए, जिनमें सत्ता पर जमकर हमले हुए. दूसरा आरोप यह लगाया गया कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भागीदारी रही.

दरअसल, मार्क्स के अंधानुयायियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे संघ से बुरी तरह से आक्रांत रहते हैं. उन्हें जब किसी भी शख्स या आयोजन को डिफेम करना होता है, तो वे संघ का सहारा लेते हैं. वामपंथियों का संघ पर अफवाह तंत्र में मजबूत होने का आरोप रहता है, लेकिन वामपंथियों से बेहतर अफवाह तंत्र देश में किसी का नहीं है, क्योंकि वे अफवाह उड़ाने और उसे वैधता प्रदान करने के लिए विचारधारा का जमकर इस्तेमाल करते हैं और हर चीज को जनपक्षधरता से जोड़ देते हैं. इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं भी संघ का कोई पदाधिकारी नज़र नहीं आया. किसी भी सत्र और वक्ताओं को सुनने के बाद यह नहीं लगा कि संघ इस कार्यक्रम के पीछे है. साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति को इस तरह के आयोजनों की सराहना करनी चाहिए. साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर सरकारों में अगर अनुराग का भाव पैदा होता है, तो यह एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आयोजन में जो धन लगता है, वह हम टैक्स देने वालों का ही है. जनपक्षधरता की बात करने वालों को जनता के पैसों पर होने वाले आयोजनों का विरोध करते देखकर मुझे सलमान खान की फिल्म का एक डायलॉग याद आता है-तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला.

दरअसल, हाल के दिनों में यह देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकारें साहित्य आयोजनों में रुचि लेने लगी हैं. अभी हाल में बिहार सरकार के कला-संस्कृति विभाग के सौजन्य से दो दिनों का भारतीय कविता समारोह आयोजित किया गया. इस कविता समारोह में हिंदी समेत गुजराती, मलयालम, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, ओडिया, काक, बरोत, मणिपुरी आदि कई भारतीय भाषाओं के कवियों ने शिरकत की, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल में ही सम्मानित कवि केदारनाथ सिंह, हिंदी के वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आदि प्रमुख थे. यह जानकारी साझा करने का उद्देश्य सूचना देना मात्र नहीं है, बल्कि यह बताना है कि सरकारें साहित्य को लेकर सहृदय हो गई हैं. बिहार में हुए इस कविता समारोह में सरकार ने कवियों को हवाई यात्रा के अलावा पांच सितारा होटलों में रुकवाया, साथ ही पांच-दस मिनट के कविता पाठ के लिए पच्चीस हज़ार रुपये का मानदेय भी दिया. यह एक सुखद संकेत है कि हमारी सरकारें रचनाकारों को आर्थिक सम्मान भी देने लगी हैं. बिहार के भारतीय कविता समारोह की तुलना में रायपुर के साहित्य महोत्सव का फलक काफी बड़ा था. पटना में जहां काव्य पाठ हुआ, वहीं रायपुर में काव्य पाठ के अलावा साहित्य की विभिन्न विधाओं और पत्रकारिता पर कई सत्र आयोजित थे. रायपुर साहित्य महोत्सव के विज्ञापन और होर्डिंग्स पूरे देश भर में लगाए गए थे. इन दोनों समारोहों में एक बात जो समान दिखाई दे रही है, वह यह है कि यहां स्थानीय भाषा को भी प्रमुखता दी जा रही है. पटना के भारतीय कविता महोत्सव में अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा बिहार की लोकभाषाओं के कवि भी आमंत्रित किए गए थे. उन्होंने मैथिली, अंगिका, वज्जिका और मगही में काव्य पाठ किया. इसी तरह रायपुर में छत्तीसगढ़ी पर भी कई सत्र आयोजित हुए. ऐसे में अगर हम देखें, तो यह राज्य सरकारों का स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का एक उपक्रम है.

बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जबकि हिंदी में सरकारी आयोजनों या नेताओं के साथ मंच साझा करने पर लेखक एक-दूसरे की लानत-मलामत किया करते थे. नेताओं के साथ मंच साझा करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता था. हिंदी में इस तरह का वातावरण तैयार कर दिया गया था कि सरकारी आयोजनों को भी हेय दृष्टि से देखा जाता था. जब भारत भवन में अशोक वाजपेयी ने अर्जुन सिंह की सरपरस्ती में लेखकों को जोड़ने का काम शुरू किया था, तब भी इसी तरह का दुष्प्रचार किया गया था. वह दौर था, जब देश में विचारधारा वाले साहित्य और साहित्यकारों की तूती बोलती थी. उस दौर ने हिंदी साहित्य का जितना भला किया, उससे ज़्यादा उसका नुक़सान किया. इमरजेंसी के समर्थन के एवज में इंदिरा गांधी ने साहित्य-संस्कृति को वामपंथी विचारधारा वाले लेखकों के हवाले कर दिया. अब इन वामपंथी विचारकों ने इस तरह का ताना-बाना बुना कि सामान्य लेखकों को सरकार से दूर कर दिया. सरकार किसके पैसों पर चलती है. वह आम जनता का पैसा होता है. हमारे अपने पैसों पर आयोजित होने वाले समारोहों से लेखकों को काट देने का एक षड्यंत्र रचा गया. उसके तहत यह बात फैलाई गई कि सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले कवि-लेखक दरबारी हैं. जबकि उक्त विचारधारा के पोषक शीर्ष लेखक सरकारों से फ़ायदा लेते रहे, तमाम कमेटियों में नामित होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे. विचारधारा के प्रभाव के कम होने के बाद अब ये सारी बातें सामने आने लगी हैं. ये वे लोग हैं, जिनका साहित्यिक संस्थाओं पर हमेशा कब्जा रहता आया है, भले ही सरकार किसी भी दल की हो. हर सरकारी शिष्ट मंडल में कुछ नाम घूम-फिर कर आते-जाते रहे हैं. अब वक्त आ गया है कि सत्तर के दशक के बाद देश में जिस तरह से साहित्य-संस्कृति को लेकर खेल खेला गया, उस पर गंभीरता से विचार हो कि उस खेल से कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुक़सान. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

प्रेमचंद

त्रिया चरित्र

पिछली बार आपने पढ़ा कि मगन दास के वकील मित्र ने उसके घर का सारा हाल कह सुनाया और कहा कि बड़ी सेठानी समेत पूरा परिवार उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा है. वकील के जाने के बाद जब मगन दास ने सारी बातें रंभा को बताईं, तो वह कुछ निराश-सी हो गई. लेकिन, अगले ही पल उसका निश्छल प्रेम मगन दास के सामने आया. रंभा ने तय कर लिया था कि वह मगन दास की राह का रोड़ा नहीं बनेगी. उधर, मगन दास को रंभा का विछोह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था. आगे क्या हुआ? पढ़िए, इस अंतिम किस्त में...

सुबह हुई, तो मगन दास उठा और रंभा को पुकारने लगा. मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई. मगन दास को उस मकान के दरो-दीवार पर एक हसरत-सी छाई हुई मालूम हुई, जैसे घर की जान निकल गई हो. वह घबराया-सा उस जगह गया, जहां रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफ़सोस, आज चक्की एकदम निश्चल थी. फिर वह कुएं की तरफ़ गया, लेकिन ऐसा लगा कि कुएं ने उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया. वह बच्चों की तरह चीखता-रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया, जहां कल रात तक प्रेम का वास था, मगर उस वक्त शोक का घर बना हुआ था. उसने चारों तरफ़ निगाह दौड़ाई. रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी. एक पिटारी में वह कंगन रखा था, जो मगन दास ने उसे दिया था. बर्तन सब रखे हुए थे, साफ़-सुथरे. मगन दास सोचने लगा, रंभा, तूने कल रात कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी. क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था कि तू दिल्लगी कर रही है, वरना कलेजे में छिपा लेता. मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था. मुझे यकीन है, तू अब भी लौट आएगी. फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया. वे नाजुक अदाएं, मतवाली आंखें, भोली-भाली बातें, जीवनदायी मुस्कान. हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, लचक-लचक कर कुएं से पानी लाना, ये सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने फिरने लगीं.

मगन दास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं एवं दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ. नागपुर जाने का पक्का फ़ैसला हो गया. तकिये के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई, तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया. यह रंभा की चिट्ठी थी. प्यारे, मैं बहुत रो रही हूं, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना ज़रूरी है. तुम्हें जगाऊंगी, तो तुम जाने न दोगे. आह, कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं! किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है. मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी. मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है. मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं. मैं अपनी मुहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं! अब तुमसे जुदा होती हूं, मेरी सुध मत भूलना. मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी. क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा.

मगन दास को दिल्ली आए तीन महीने गुजर चुके हैं. इस बीच उसे सबसे बड़ा निजी अनुभव यह हुआ कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है. ड़ेढ साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार एवं सूझ-बूझ रखने वाला आदमी बन गया था. सागर घाट में कुछ दिन रहने से उसे रिआया की उन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था, जो कारिंदों एवं मुख्तारों की सख्तियों की बदौलत उसे उठानी पड़ती है. इससे उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद मिली और कर्मचारी दबी ज़ुबान से

उसकी शिकायत करते थे, मगर रिआया खुश थी. जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता, तो एक भोली-भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्यालों में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट की हरी-भरी झोंपड़ी और उस लड़की की मस्तियां आंखों के सामने आ जातीं. सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को मसोसने लगतीं. लेकिन, कभी-कभी खुद-बखुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ़ भी जा पहुंचता. उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर उसमें इंदिरा के लिए भी एक कोना निकल आया था. अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई. अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, शान है, तो यह उसका कुसूर नहीं. ये रईसजादों की आम कमजोरियां हैं, यही उनकी शिक्षा है. इन बदले हुए एवं संतुलित भावों के साथ जहां वह बेचैनी से रंभा की याद ताजा करता था, वहीं इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए भी तैयार था. उसके कई आत्मीय-जन अमीराना शान-शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने नागपुर गए हुए थे.

मगन दास की तबियत आज तरह-तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट-सी हो रही थी. जब कोई नौकर आता, तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची. शाम के वक्त जनानखाने में जोर-शोर से गाने की आवाज़ ने बहू के पहुंचने की सूचना दी. सुहाग की सुहानी रात थी. दस बज चुके थे. खुले हुए हवादार सहन में वह चांदनी छिटकी हुई थी, जिसमें नशा, आरजू और खिंचाव है. गमलों में खिले हुए गुलाब व चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज़्यादा गंभीर और खामोश नज़र आते थे. मगन दास इंदिरा से मिलने के लिए चला. उसके दिल में लालसाएं ज़रूर थीं, मगर एक पीड़ा भी थी. दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खाली. उसके दिल में बैठी रंभा शायद बार-बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. वह शयनकक्ष के दरवाजे पर पहुंचा, जिस पर रेशमी पर्दा पड़ा था. उसने पर्दा उठाकर देखा, अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी. हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवाय उसके बदन पर एक जेवर भी न था. वह मुस्कराती हुई उसकी तरफ़ बढ़ी. मगन दास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रम्भा! और फिर दोनों प्रेमावेश से लिपट गए. दिल में बैठी रंभा बाहर निकल आई थी.

साल भर गुजरने के वाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो! कुछ याद है, उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगन दास ने कहा, खूब याद है. वह आवाज़ भी कानों में गूंज रही है. मैं रंभा को भोली-भाली लड़की समझता था. यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है. मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूं. तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों? तुम्हारी रंभा है, तो क्या मेरा गनसिंह नहीं है. मैं अब भी उस पर मरती हूं. दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुंचे. वह झोंपड़ी, वह मुहब्बत का मंदिर हरियाली से लहलहा रहा था. चंपा मालिन उन्हें वहां मिली. गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए. रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती. फिर चक्की पीसती और गाती. गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलातीं. हां, इतना ज़रूर कहतीं कि उसका रंग कैसा निखर आया है, हाथ-पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं, किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर वही स्वभाव, वही मीठी बोली, वही हंसमुख चेहरा. इस तरह एक हफ्ते उस सरल एवं पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए. अब दस साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोंपड़ी के नसीब जागते हैं. वह मुहब्बत की दीवार अभी तक दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कविता

अच्छे दिन

यदि हम इस सोच में रहें
कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद
एक सीप के मुंह में गिरे
और मोती बन जाए
तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी,
यदि हम यह सोचें कि
शासन-प्रशासन और कोई अन्य
अच्छे दिनों का पिटारा
चुपचाप हमारी जेब या
झोली में डाल दे
तो यह हमारी दूसरी बड़ी भूल होगी,
अच्छे दिन तो लाए जाते हैं.
और, इसके लिए देश के
जन-जन को
करना होगा एक महायज्ञ
जिसमें देनी होंगी आहुतियां
समर्पण की, सहयोग की
सकारात्मक सोच की, ठोस संगठन
की
ईमानदारी की, कर्मठता की
धर्मनिरपेक्षता की, भेदभाव रहित
समाज की
सरकार के साथ भागीदारी की
अनेकता में एकता की,
ताकि भारत बने स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त
तो निश्चित ही अच्छे दिन आएंगे
झमाझम आएंगे,
सड़क से संसद तक आएंगे.

-एलडी तिवारी ललित

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

यह माइक्रोमैक्स का टैब पी 470 7इंच की टीएफटी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आता है. इस टैबलेट की स्क्रीन 1024 गुणा 600 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इस टैबलेट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय वर्जन (एंड्रॉइड किटकैट 4.4.2) दिया गया है. माइक्रोमैक्स का ये टैबलेट डुअल कोर (दो लेयर वाला प्रोसेसर जिसमें आम प्रोसेसर से दो गुना पावर होता है) मीडियाटेक एमटी8312 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 1जीबी रैम दी गई है. कनेक्टिविटी के मामले में इसमें वॉइस कॉलिंग, वाई-फाई, ब्लूटुथ 2.1 और 3जी की सुविधा है.

पलक झपकते ही एक शहर से दूसरे शहर

इसे आप अंतरिक्ष यान कहें, कार कहें या जेट फाइटर. इन सबका मिला-जुला रूप है ब्लडहाउंड सुपरसोनिक कार, जिसकी रफ्तार के बारे में आप सुनते ही चौंक जाएंगे. इसकी स्पीड दुनिया के सबसे तेज विमान कॉनकॉर्ड की रफ्तार से बस कुछ ही कम है. अगर सब कुछ इंजीनियरों की योजना के अनुसार चला तो नई पीढ़ी की इस कॉनकॉर्ड कार की स्पीड 1000 मील होगी यानी लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा. ब्लडहाउंड प्रॉजेक्ट के चीफ इंजीनियर मार्क चैपमैन कहते हैं कि पहला थ्रस्ट एसएससी इंजन कार को 763 मील प्रति घंटे की रफ्तार देने में ही सक्षम था. ब्लडहाउंड एसएससी में एक-दो नहीं बल्कि तीन इंजन हैं. पहले दो इंजन कंबाइंड हैं, तीसरा इंजन रेसिंग कार की तरह का है. जो कार को रॉकेट जैसी गति देता है. ब्लडहाउंड एसएससी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने के लक्ष्य से तैयार की जा रही है. इसकी खूबियों की बात करें तो कार में ड्राइवर के बैठने की जगह अंतरिक्ष, एरोनॉटिकल और फॉर्मूला वन इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन से तैयार की गई है. अब तक की तेज रफ्तार कारों में तरल प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है, जबकि ब्लडहाउंड में ठोस रबर ईंधन का इस्तेमाल होगा. इसकी सभी मशीनों को बनाने के लिए कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया है. चेसिस में टाइटेनिय और एल्यूमीनियम की छड़ों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. एल्यूमीनियम के ऑक्साइड की परत इतनी मोटी होगी कि इसमें किसी तरह की जंग नहीं लगेगी. इंजन की थरथराहट कॉकपिट तक न पहुंचे, इसके लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. अंदर बैठे ड्राइवर को अहसास ही नहीं होगा कि कार का जेट इंजन कितना शोर कर रहा है. लेकिन शुरुआत में इंजन के शोर को लेकर कुछ परेशानी आ सकती है. इसके लिए ड्राइवर खास तरह के हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे. ■

गूगल नेक्सस 9 लॉन्च

गूगल ने अपने लोकप्रिय नेक्सस 9 टैबलेट भारत में लॉन्च कर दिया है, नेक्सस 9 की स्क्रीन 8.9 इंच की है और यह 64 बिट क्वॉड कोर एनवीडिया टेग्रा के1 प्रोसेसर से लैस है. यह एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला पहला टैबलेट है. इसमें

यह एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला पहला टैबलेट है. इसमें 2 जीबी की रैम लगी है. टैबलेट में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 1.6 मगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है. इसकी स्क्रीन 8.9 इंच की है, जो 2048 गुणा 1536 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है.

2 जीबी की रैम लगी है. टैबलेट में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 1.6 मगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है. इसकी स्क्रीन 8.9 इंच की है, जो 2048 गुणा 1536 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इसमें मेमोरी 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज देती है, 32 जीबी एक्सपेंडेबल है. इसकी बैटरी 6,700 एमएएच की है और एक बार चार्ज होने पर साढ़े नौ घंटे चलती है. इसकी कीमत 28,900 रुपये है. ■

एलजी का आर पार दिखने वाला स्मार्टफोन एफएक्सओ

कोरिया की जानी-मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलजी ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो आर-पार दिखने वाला(पारदर्शी) है. यह कंपनी का पहला फायर फॉक्स ऑपरेटिव सिस्टम वाला स्मार्टफोन है. यह फोन मोजिला और ऑपरेटर केडीडीआई के सहयोग से उतारा गया है. एलजी एफएक्सओ की स्क्रीन 4.7 इंच की है, जो हाई डेफिनेशन आईपीएस डिस्पले है. इसकी रैम 1.5जीबी की है और 16 जीबी का इंटरनल स्टोरेज है. इसमें एलईडी फैलश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. इसमें अन्य फीचर-4जी, एलटीई, 3जी, वाई-फाई, ब्लूटुथ, जीपीएस, एनएफसी उपलब्ध है. इसकी बैटरी 2370 एमएएच की है. इसकी कीमत लगभग 26,300 रुपये है. ■

25 लाख रुपये की सुपर नैनो

टाटा मोटर्स की सस्ती कार नैनो का जेए मोटर स्पोर्ट की ओर से एक नया संस्करण जल्द आने वाला है, जो बिल्कुल अनूठी होगी और बहुत ताकतवर भी. जेए मोटर स्पोर्ट ने इसके लिए कार के इंजन पर काफी ध्यान दिया है. इसका 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन ऐसा होगा जो 230 बीएचपी की ताकत पैदा कर सकेगा. यह सिक्स स्पीड गियरबॉक्स से लैस होगा. इंजन की इस ताकत से यह छोटी कार 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी. इस कार में बोल्ट ऑन रॉल केज और बेहतरीन सस्पेंशन के साथ ही सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक होंगे. इस कार की बाहरी बॉडी में भी बदलाव किए गए हैं. तेज रफ्तार के लिए इसे ऐयरो डायनेमिक डिजाइन का बनाया गया है. इसके टायर भी खास होंगे. देखने में यह किसी रेसिंग कार की तरह लगेगी. यह कार 2015 तक तैयार हो जाएगी और इसकी कीमत 25 लाख रुपये होगी. ■

माइक्रोमैक्स का 3जी वॉइस कॉलिंग टैबलेट

माइक्रोमैक्स ने नया 3जी वॉइस कॉलिंग टैबलेट कैनवास टैब पी470 लॉन्च किया है. माइक्रोमैक्स कैनवास टैब पी407 सिल्वर और ग्रे रंग में उपलब्ध है. इसकी खास बात यह है कि इस टैबलेट में 21 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट है. इनमें हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मल्यालम, तमिल और कन्नड़ शामिल हैं. माइक्रोमैक्स का टैब पी 470 7इंच की टीएफटी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आता है. इस टैबलेट की स्क्रीन 1024 गुणा 600 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इस टैबलेट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय वर्जन (एंड्रॉइड किटकैट 4.4.2) दिया गया है. माइक्रोमैक्स का ये टैबलेट डुअल कोर (दो लेयर वाला प्रोसेसर जिसमें आम प्रोसेसर से दो गुना पावर होता है) मीडियाटेक एमटी8312 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 1जीबी रैम दी गई है. कनेक्टिविटी के मामले में इसमें वॉइस कॉलिंग, वाई-फाई, ब्लूटूथ 2.1 और 3जी की सुविधा है. इसमें 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और वीडियो कॉलिंग के लिए 0.3 मेगापिक्सल (वीजी) फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इसमें 8जीबी की इंटरनल मेमोरी है. जिसे कार्ड की मदद से 32जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी बैटरी 3200 एमएएच की है, जो 158 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देती है. ■

बेहद सस्ता खुद का होम सिक्युरिटी सिस्टम

आपराधिक घटनाओं के कारण घरों की सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है. कुछ जरूरी गैजेट्स और सॉफ्टवेयर्स की मदद से सीसीटीवी सिक्युरिटी सिस्टम घर पर डिजाइन कर सकते हैं. इसके लिए किसी सिक्युरिटी कंपनी को ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है. घर पर 1000 रुपये से भी कम कीमत में सिक्युरिटी सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है. सिक्युरिटी सिस्टम की कीमत आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए कैमरा पर निर्भर करेगी. इस सिस्टम के लिए कैमक्लाउड के प्रीमियम अकाउंट की कीमत (468 रुपये से शुरू) और वेबकैमरा (300 रुपये से शुरू) पर पैसे खर्च करने होंगे.

1. किस-किस चीज की होगी जरूरत-

वेबकैमरा या आईपी कैमरा

कम्प्यूटर पर वीडियो चैटिंग के लिए वेबकैम का इस्तेमाल किया जाता है. आईपी कैमरा नाइट विजन के साथ आता है जिसे अलग से किसी भी कोने में फिट किया जा सकता है. 1-कैमक्लाउड सॉफ्टवेयर, 2-स्काइप अकाउंट, 3-लॉगमी इन आईडी (ऑप्शनल)

कम्प्यूटर पर अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन

कैमरा इंस्टॉल करना

सिक्युरिटी सिस्टम के लिए सबसे जरूरी चीज रहेगा कैमरा जहां साधारण वेबकैमरा की रेंज 300 रुपये से शुरू होती है, वहीं नाइट विजन कैमरा के लिए आपको 1000-5000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अलग-अलग कंपनियों के कैमरा उपलब्ध होते हैं. सिक्युरिटी के लिए बेहतर होगा कि मोशन डिटेक्ट करने वाला नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल किया जाए. हालांकि, इसके लिए यूजर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. अगर आप साधारण वेबकैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिजीफ्लिप या लॉजीटेक के वेबकैमरा कम कीमत में मिल सकते हैं. इसके अलावा, नाइट विजन कैमरा की बात करें तो हिकविजन(क्ळर्झीिळेप), इनेम(एपशा), सी मीडिया (उचशवळर) जैसी कंपनियों के कैमरा सस्ते दाम में मिल सकते हैं. कैमरा खरीद कर उसे उस जगह पर सेट करें जहां की निगरानी करनी है.

कैसे करें कैमरा सेट :

इसके लिए कैमरा के साथ आया इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ें.

पीसी से कैमरा कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर्स (कम्प्यूटर प्रोग्राम्स) की जरूरत होगी.

ड्राइवर की सीडी कैमरा के साथ आएगी जिसे कम्प्यूटर में इंस्टॉल करना होगा.

इसके बाद यूएसबी कनेक्टर की मदद से वेबकैमरा कम्प्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा.

कैम क्लाउड ऐप्लिकेशन की मदद से आपके सिक्युरिटी कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियोज क्लाउड सर्विस पर सेव किए जा सकते हैं. इसकी मदद से आप दूर बैठे भी कैमक्लाउड अकाउंट की मदद से वीडियोज देख सकते हैं.

सिक्युरिटी सिस्टम के लिए सबसे जरूरी चीज रहेगा कैमरा जहां साधारण वेबकैमरा की रेंज 300 रुपये से शुरू होती है, वहीं नाइट विजन कैमरा के लिए आपको 1000-5000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अलग-अलग कंपनियों के कैमरा उपलब्ध होते हैं. सिक्युरिटी के लिए बेहतर होगा कि मोशन डिटेक्ट करने वाला नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल किया जाए.

इसके लिए सबसे पहले कैमक्लाउड वेबसाइट पर आईडी बनानी होगी. यूजर्स प्रीमियम आईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए सबसे कम चार्ज 1 महीने का 468 रुपये होगा. इसके अलावा, अपनी जरूरत के हिसाब से प्रीमियम प्लान सिलेक्ट किया जा सकता है. अकाउंट बनाने के बाद कैमक्लाउड में आपको अपना कैमरा ऐड करने होगा.

कैसे करें ऐड :

कैमक्लाउड के कैमरा पेज पर जाकर अपना वेबकैम जोड़े.

इसके लिए आईपी ऐड्रेस और पोर्ट ऐड्रेस की जरूरत होगी जिसे सॉफ्टवेयर अपने आप आपके सिस्टम से सिलेक्ट कर लेगा.

आपने जीनियस आईपीकैम 350टीआर कैमरा का इस्तेमाल किया जिसे क्लाउडकैम सॉफ्टवेयर ने ऐड कर लिया.

अगर आप कुछ अलग सेटिंग्स करना चाहते हैं या एक से अधिक कैमरा जोड़ रहे हैं तो अपनी आईपी सेटिंग्स के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं.

कैमरा जोड़ने के बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही यूजर्स को सिस्टम पर वीडियो दिखने लगेंगे. गूगल प्ले पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और आईट्यून्स स्टोर पर आईओएस यूजर्स के लिए क्लाउडकैम का ऐप उपलब्ध है. इन ऐप्स की मदद से यूजर्स को स्मार्टफोन पर किसी भी मूवमेंट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ऐप की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा. अगर आप सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग किसी और जगह और कम्प्यूटर से देखना चाहते हैं तो उसके लिए स्काइप अकाउंट की जरूरत होगी. एक स्काइप अकाउंट होने के बाद भी यूजर्स को दूसरा अकाउंट बनाना होगा. इस नए स्काइप अकाउंट पर ऑटोमैटिक साइन इन का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. इससे जैसे ही कम्प्यूटर खुलेगा स्काइप अकाउंट लॉगइन हो जाएगा. इस अकाउंट की मदद से यूजर्स अपने वीडियोज को रिकॉर्ड और रीसेंड कर सकते हैं. अब एक ऐसी सर्विस का इस्तेमाल करना होगा जिससे यूजर्स किसी भी जगह से लॉगइन कर सकें. इसके लिए लॉगमीइन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस सर्विस से अपने कम्प्यूटर की फाइल्स किसी और कम्प्यूटरपर देखी जा सकती हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

धोनीगिरी के दस साल

भारतीय क्रिकेट जगत के असाधारण और अद्भुत शख्सियतों में अपना नाम शुमार करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक दशक पूरे कर लिये हैं . दस साल पहले 23 साल की उम्र में झारखंड से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छा जाने के लिये कदम बढ़ाया. इसके बाद धोनी ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गये. बतौर कप्तान भारत को टी-20 और एकदिवसीय विश्वकप दिलाकर धोनी ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया. दस साल के करियर में धोनी ने नाम, शोहरत, पैसा और वह सब कुछ कमाया जो एक खिलाड़ी पा सकता है. एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि देश के छोटे शहरों के खिलाड़ियों के लिए हर जगह दरवाजे खुल गये. धोनी ने अपनी सफलता से यह बात साबित की कि छोटे शहर के खिलाड़ी भी बड़े कारनामे कर सकते हैं बस उन्हें एक अदद मौके की तलाश होती है.

नवीन चौहान

दस साल पहले 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में मजबूत कद काठी और लंबे बालों वाला एक लड़का टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने उतरा और बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गया. महेंद्र सिंह धोनी नाम के इस खिलाड़ी को जिस वक्त भारतीय टीम में जगह दी गई थी, तब भारतीय टीम को एक ऐसे विकेटकीपर की तलाश थी जो एक अच्छा बल्लेबाज़ भी हो. क्योंकि उस दौर में भारतीय टीम कई मैचों में करीबी हार मिली थी जिन्हें निचले क्रम की मजबूती की वजह से जीता जा सकता था. उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह खिलाड़ी आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह बदल देगा. आज दस साल बाद महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है. बतौर कप्तान धोनी ने भारतीय टीम को सफलता के शिखर पर ले गए. आज विश्व में एकदिवसीय और टी-20 मैचों में उनके जैसा कोई फिनिशर नहीं हैं.

धोनी के बल्ले की पहली बार चमक साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में 123 गेंदों पर 148 रनों की शतकीय पारी के दौरान दिखाई पड़ी थी. इस मैच में भारत को 58 रनों से जीत हासिल हुई थी. इसके बाद धोनी का बल्ले ने साल 2005 में ही श्रीलंका खिलाफ जयपुर में आग उगली. धोनी ने उस मैच में 145 गेंदों में 183 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके बाद धोनी की पहचान विकेटकीपर से बढ़कर एक विशुद्ध बल्लेबाज की हो गई जो लंबे-लंबे छक्के मारता है. धोनी के टीम में आने से भारतीय टीम की सालों पुरानी विकेटकीपर -बल्लेबाज की खोज खत्म हो गई. नयन मोंगिया के बाद न जाने कितने विकेटकीपर टीम में आये और गये. लेकिन धोनी के आने के बाद भारतीय टीम ज्यादा संतुलित नज़र आ ने लगी थी.

राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया को साल 2007 में वेस्टइंडीज में खेले गए एकदिवसीय विश्वकप में पहले ही दौर के बाद बाहर होना पड़ा था. विश्वकप में हार की निराशा की वजह से सचिन, सौरव और राहुल जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले टी-20 विश्वकप से दूरी बना ली थी. चयनकर्ताओं के सामने कप्तान चुनने की समस्या आ खड़ी हुई. ऐसे में धोनी के हाथों में टी-20 विश्वकप के लिए कमान सौंपी गई. वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में धोनी को कप्तान बनाने का रिस्क चयनकर्ताओं ने लिया. धोनी ने अप्रत्याशित रूप से टीम इंडिया को पहला टी-20 विश्वकप विजेता बना दिया. इसके बाद साल 2007 में धोनी को एकदिवसीय टीम की भी कप्तानी सौंप दी गई. कुछ समय बाद इस बात का खुलासा हुआ कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की सलाह के बाद चयनकर्ताओं ने धोनी को कप्तान बनाने का निर्णय किया था. यह बात धोनी ने भी एक इंटरव्यू में स्वीकार की थी. सचिन ने धोनी की क्रिकेट की समझ को परख लिया था. इसके बाद 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में कप्तान अनिल कुंबले के संन्यास लेने के बाद धोनी को टेस्ट कप्तान बना दिया गया. धोनी ने जहां हाथ रखा वह सोने का हो गया या कहें कि भाग्य लगातार उनका साथ देता गया. किसी ने उन्हें कैप्टन विथ मिडास टच, किसी ने करिश्माई कप्तान तो किसी ने कैप्टन कूल कहा. धोनी हर बात को सही साबित करते रहे. धोनी एक तरह से सफलता का पैमाना बन गए. दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी धोनी के ठंडे दिमाग और क्रिकेटीय चपलता का कायल हो गया. उनकी तरकश में हर समय विपक्षी खेमे के लिए तीर तैयार रहता है. धोनी ने खुद को बड़े मैचों में साबित किया. जिस समय दूसरे खिलाड़ी दबाव में आ जाते थे. वहां धोनी ने ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए अधिकांश मैचों को आखिरी ओवर तक ले गए और भारत को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. धीरे-धीरे धोनी विश्व के नंबर एक एकदिवसीय बल्लेबाज़ बन गए. धोनी के कप्तान रहते भारतीय टीम ने लक्ष्य का पीछा करने में महारत हासिल कर ली. यह लंबे समय तक भारत की कमजोरी रही थी. आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय लेना धोनी की सबसे बड़ी खूबी है. वह फाइनल जैसे अहम मुक़ाबले में भी रिस्क लेने से नहीं चूकते हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी की पहली ही परीक्षा में टी-20 विश्वकप के फाइनल में आखिरी ओवर में गेंद जोगिंदर शर्मा के हाथों में देकर सबको चौंका दिया था. जोगिंदर ने मिसबाह-उल-हक़ को आउट करके भारत को पहला टी-20 विश्वकप विजेता बना दिया था. इसी तरह धोनी साल 2011 में विश्वकप के फाइनल में फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से पहले बल्लेबाजी करने उतरे और 91 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को 28 साल बाद विश्व चैंपियन बना दिया. धोनी के करियर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि केवल नेतृत्व क्षमता ही नहीं एक बल्लेबाज और विकेटकीपर के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर खुद को साबित किया है. विकेटकीपर के तौर पर उनके नाम अंतरराट्रीय क्रिकेट में 500 कैच भी दर्ज हैं. धोनी अब तक अपने करियर में 250 एकदिवसीय मैचों की 219 पारियों में 8192 रन, 89 टेस्ट मैचों की 142 पारियों में 4841 रन और 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 45 पारियों में 849 रन बना चुके हैं. एक दिवसीय मैचों में वह 9 शतक और 56 अर्धशतक लगा चुके हैं. 183 रन नाबाद उनका उच्चतम स्कोर है यह किसी भी भारतीय विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. टेस्ट मैचों में उनके नाम 6 शतक और 33 अर्धशतक हैं. टेस्ट मैचों में उनका सर्वाधिक स्कोर 224 रन है जो उन्होंने चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2013 में बनाया था.

> **आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय लेना धोनी की सबसे बड़ी खूबी है. वह फाइनल जैसे अहम मुक़ाबले में भी रिस्क लेने से नहीं चूकते हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी की पहली ही परीक्षा में टी-20 विश्वकप के फाइनल में आखिरी ओवर में गेंद जोगिंदर शर्मा के हाथों में देकर सबको चौंका दिया था. जोगिंदर ने मिसबाह-उल-हक़ को आउट करके भारत को पहला टी-20 विश्वकप विजेता बना दिया था.**

बतौर कप्तान धोनी के नाम कई विशिष्ट उपलब्धियां दर्ज हैं. धोनी विश्व के एक मात्र कप्तान हैं जो आईसीसी की तीनों 2007 में टी-20 विश्वकप, 2011 में आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस टॉफी जीत चुके हैं. वह भारत के अब तक के सबसे सफल कप्तान हैं. धोनी ने अब तक 166 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है और 93 मैचों में विजयी रहे हैं, जबकि उन्हें 59 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. 4 मैच टाई रहे हैं. बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में धोनी पांचवें पायदान पर हैं उनका जीत प्रतिशत 60.89 है. टेस्ट मैचों में धोनी ने बतौर 89 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है जिसमें 27 में जीत 18 में हार मिली जबकि 14 मैच ड्रा रहे हैं. घरेलू धरती पर धोनी ने टीम को टेस्ट मैचों में सफलता दिलवाई लेकिन विदेशी सरजमीं पर वह टीम को टेस्ट मैचों में जीत नहीं दिला सके. यह धोनी के एक दशक लंबे करियर का सबसे कमजोर पक्ष है. इसे लेकर उनकी आलोचना होती रही है कई बार तो आलोचकों ने उन्हें विदेशी धरती पर सबसे कमजोर भारतीय कप्तान भी बताया. बावजूद इसके टीम इंडिया आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर भी पहुंची. धोनी ने टीम इंडिया को नंबर वन एकदिवसीय टीम भी बनाया. आईपीएल में उनकी टीम, चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीम है. उन्होंने टीम को 2010 और 2011 में आईपीएल चैंपियन बनवाया. इसके अलावा 2010 और 2014 चैंपियंस लीग चैंपियन भी बनवाया. खेलों की दुनिया में भारतीय कप्तान जितने सफल हैं उसी तरह कमाई की दुनिया में भी धोनी ने अच्छे-अच्छों को पछाड़ दिया है. 25 साल तक देश का प्रतिनिध्त्व करने वाले सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी धोनी से कमाई के मामले में पिछड़ गए हैं. फोर्ब्स की सूची में धोनी सर्वाधिक कमाई करने वाले दुनिया के शीर्ष एथलीटों में शामिल हैं. उन्हें फोर्ब्स ने विश्व में 22 वें स्थान पर रखा है. उनकी सालाना कमाई खेल और प्रायोजनों से करीब तीन करोड़ डॉलर की है. धोनी देश के करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल भी हैं. टाइम मैग्जीन ने धोनी को साल 2011 में विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया था. धोनी क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर भी ध्यान दे रहे हैं. धोनी ने हॉकी लीग की रांची की टीम में, इंडियन सुपर लीग की टीम चेननईयन एफसी में हिस्सेदारी खरीदी है. साथ ही वह बाइक रेसिंग की एक टीम के भी मालिक हैं.

धोनी का नाम आईपीएल फिक्सिंग विवाद में आ रहा है. हालांकि इस मामले की जांच कर रही मुदगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दायर कर दी है. रिपोर्ट कोर्ट ने अभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है. लेकिन चेन्नई टीम के मलिकाना हक को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की है. टीम का मलिकाना हक़ रखने वाली इंडिया सीमेंट्स में धोनी वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्होंने मुदगल समिति के सामने दिए बयान में मुख्य आरोपी गुरुनाथ मयप्पन को मजह एक खेल प्रेमी बताया था, इस वजह से उनकी भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है.

इस विवाद से इतर धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है. वह सौरव गांगुली की परंपरा को बतौर कप्तान आगे ले गये हैं. अगले महीने ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में हो रहे विश्वकप में भारतीय टीम धोनी के नेतृत्व में खिताब बचाने के लिए उतर रही है. धोनी के नेतृत्व में आईसीसी की प्रतियोगिताओं में भारत के अब तक के बेमिसाल प्रदर्शन के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया विश्व खिताब बचाने की पुरजोर कोशिश करेगी. धोनी अनहोनी को होनी, बनाते हुए टीम इंडिया को एक बार फिर विश्व चैंपियन बना दें तो किसी को इस पर अचरज नहीं होना चाहिए.■

navinonline2013@gmail.com

डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी का फर्स्टलुक जारी

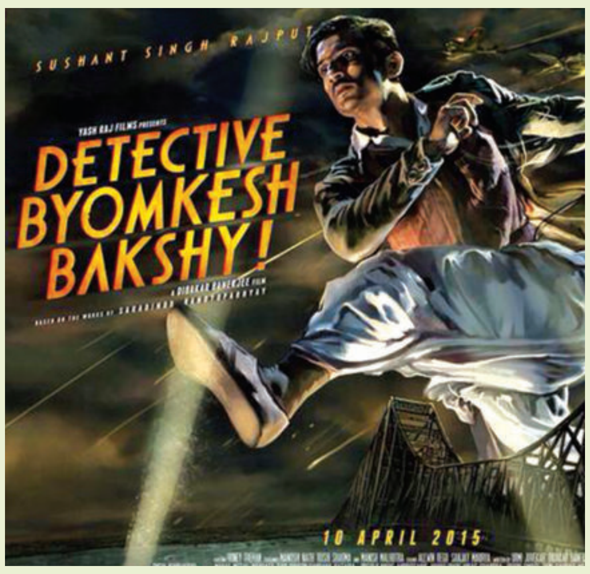

निर्माता-निर्देशक दिबाकर बैनर्जी की आगामी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है. पोस्टर को कोलकाता में लॉन्च किया गया. इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत मुख्य भूमिका में हैं जो व्योमकेश बख़्शी के किरदार में नज़र आयेंगे. इस फिल्म को पोस्टर को हाथ से पेंट किया गया है. इसे दिबाकर ने कोलकाता के पेंटर्स से तैयार करवाया है. फिल्म की कहानी 1940 के दशक के कोलकाता के एक जासूस की कहानी है. उस दौर का टच देने के लिए खास तौर पर प्रमोशन के लिए हाथ से पेंट किया गया पोस्टर तैयार करवाया गया है. हाथ से पेंट किए गए फिल्मी पोस्टरों का चलन अब लगभग खत्म हो चुका है. लेकिन इस पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के तौर-तरीकों को टच देने की डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है. पोस्टर में सुशांत सिंह का पहनावा भी अलग लग रहा है. सुशांत के अलावा इस फिल्म में स्वास्तिका मुखर्जी और आनंद तिवारी भी नजर आएंगे. सुशांत का हाल ही रिलीज हुई फिल्म पीके में अच्छा रोल है दर्शकों ने इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खासा पसंद भी किया है. इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर पहले एक सीरियल भी बन चुका है जिसे दर्शकों ने खासा पसंद भी किया था. यशराज बैनर के तले बन रही यह फिल्म पहले 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स-डे के दिन प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन इसी तारीख से ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट विश्वकप भी शुरू हो रहा है. इस वजह से फिल्म के रिलीज की तारीख को बढ़ा दिया गया है, अब यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी.■

सबसे अमीर सेलीब्रिटी बने सलमान

सलमान खान वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय सेलीब्रिटी बन गए हैं. फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार बॉलीवुड के दबंग सलमान ने इस वर्ष 244.5 करोड़ रुपये की कमाई की है. फोर्ब्स ने तीन साल पहले सबसे अमीर सेलीब्रिटी की रैंकिंग शुरु की थी. जब से यह रैंकिंग शुरू हुई है तब से सबसे धनी बॉलीवुड स्टार की रैंकिंग में शाहरुख खान पहले स्थान पर बने हुए थे. लेकिन इस बार शाहरुख दूसरे स्थान पर आ गये हैं. शाहरुख की इस साल की कमाई 202.4 करोड़ रुपये है. साथ ही सबसे लोकप्रिय अभिनेता की रैंकिंग में भी शाहरुख सातवें स्थान पर खिसक गये हैं. ओवर ऑल रैंकिंग में शाहरुख तीसरे पायदान पर पहुंच गये हैं. सलमान दोनों ही सूचियों में पहले नंबर पर बने हुए हैं. शाहरुख की इस साल हैप्पी न्यू इयर के रूप में केवल एक फिल्म रिलीज हुई है इस वजह से वह कमाई में सलमान से पिछड़ गये. सलमान की इस साल जय हो और किक जैसी फिल्में रिलीज हुईं. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. फोर्ब्स की सूची में तीसरे नंबर पर सबसे धनी सेलीब्रिटी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन रहे. 2014 में उनकी कमाई 197.75 करोड़ रही. लोकप्रियता के मामले में भी अमिताभ चौथे और ओवरऑल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहे.■

अनुष्का के हॉट फोटोशूट पर विराट भड़के

अनुष्का ने जीक्यू मैग्जीन के लिए काफी बोल्ड फोटोशूट कराया है, जीक्यू एक फैशन मैगजीन है, जिसके लिए तमाम अभिनेत्रियां फोटोशूट करवाती हैं. माना जा रहा है कि ये अनुष्का का अब तक का सबसे हॉट फोटोशूट है

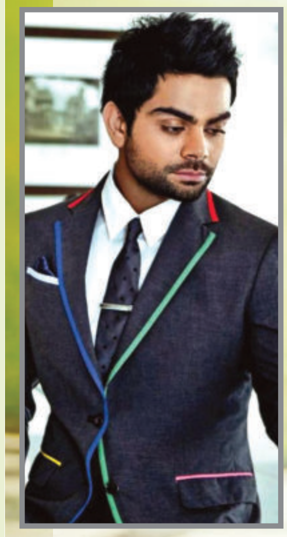

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को बॉयफ्रेंड विराट कोहली के गुस्से का शिकार होना पड़ा है. विराटे के गुस्से का कारण अनुष्का का एक हॉट फोटो शूट है. अनुष्का की ये फोटो विराट को पसंद नहीं आई. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से फोन कर अनुष्का की फटकार लगाई. अनुष्का ने जीक्यू मैग्जीन के लिए काफी बोल्ड फोटोशूट कराया है, जीक्यू एक फैशन मैगजीन है, जिसके लिए तमाम अभिनेत्रियां फोटोशूट करवाती हैं. माना जा रहा है कि ये अनुष्का का अब तक का सबसे हॉट फोटोशूट है, लेकिन अनुष्का का बोल्ड अंदाज देखकर विराट आग बूबला हो गए. विराट और अनुष्का की लव स्टोरी अभी-अभी परवान चढ़ी है. ऐसे में उनका ये कदम दोनों के बीच के रिश्ते के लिए घातक हो सकता है. विराट ने हाल ही में फिल्म पीके में अनुष्का के काम की तारीफ की थी.■

क्या ऑस्कर फिर भारत आयेगा ?

डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलिनेयर के लिए दो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकर ए आर रहमान एक बार फिर अकादमी पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो गए हैं. फिल्मकार गिरीश मलिक की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म जल ऑस्कर की दो श्रेणियों, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट ओरिजनल स्कोर, के लिए नामांकित की गई है. 87 वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए ओरिजनल स्कोर श्रेणी में संभावित 114 लोगों की सूची में रहमान का नाम भी शामिल है. यदि उनका नाम अंतिम पांच में शामिल हो जाता है तो यह रहमान ऑस्कर की दौड़ के अंतिम दौर में शामिल होने का तीसरा मौका होगा. इस पुरस्कार के लिए अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा जारी सूची में रहमान की मिलियन डॉलर आर्म, द हंड्रेड फीट जर्नी और भारतीय फिल्म कोच्चादैयां भी शामिल है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मैं अंग प्रदर्शन के लिए तैयार हूं: राखी सावंत

अपने बड़बोलेपन की वजह से अकसर विवादों में रहने वाली अभिनेत्री राखी सावंत ने कहा है कि बतौर कलाकार उनकी कोई हद नहीं है और वो अंग प्रदर्शन के लिए तैयार हैं. राखी आजकल अपनी फिल्म मुंबई कांट डांस साला के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इस दौरान राखी ने एक खुलासा किया और बताया कि मुझे दो सालों से काम नहीं मिल रहा था. इंडस्ट्री में बने रहना आसान नहीं है, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूं, इसलिए मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं आज जहां भी हूं, अपनी मेहनत से हूं. मैं खुद को सीमित नहीं कर सकती. मेरी कोई सीमायें नहीं हैं मैं एक्सपोज करने के लिए तैयार हूं. सचिंद्र शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म मुंबई कांट डांस साला में राखी बेहद अहम किरदार में नज़र आएंगी. राखी ने कहा कि फिल्म में मेरा किरदार बहुत ही दमदार और अहम है. फिल्म में मेरा नेगेटिव शेड है. मैंने इससे पहले इस तरह की भूमिका नहीं निभायी है. मुझे फिल्म की कहानी भी बहुत पसंद आई. ■

100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई पीके

आमिर खान और राजकुमार हीरानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म पीके ने रिलीज के दिन(19 दिसंबर) 26.63 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन ओपनिंग की. इसके अगले दिन फिल्म ने 29 करोड़ का कारोबार किया. तीसरे दिन फिल्म ने 33 करोड़ रुपये की कमाई की. चौथे दिन फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई. पीके को क्रिसमस की छुट्टियों का पूरा फायदा मिला. अगले हफ्ते भी कोई फिल्म रिलीज नहीं होने की वजह से भी पीके को फायदा मिला. फिल्म के रिलीज होने से पहले राजकुमार हीरानी ने कहा था कि वह 200 करोड़ के क्लब की बजाय गुड फिल्म क्लब में शामिल होना चाहते हैं. विश्लेषकों का मानना है कि फिल्म की कहानी लोगों को पसंद आ रही है इस वजह से फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी. आमिर की पिछली रिलीज हुई फिल्म धूम-3 ने 280 करोड़ का कारोबार किया था, इस बार आमिर उस रिकॉर्ड को तोड़ते नज़र आ सकते हैं.■

दबंग-3 में आइटम सॉन्ग नहीं होगा: अरबाज खान

दबंग का सीक्वल बना रहे निर्माता-निर्देशक अरबाज खान का कहना है कि दबंग-3 में आइटम सॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा. इससे आइटम सॉन्ग की चाह रखने वालों को निराशा होगी. अरबाज खान ने अपनी फिल्म दबंग में मुन्नी बदनाम हुई और दबंग-2 में फेवीकोल से जैसे आइटम सॉन्ग थे. उनका कहना है कि वे इसे आइटम सॉन्ग की बजाय कहानी की जरूरत के हिसाब से आवश्यक संगीत मानते हैं उन्हें फिल्मी गाने को आइटम सॉन्ग का टैग देना भी नापसंद है अरबाज ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि फिल्मों में आइटम सॉन्ग का एक चलन बन गया है, लेकिन मैं अपनी फिल्मों में जो आइटम सॉन्ग डालता हूं वह फिल्म के विषय पर निर्भर करते हैं. मैं शायद अपनी अगली फिल्म में आइटम सांग नहीं रखूंगा. गानों को विषय के साथ मैच करना चाहिए. अरबाज फिलहाल अपने प्रोडक्शन की अगली फिल्म डॉली की डोली के प्रचार में व्यस्त हैं, जिसमें सोनम कपूर मुख्य भूमिका में हैं.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

05 जनवरी–11 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

सबसे दिलचस्प मुकाबले की तैयारी शुरू

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जनवरी से ही अपना बिहार दौरा शुरू कर रहे हैं. वो बिहार में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल कर एक तरीके से चुनावी अभियान का श्रीगणेश भी कर देंगे. उनका यह दौरा दो दिनों का होगा. इन दो दिनों में अमित शाह बिहार की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. कार्यकर्ताओं से मिल कर उनमें उत्साह और ऊर्जा भरने का काम करेंगे. खबर यह भी है कि अमित शाह अपने बिहार दौरे के दौरान कर्पूरी ठाकुर से जुड़े एक समारोह में भी शिरकत करेंगे. ज़ाहिर है, भाजपा यह बात समझ रही है कि बिहार की जातीय संरचना इतनी जटिल है कि उसे अपने साथ बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बिहार में पिछड़ा वर्ग का वोट काफी अहमियत रखता है. ऐसे में जदयू, राजद समेत भाजपा की नजर भी इस वोट बैंक पर है.

सरोज सिंह

झारखंड और जम्मू-कश्मीर के बाद अब भाजपा की पूरी नजर बिहार पर टिक गई है. राज्य में 2015 में चुनाव होने है. हालांकि चुनाव में अभी समय बाकी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. पार्टी की ओर से एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य सहयोगी दलों को भी ताकीद कर दी गई है. खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी अब अपना ज्यादातर समय बिहार को देने वाले हैं. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल तो यह भी कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 175 पर काम करना होगा. रामलाल ने कहा कि बहुमत में आने के लिए भले ही 122 सीटों की ही जरूरत है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मजबूत एवं सुशासन के लिए दो तिहाई बहुमत से मिली जीत जरूरी है. ज़ाहिर है, पार्टी आम चुनाव 2014 में मिले वोट के हिसाब से अपना गणित देख रही है. आम चुनाव में मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से उसे अच्छी-ख़ासी सीटें मिल सकती हैं. आम चुनाव में एनडीए को बिहार से 31 सीटें मिली थीं, जिनमें भाजपा को 22, लोजपा को 6 एवं लोक समता पार्टी को 3 सीटें मिली थीं. मोदी सरकार को बहुमत मिलने में बिहार और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है. इन दो राज्यों ने सौ से ज्यादा सीटें एनडीए को दी. अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपने प्रदर्शन को कम से कम बिहार विधान सभा चुनाव तक बरकरार रखें क्योंकि 2015 और 2017 का यानी बिहार और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य जनता परिवार के एक होने के साथ थोड़ा-बहुत बदल सकता है. यही वजह है कि भाजपा ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है और सहयोगी दलों को भी काम करने के लिए कह दिया है.

सबसे पहले तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जनवरी से ही अपना बिहार दौरा शुरू कर रहे हैं. वो बिहार में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल कर एक तरीके से चुनावी अभियान का श्रीगणेश भी कर देंगे. उनका यह दौरा दो दिनों का होगा. इन दो दिनों में अमित शाह बिहार की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. कार्यकर्ताओं से मिल कर उनमें उत्साह और ऊर्जा भरने का काम करेंगे. खबर यह भी है कि अमित शाह अपने बिहार दौरे के दौरान कर्पूरी ठाकुर समारोह में भी शिरकत करेंगे. ज़ाहिर है, भाजपा यह बात समझ रही है कि बिहार की जातीय संरचना इतनी जटिल है कि उसे अपने साथ बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बिहार में पिछड़ा वर्ग का वोट काफी अहमियत रखता है. ऐसे में जदयू, राजद समेत भाजपा की नजर भी इस वोट बैंक पर है.

झारखंड में सरकार बनाने और रघुवर दास को विधायक दल का नेता मनोनित कर के भाजपा ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है. रघुवर दास भी पिछड़ी जाति से आते है. उनके बहाने भाजपा बिहार में भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है. हालांकि, इसका असर क्या होगा, अभी से कहना मुश्किल है लेकिन राजनीति में प्रतीकों के महत्व को देखते हुए यह तो कहा ही जा सकता है कि भाजपा ने इस मामले में बाजी मार ली है. बिहार में उसके मुख्य विरोधी लालू यादव व नीतीश कुमार इधर जनता परिवार को एकजुट बनाने की जुगत में लगे हुए है. दिल्ली में 22 दिसंबर को इस संबंध में जनता परिवार का एक महाधरना भी हुआ. इस महाधरना के जरिए नीतीश कुमार और लालू यादव ने यह जताने की कोशिश की कि बिहार में मोदी के अपराजेय रथ को रोकने की कूवत है और वे दोनों मिलकर ऐसा कर भी सकते है. हालांकि, जनता परिवार एक झंडा, एक निशान और एक पार्टी के रूप में तब्दील हो पाता है या नहीं, या कब होता है, देखने वाली बात है. लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर सचमुच लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी का विलय हो जाता है और अगर ये दोनों दिग्गज एक निशान के तहत आगामी विधान सभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो भाजपा के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी अभी दिख रही है. लेकिन, यहां भी एक समस्या है और यह समस्या बहुत बड़ी है. समस्या यह है कि क्या लालू यादव या नीतीश कुमार बिहार विधान सभा चुनाव तक एक साथ रह पाएंगे? क्या ये दोनों दिग्गज एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं. सवाल है कि बिहार में इनका नेता कौन होगा? टिकट बंटवारा कैसे होगा? इन दोनों दलों के प्रखंड स्तर तक, गांव स्तर तक कार्यकर्ता हैं. कैसे ये अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए मना पाएंगे? फिलहाल इन सवालों का जवाब तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि कम से कम जनता परिवार एकजुट नहीं हो जाती. क्योंकि, जनता परिवार के एकजुट होने के बाद ही पता चलेगा कि बिहार में इस पार्टी का नेता कौन होता है, या इस महाविलय के लिए कौन सा फॉर्मूला तय किया गया है. जनता परिवार के लिए सब कुछ सही रहे इसके लिए जरूरी है कि ये महागठबंधन ईमानदारी से काम करे.

इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस बिहार विधान सभा चुनाव में अकेले भी मैदान में उतर सकती है. वैसे मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बिहार की राजनीति में कांग्रेस का एक भी चर्चित चेहरा तक नहीं दिखता. बिहार में अब तक जो भी थोड़ी-बहुत सीटें उसे मिली हैं वो गठबंधन के साथ रहते हुए ही मिली हैं. फिर भी यह खबर महागठबंधन के लिए अच्छी तो नहीं ही मानी जा सकती है क्योंकि जितना भी वोट कांग्रेस को मिलेगा वो असल में भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा करने वाला ही साबित होगा. बहरहाल, इन सब के बीच एक अंतिम सत्य यही है कि बिहार का दंगल अंततोगत्वा मोदी बनाम नीतीश की पुरानी लड़ाई का एक तरह से अंतिम फैसला साबित होगा. आम चुनाव से पहले से ही मोदी बनाम नीतीश की बात होती आ रही है. आम चुनाव में भले ही मोदी आगे निकल गए लेकिन असल परीक्षा बिहार विधान सभा चुना में ही होनी है. इस लड़ाई में अगर मोदी जीतते है तो उसके बाद नीतीश कुमार के पास विरोध के लिए बहुत ज्यादा हथियार नहीं बचेंगे. और अगर नीतीश इस चुनाव में बाजी मार जाते है तो एक बार फिर से नीतीश कुमार, नीतीश बनाम मोदी की लड़ाई में मजबूती से शामिल हो जाएंगे. तो इंतजार करिए बिहार विधानसभा चुनाव का. यह चुनाव निश्चित तौर पर 2014 के आम चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

'जीना चाहते हो, तो हंसना सीखो' का लोकार्पण

धन में नहीं, तप में शक्ति है. मूल्यवान जीवन के लिये जीवन में शांति आवश्यक है. इसी में आनंद और खुशी है. हंसना-मुस्कुराना आसान काम नहीं, किंतु जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट चले जाते हैं. यह विचार बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में, बिहार इंडस्ट्रीज ऐसोसियेशन सभागार में, आचार्य सुदर्शन की पुस्तक 'जीना चाहते हो तो हंसना सीखो' का लोकार्पण करते हुए त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रो सिद्धेश्वर प्रसाद ने व्यक्त किये. प्रो. प्रसाद ने पुस्तक का स्वागत करते हुए लेखक के विद्वतापूर्ण विचारों की सराहना की तथा शुभकामनाएं दीं. मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित बिहार विश्व विद्यालय सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो शशि शेखर तिवारी ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक में आये विविध निबंधों में लोक-जीवन से विभिन्न तात्त्विक विषयों पर सार्थक विमर्श किया गया है. पुस्तक को दो खंडों मे देखा जा सकता है, जिसके एक खंड मे धर्म और अध्यात्म है तो दूसरे में लोक-चिंता और इसके निदान का आग्रह देखा जा सकता है. सभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने कहा कि आचार्य सुदर्शन की लोकार्पित पुस्तक इस मायने में महत्त्वपूर्ण है कि इससे गुणवत्तापूर्ण और मूल्यवान जीवन जीने की प्रेरणा और संदेश मिलता है. 33 छोटे-बड़े निबधों का यह संकलन अनेक प्रकार से सभी सुधी और सामान्य पाठकों के लिये लाभकारी है. इसमें आध्यात्मिक चिंतन के साथ सामान्य गृहस्थ जीवन के तत्त्वों पर अत्यंत सरल भाषा मे चर्चा की गयी है. इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्य सेवी जियालाल आर्य, सम्मेलन के पं. शिवदत्त मिश्र, मृत्यंजय मिश्र करुणेश, राजीव कुमार सिंह परिमलेन्दु, पद्मश्री डॉ. रवीन्द्र राजहंस तथा प्रो. साधु शरण सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये. अतिथियों का स्वागत सम्मेलन के उपाध्यक्ष नृपेन्द्र नाथ गुप्त ने तथा धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ साहित्यकार बलभद्र कल्याण ने किया. मंच का संचालन कवि योगेन्द्र प्रसाद मिश्र ने किया. इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक राजु कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यसेवी बच्चा ठाकुर, डॉ. नरेश पांडेय चकोर, कवि रवि घोष, आचार्य पांचु राम, डॉ. अर्चना त्रिपाठी, डॉ. विनोद शर्मा, सुमन कुमार मलिक, श्रीकांत सत्यदर्शी, अंबरीश कांत, प्रो. अरुण कुमार सिन्हा, डॉ. दिनेश दिवाकर, पूर्व विधायक लालबाबू लाल, डॉ. विनय कुमार विष्णुपुरी, श्याम विहारी प्रभाकर, विश्वमोहन चौधरी संत, कवि सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो. कल्याणी कुसुम सिंह, देवांशु शेखर मिश्र, राकेश सिन्हा, सुनील सिंह छविराज तथा वेद प्रकाश वेदुआ समेत बड़ी संख्या में साहित्यसेवी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित थे.

पूर्व सांसद की पुण्य तिथि

पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया में स्थिति मदरसा परिसर में पूर्व सांसद मोतिउर्रहमान की 7 वीं पुण्य तिथि मनायी गयी. कार्यक्रम की शुरुआत मरहूम पूर्व सांसद के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गयी. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष वसील अहमद खां ने कहा कि रहमान साहब गरीबों के मसीहा थे. वे जन-जन की आवाज बन चुके थे. वहीं जदयू नेता अभय कुमार सिंह ने कहा कि रहमान साहब पटना से लेकर दिल्ली तक सफर किया. पूर्व नप उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि ऐसे महान नेता का पुण्य तिथि मनाना गौरव की बात है. वे चम्पारण के ही प्रदेश के नेता था. इस कार्यक्रम को जदूय नेता लालबाबू सहनी, प्रखण्ड राजद अध्यक्ष हाति खां, सुबोध पाठक, चुनू सिंह, अब्दुल बारी, लव कुमार यादव, जमील अख्तर, इमाशंकर प्रसाद समेत कई लोगों ने इनके जीवनी पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम के इपरान्त पाक के पेशावर आर्मी स्कूल के बच्चों की निर्मम हत्या पर दो मिनट का मौन रख कर शोक प्रकट किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन वसील अहमद खां ने किया.

इंतेजारुल हक

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

ठंढ का मौसम और परेशानियां
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
नव वर्ष की बधाई
डॉ.ओ.पी.शर्मा
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
Levokon-AZ
Levofloxacin 250 mg + Azithromycin 250 mg
Siliplex
OFFLOGY-OS
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of Ariskon Pharma

मोतिहारी

चुनौतियों व संघर्षों का साल रहा 2014

अपराधियों के गैंगवार से कराहता रहा चंपारण

इंतेजारुल हक

वर्ष 2014 चंपारणवासियों के लिए कठिन चुनौतियों व संघर्षों का वर्ष रहा. एक तरफ जहां लोग पूरे साल भू-माफियाओं, डकैतों व अपराधियों व लुटेरों के गैंगवार से कराहते रहे तो दूसरी तरफ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को ले कई समाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोग सड़कों पर आन्दोलन करते रहे.यहां भू-माफियों व अपराधियों के बीच पुलिस की आंख-मिचौली चलती रही और शहरवासी अनेक चुनौतियों से जुझते रहे.जमीन की खरीद व बिक्री में अपराधियों की पकड़ इस कदर मजबूत रही कि पुलिस प्रशासन बौना दिखता रहा और दबंगई के बल पर औने-पौने भाव में जमीन खरीदने व उसे महंगे दामों पर बेचने का सिलसिला जारी रहा.पूर्वी चम्पारण जिले के विभिन्न थानों में दर्ज काण्डों के मुताबिक वर्ष 2014 में 142 लोगों की जहां हत्याएं हुई वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए.इसके अलावा डकैती के 20,लूट के 22, चोरी के 603 व दुष्कर्म 38 मामले विभिन्न थानों में दर्ज किये गये. कोटवा में नुरहसन उर्फ लम्बू हत्याकाण्ड,मुफस्सिल के पतौरा में गोलु हत्याकाण्ड,मोतिहारी-अगरवा में देवयंती देवी हत्याकाण्ड,प्रधानडाक घर में गृह रक्षक की हत्या,मंटू शर्मा समेत दो की श्रीकृष्ण नगर में हत्या,छतौनी में चर्च के पास कृष्णा सिंह की हत्या व सुगौली में दोहरा हत्याकाण्ड काफी चर्चित आपराधिक घटनाएं रहीं और लोग सहमे रहे.इस दौरान पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठता रहा और लोग तरह-तरह की बातें करते रहे.इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से कई प्रयास किये गये और एक वर्ष में तीन पुलिस कप्तानों का तबादला व पदस्थापन हुआ. बावजूद इसके अपराधी अलग-अलग अंदाज में सक्रिय हो हिंसक घटनाओं को अंजाम देते रहे. पहले राज्य सरकार ने जिले की कमान एसपी विनय कुमार को सौंपी इसके बाद सुधीर कुमार यहां के एसपी बने और अभी सुनील कुमार यहां के एसपी हैं. हालांकि पुलिस को सफलता भी मिली और दर्जनों अपराधी पकड़े भी गये. सुगौली के सेल्समैन हत्याकाण्ड का पुलिस ने उदभेदन किया था और दो को पकड़ने में सफलता हासिल की थी.कमोवेश यही स्थिति पश्चिमी चम्पारण जिले की रही. भू-माफियाओं व अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोलता रहा और बेगुनाहों की हत्या होती रही. अभी सुनील कुमार मोतिहारी के एसपी हैं और इनका कार्यकाल कैसा होगा,और अपराध व अपराधियों पर शिंकजा कसने में किस तरह कामयाब होंगे, यह तो समय निर्धारित करेगा,किन्तु उन्होंने यहां अपनी पदस्थापना के साथ ही कई माओवादियों व दुर्दान्तों को पकड़ने में जो सफलता हासिल की है इसकी चर्चा आम जनता के बीच हो रही है. वहीं विभिन्न मुद्दो व समस्यों को लेकर विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों के लोग संघर्ष करते रहे.मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराने, मोतिहारी में स्थापित चीनी मिल प्रशासन की मनमानी व मिल मजदूरों का वर्षों से बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए मिल पर गेट पर किया धरना व भिक्षाटन, बदहाल मोतिहारी की मोतीझील को बचाने,राशन व केरोसिन में हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए किया गया विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन काफी चर्चित रहा.चंपारण विकास मोर्चा के बैनर तले केन्द्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना कराने व इसकी मंजूरी सदन में दिलाने के लिए किया आंदोलन हमेशा याद किया जायेगा. मोर्चा के अध्यक्ष राय सुन्दरदेव शर्मा,गुलरेज शाहजाद,समाज सेवी साजिद रजा,पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह,जदयू नेता अमरेन्द्र सिंह,ई. शबीह अहमद खां उर्फ मासूम खां, कुमार शिव शंकर, अब्दुल हमीद कैप्टन,प्रो. नसीम अहमद, नसीमा खातून, आदि एक बेहतर कार्ययोजना बना कर जनता का समर्थन लेते रहे और केन्द्र की सरकार पर दबाव बनाते रहे. समय-समय पर धरना व प्रर्दशन होता रहा. इसी तरह मोतिहारी चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों की समस्याएं भी काफी चर्चित रहीं.गन्ना उत्पादकों व मजदूरों को करोड़ों रुपये भुगतान कराने की मांग को लेकर कई दिनों तक लगातार धरना व प्रर्दशन चलता रहा. मजदूरों के परिजनों ने अपनी बदहाली का परिचय देते हुए भिक्षाटन भी किया. जिसकी चर्चा चारों तरफ होती रही. मोतिहारी में शहर में स्थापित बदहाल मोतीझील को बचाने व शहर वासियों की भावना इस झील से जोड़ने के लिए मोतीझील बचाओ अभियान समिति के लोग काफी जागरूक रहे और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का समर्थन लेते रहे.समिति के अध्यक्ष अंसारुल हक, उपाध्यक्ष शमशाद खां,डॉ. चन्द्र सुभाष,पत्रकार सुदिष्ट नारायण सिंह,आदि अपने मिशन में लगे रहे.हालाकि जिला प्रशासन भी आखिर समय में काफी मुस्तैद रहा और अंचलाधिकारी के माध्यम से अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई किया जाता रहा.इस के अलावा भी कई संगठनों द्वारा अनेक मुद्दों को लेकर समय-समय पर धरना-प्रदर्शन किया गया.कूल मिला कर वर्ष 2014 चम्पारणवासियों के लिए संघर्षो व चुनौतियों का वर्ष रहा.संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि एक तरफ जहां मोतिहारी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल गया वहीं कई मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई. ■

मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराने, मोतिहारी में स्थापित चीनी मिल प्रशासन की मनमानी व मिल मजदूरों का वर्षों से बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए मिल पर गेट पर किया धरना व भिक्षाटन,बदहाल मोतिहारी की मोतीझील को बचाने,राशन व केरोसिन में हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए किया गया. विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन काफी चर्चित रहा.चम्पारण विकास मोर्चा के बैनरतले केन्द्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना कराने व इसकी मंजूरी सदन में दिलाने के लिए किया आंदोलन हमेशा याद किया जायेगा.

feedback@chauthiduniya.com

सासाराम

अधिकारियों की जंग में सरकार का नुकसान

लाखों के अवैध पत्थर जा रहे बाहर

ममता चौहान

रोहतास जिले की सड़को पर रात के अंधेरे में फर्राटा भरते हुए निकल रहे विशालकाय वाहनों की आवाज से सड़क के किनारे रहने वाले लोगो की नींद तो हराम है ही. इन वाहनों पर प्रतिदिन लाखों रुपए के लादे गए अवैध पत्थरों को बाहर जाते देखकर भले हीं आम लोग छाती पीट रहे हों. यहां पुलिस प्रशासन को कोई गम नहीं. गम हो भी क्यों यहां तो पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी और इनके निचले कुर्सी पर बैठे अधिकारी के बीच जंग जो ठनी है. इस जंग में राज्य सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान भले ही हो जाए. इसकी उन्हें परवाह नहीं. यहां तो ट्रांसफर-ट्रांसफर का खेल खेला जा रहा है. इसके उपर रोकने की बाजी चल रही है. कहा तो यह भी जाता है कि करवन्दिया से प्रतिदिन निकल रहे सैकड़ों ट्रकों के पीछे इन्हीं पुलिस पदाधिकारियों में से एक का वरद हस्त प्राप्त है. वर्चस्व की जंग अपने अपने समर्थक पुलिस कर्मियों को लेकर चल रही है. रोहतास जिले से संबंध रखने वाले डीआइजी उमाशंकर सुधांशु की अपनी अलग धाक है. जबकि नौजवान एसपी के रूप में रोहतास में पदस्थापित किए गए चंदन कुशवाहा की बॉडी लैग्वेंज कुछ और कहानी कह रही है. आंतरिक तौर पर दोनों अधिकारियों के बीच कही कोई ताल मेल दिखाई नहीं देती. एक तरफ एसपी कोई कारवाई करते हैं तो दूसरी तरफ डीआईजी इस पर अपनी मोहर लगाने के बजाए प्रतिरोधात्मक कार्रवाई में जुट जाते हैं. जिसका ताजा तरीन उदाहरण हाल ही के दिनों में एक दर्जन से ज्यादा थानाध्यक्षों को तबादला का मामला है. जिसके बारह घंटे अंदर हीं डीआईजी ने रोक लगा दी. अंदर खाने की बात है कि तबादले की सूची में डीआईजी के कुछ पुलिस पदाधिकारी प्रतीक्षारत थे. जिनका नाम शामिल नहीं हुआ तो ऐसी कार्रवाई की गई. हालांकि डीआईजी उमाशंकर सुधांशु इस बात को सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि रोक नियमानुकुल था. अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय आरोप नहीं रहा हो. और उसकी पदस्थापना की अवधी अल्प रही हो तो बिना कारण इसका तबादला न्याय संगत नही होता है. सूची में कई पुलिस पदाधिकारी ऐसे थे. जिन्हें हाल ही में तबादला किया गया था और उनका पुन: तबादला कर दिया गया. डीआईजी किसी भी तरह के आंतरिक मतभेद व वर्चस्व की लड़ाई से इंकार करते हैं. परंतु रोहतास जिले से उनके पूर्व के पैतृक संबंध पर भी चर्चा का बाजार गर्म है. इधर रोहतास एसपी चंदन कुशवाहा द्वारा अवैध खनन क्षेत्र में बरती गयी नरमी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन के एक वर्ग में फैला असंतोष भी इस गुटबाजी और वर्चस्व की जंग को मोहर लगा रहा है. गत माह यही पुलिस प्रशासन रोहतास डीएम संदीप कुमार के साथ और डीएफओ अमीत कुमार के साथ मिलकर अवैध पत्थर खनन क्षेत्र में ऐसा अभियान चलाया था कि पूरे पंद्रह दिन इस अवैध कारोबार के चंबल में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था. क्रेशरों को उखाड़ फेका गया. प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में गाड़ियां जब्त कर वन विभाग के हवाले की गई. लगा कि जो काम बच्चु सिंह मीणा, नैयर हसनन खां, विकास वैभव, मनु महाराज जैसे एसपी अनुपम कुमार जैसे डीएम नही कर पाए वह संदीप और चंदन की जोड़ी चंद माह में कर दिखाएगी. बाद में पता चला कि यह चार दिन की चांदनी थी. अब तो करवन्दिया के अलावे बुढ़न के पहाड़ भी अवैध कारोबारियों द्वारा बेरहमी से तोड़े जा रहे हैं. पहले से ज्यादा पहाड़ में ब्लास्टिंग शुरू हो गई है. दोगुने और तीगुनी संख्या में गाड़ियां इन टुटे हुए पत्थरों को राज्य के दूसरे हिस्से में पहुंचा रही हैं. जो इतना अवैध है कि प्रतिदिन सरकार को कम से कम एक करोड़ रूपए का राजस्व नुकसान हो रहा है. आम लोग यही चर्चा करने में जुटे हैं कि यही प्रशासन अगर पंद्रह दिनों के लिए अवैध पत्थर खनन को एकदम से रोकने में सफल रहा तो अब कौन सी कमी आई की यह खनन दोगुनी रफ्तार से शुरू हो गया. अंदरखाने में जरूर ऐसी कोई बात है. जिसमें अधिकारियों को अवैध पत्थर खनन के खिलाफ नरम होने को बाध्य किया. या तो उपर से अधिकारी और सरकार में बैठे सरपरस्त लोग इसमें शामिल हुए. जिनके दबाव में अवैध पत्थर खनन शुरू हुआ नहीं तो अवैध खनन से जुड़े माफियाओं के काले हाथ पुलिस पदाधिकारियों के हाथों से जा मिले हैं. इसके अलावा कोई कारण नहीं दिखता, जिससे कि अवैध पत्थर खनन का कारोबार शुरू हुआ. इस कारोबार से जुड़ा हुआ प्रशासन का एक महकमा वन विभाग भी है. जिसके विभागीय अधिकारी रोहतास डीएफओ अमित कुमार से पूछे जाने पर वे कहते हैं कि यह सवाल हम से न करें तो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि प्रशासन के पास मेरे लिए पंद्रह बीस सशस्त्र जवान मौजूद नहीं हैं, जिनके बल पर हम अवैध खनन का कारोबार रोक सकें. एसपी चंदन कुशवाहा से पूछे जाने पर कहते हैं कि पहले भी अवैध खनन पर रोक लगी थी. अब भी रोक जारी है. पुलिस बल की थोड़ी कमी जरूर हुई थी. अब इसके लिए फिर से अभियान चलेगा. लेकिन कब ?

जब ये पहाड़ टूट कर इस काबिल हो जाएंगे कि शेखपुरा और गया की तरह ये निलामी के लायक नहीं रहे तब. यही सवाल सभी पूछ रहे हैं. रोहतास एसपी चंदन कुशवाहा भी डीआईजी से अपने मतभेद की बात को सिरे से नकारते हैं. परंतु हाल के दिनों में पुलिस पदाधिकारियों के तबादले. इस पर लगाई गई रोक अवैध पत्थर खनन में पुलिस कैंप की स्थापना फिर इसे हटाया जाना हाल के दिनों में रोहतास जिले के कई थानेदारों पर एसपी द्वारा की गई कार्रवाई. फिर डीआईजी द्वारा उठाए गए विपरीत कदम यह साबित कर रहे हैं कि रोहतास का पुलिस प्रशासन दो खेमों में बंटा हुआ है. इसका सीधा नुकसान सरकार के करोड़ों रूपए की हानि के रूप में सामने आया है. देखना यह है कि इन अधिकारियों के जंग को सरकार में बैठे लोग किस तरह से सुलझा पाते हैं या यूं ही इसे चलते रहने की छूट दिए जा रहे हैं कि रोहतास के साथ यहां की अकूत पत्थर संपदा लूटती जाए, सरकार का राजस्व चोरी होती रहे और लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैंडिल जला मनाया शोक

पाकिस्तान के पेशावर में स्थित सैनिक स्कूल पर हुए आत्मघाती हमले में मारे गये छात्रों के प्रति शोक सभा आयोजित की गयी.मोतिहारी निबंधन कार्यालय परिसर में कर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से कैण्डिल जलाकर शोक संवेदना व्यक्त की गई. सभा की अध्यक्षता जिला अवर निबंधक पदाधिकारी सुशील कुमार सुमन ने की. अवर निबंधक श्री सुमन ने कहा इस तरह की नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है जिससे आम आवाम सहित छोटे-छोटे बच्चे में काफी भय व्याप्त है. उन्होंने कहा कि इस इस तरह की घटना काफी निन्दनीय है. दो मिनट की शोक सभा के दौरान कार्यालय के सभी कर्मी एवं आम जनता शामिल हुई और इनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. मौके पर ईश्वर दास, नीरज कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद सरवर अली, राकेश वर्मा एवं विक्रमा सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे.■ - *इन्तेजारूल हक*

समस्त गोगरी एवं खगड़िया जिले वासियों को नववर्ष 2015 की हार्दिक बधाई
नववर्ष के शुभ अवसर पर गोगरी प्रखंड सहित जिले के तमाम नागरिकों, पदाधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, छात्र /छात्राओं एवं युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं।
डॉ. संजय कुमार (सर्जन) डॉ. रिंकल
स्वास्तिक हॉस्पिटल एण्ड स्टोन क्लीनिक, जमालपुर-गोगरी, खगड़िया
प्रीतम मिश्रा
डॉ. अखिलेश कुमार विद्यार्थी
रंजन कुमार सिन्हा
रीमा देवी
भाई संजय यादव
सनोज मिश्रा
पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत गोगरी-जमालपुर, खगड़िया
मोहन सिंह
राजस्व कर्मचारी, परबत्ता, खगड़िया
तिरंजय कुमार अध्यक्ष
नियोजित शिक्षक संघ, परबत्ता, खगड़िया
पृथ्वी चन्द्र सिंह
मुखिया
ग्राम पंचायत राज सौढ़ उत्तरी
रविश कुमार सचिव
नियोजित शिक्षक संघ, परबत्ता, खगड़िया
मुकेश कुमार सिंह
जदयू जिला महासचिव, खगड़िया
महेन्द्र प्रसाद साह
मुखिया
ग्राम पंचायत राज रटन प्रखंड-गोगरी, खगड़िया
बिट्टू कुमार
मनभावन स्वीट्स कॉर्नर
आलम बाजार चौक, नयागांव रोड,परबत्ता
Happy New Year!

एक नज़र

कार्यशाला का आयोजन

सामाजिक व पारिवारिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी विषय पर पिछले दिनों समस्तीपुर में एक कार्याशाला का आयोजन किया गया. निदान पलान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र चौरसिया ने किया. मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार बब्लू मौजूद थे. कार्यक्रम में अमित कुमार वर्मा, मुकेश कुमार, सुमन कुमारी, अमित कुमार मधुकर, रंजू कुमारी, राजीव व सुमन मिश्रा समेत अन्य थे.

आधार से परेशान बच्चे

देश में आधार कार्ड की बढ़ती उपयोगिता ने बड़ों के साथ ही बच्चों को भी परेशानी में डाल दिया है. समस्तीपुर जिले के मथुरापुर में प्रतिदिन दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य स्थानों से तकरीबन दो हजार के करीब लोग आधार कार्ड बनाने को लेकर पहुंच रहे है. इनमें बच्चों की संख्या भी काफी रहती है. परंतु लोगों की अधिक भीड़ हो जाने की वजह से अधिकांश लोगों को लौटना पड़ता है. कार्य में भागीदारी दे रहे महेंद्र प्रधान की मानें तो प्रतिदिन मेहनत के बाद भी मुश्किल से महज 5 सौ तक ही लोगों का कार्ड बन पा रहा है. स्कूल से पढ़ाई छोड़ कर आने वाले बच्चों को दोहरी परेशानी का सामना करने की विवशता बनी है.

वाजपेयी की मनायी जयंती

समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनायी गयी. भाजपा नेता राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी एवं मदन मोहन मालवीय को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की. मौके पर राजीव ने कहा कि वाजिब हकदार को सम्मान मिला. इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है. कार्यक्रम में प्रियरंजन ठाकुर, ध्रुवचंद्र ठाकुर, विशेश्वर राय, सत्यनारायण महतो, रंजीत ठाकुर, दिग्विजय ठाकुर समेत अन्य ने विचार व्यक्त किया. - *अमृता*

तालाब का होगा काया कल्प

पुपरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित पंचमेश्वर नाथ मंदिर ऐतिहासिक तालाब के काया कल्प का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है. बताया जाता है कि पूर्व सांसद सीताराम यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार यादव व वार्ड पार्षद सुकृति देवी की पहल पर नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक तालाब के सौदर्यीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. इस कार्य हेतु 97.33 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. राशि आवंटित किये जाने पर पुपरी नव निर्माण समिति के प्रमोद शर्मा, पप्पू शिवहरे, पंकज बाजोरिया, राज कुमार जोशी, परमानंद केजरीवाल, मनोज केजरीवाल, सुशील केजरीवाल समेत अन्य ने पूर्व सांसद यादव के अलावा नगर विकास मंत्री को धन्यवाद दिया है.

डीएम के निर्देश पर छापा

जिला पदाधिकारी डॉ. प्रतिमा के निर्देश पर सिविल सर्जन द्वारा गठित जांच टीम ने पिछले दिनों पुपरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित शिवम सेवा संस्थान नर्सिंग होम पर छापामारी की. टीम का नेतृत्व एसीएमओ दयानंद मलिक ने किया. छापामारी दल में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. केडी पूर्वे, औषधि निरीक्षक एआर आर्या, पीएचसी प्रभारी डॉ. सुरेंद्र कुमार, बीडीओ मनीष कुमार व अनि महेश शर्मा शामिल थे. बताया जाता है कि छापामारी के दौरान नर्सिंग होम में एक अप्रशिक्षित नर्स मिली. एसीएमओ ने माना है कि उक्त नर्सिंग होम अवैध है. उपलब्ध प्रमाण पत्र को भी फर्जी पाया गया. चिकित्सक, कमपाउंडर, ऑपरेशन थियेटर समेत अन्य सुविधा भी नहीं है. छापामारी को लेकर पुपरी शहर में कई अन्य नर्सिंग होम संचालको का हाथ पांव फूलता रहा. - *गोविंद*

सेमीनार का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के रेडक्रॉस भवन के सभागार में सुलभ इंटरनेशनल सेंटर के तत्वावधान में भारत स्वच्छता अभियान विषय पर एक सेमीनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व आईएएस उमा शंकर प्रसाद ठाकुर व लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मौके पर प्रो. राज कुमार गुप्ता, मनोज कुमार, आशा प्रभात, गीतकार गीतेश व उमेश कुमार समेत अन्य थे. - *वाल्मीकि*

राहुल बने युवा जदयू के संयोजक

पिछले दिनों युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने राहुल कुमार सिंह को सीतामढ़ी जिला युवा जदयू का संयोजक मनोनीत किया है. स्थानीय एक विवाह भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला जदयू के जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद ने नव मनोनीत संयोजक राहुल को माला पहना कर स्वागत किया. मौके पर वार्ड पार्षद पंकज कुमार गुप्ता, सुरेंद्र पटेल, चंदन सिंह सम्राट, नेहाल अहमद खान, बबलू मिश्र, नागेंद्र कुमार, रण विजय सिंह व चंदन कुमार समेत अन्य ने बधाई दी.

प्रतियोगिता का आयोजन

पिछले दिनों सीतामढ़ी शहर स्थित रेडक्रॉस के सभागार में गणितज्ञ रामानुजम की जयंती मनायी गयी. कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता नेता रामबाबू सिंह, गीतकार गीतेश व मैथेमैटिक्स क्लासेज के संचालक अजय कुमार ने केक काट कर किया. रालोसपा के जिला छात्र संसद के अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें गौतम कुमार को प्रथम, बेचन कुमार को द्वितीय व अभिमन्यु मिश्रा को तृतीय पुरस्कार दिया गया. साथ ही चतुर्थ से दस तक स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया. कार्यक्रम में नवीन कुमार, सत्यजीत झा, अश्विनी कुमार, अजमल अली व श्याम गुप्ता समेत अन्य थे.

राजकुमार की शादी बनी चर्चा का विषय

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के गोढ़िया टोला निवासी राज कुमार ने हाल ही में ताइवान की एक युवती ल्यू के साथ शादी रचायी है. इन दोनों के प्रेम विवाह के मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. शादी से शिरकत कर लौटे गीतकार गीतेश ने बताया कि मूलरूप से ताइवान निवासी युवती ल्यू को राज कुमार के साथ ही भारत के बिहार प्रांत की खूश्बू इसे यहा की दुल्हन बनने को बाध्य कर दिया. कुछ ऐसे ही अंदाज में ल्यू शादी के मौके पर ताइवान की भाषा में अपने पति के माध्यम से लोगों के बीच अपनी भावना का इजहार करती रही. बताया जाता है कि गोढ़िया टोला निवासी राजेंद्र कुशवाहा का पुत्र राज कुमार रंजन नई दिल्ली में पर्यटकों के लिए गाइड का काम करता है. जबकि ल्यू आर्किटेक्चर से स्नातक है. इन दोनों का प्रेम विवाह इन दिनों जिले में चर्चा का केंद्र बना है. - *वाल्मीकि*

शोभायात्रा निकली

श्रीश्याम परिवार फारबिसगंज के तत्वावधान में स्थानीय सिद्धसागर भवन से श्री खाटू नरेश के जयकारों के साथ एस.के. रोड, श्रीलक्ष्मीनारायण पथ, सदर रोड, पोस्टऑफिस चौक, श्री महाराजा अग्रसेन पथ, दीनदयाल चौक होते हुए भजन स्थल तक भव्य शोभायात्रा निकाली गयी. इस शोभायात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्री खाटू नरेश के साथ श्याम भक्तों ने एक, दो, तीन, चार... खाटू नरेश की जय जयकार की. आरक्षी इपाधीक्षक अजीत कुमार सिंह एवं थानाध्यक्ष विपिन कुमार के द्वारा शोभायात्रा में शामिल भक्तों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल मुहैया कराये गये. शोभायात्रा में प्रमुख रूप से श्रीश्याम परिवार के सर्व श्री विजय अग्रवाल (अधिवक्ता), जयकुमार अग्रवाल, श्याम भुपाल, दीपक अग्रवाल (सीए), गणेश भुपाल, पवन अग्रवाल, दिलीप खेमानी, अजय अग्रवाल (अररिया), जयप्रकाश अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, हरेन्द्र फिटकिरी वाला, आनंद फतेहपुरिया, पूनम पांडिया, पवन मिश्रा, रजत सिंह, संजय केशरी, मंचन केशरी, पप्पू डालमिया, केदार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, हरीश गोयल, विनोद चोखानी, संतोष चोखानी, दिनेश अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, श्रीमती सुलोचना धनावत, सरोज अग्रवाल, बबिता अग्रवाल, रंजू डालमिया सहित सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे शामिल थे. संजय अग्रवाल एण्ड ग्रूप कोलकाता के द्वारा नृत्य नाटिका के जरिये श्री खाटूनरेश की महिमा का वर्णन आकर्षक ढंग से साथ प्रस्तुत किया गया. ■

- *अजातषत्रु अग्रवाल*

सीतामढ़ी

सीतामढ़ी जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. लेकिन समुचित सुविधा के अभाव में खेल प्रतिभाओं का विकास मुश्किल बना है. करीब डेढ़ दशक पूर्व जिला मुख्यालय में खेल के विकास को लेकर स्टेडियम निर्माण की आधारशिला रखी गयी. निर्माण मद में अब तक करोड़ों रुपये का आवंटन भी मिला, परंतु प्रशासनिक लापरवाही का आलम है कि स्टेडियम महज एक चारागाह बन कर रह गया है. अब हाल ही में जिले के तीन अलग–अलग प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण को लेकर तकरीबन 60 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये है. जब जिला मुख्यालय में डेढ़ दशक बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है तो प्रखंडों के विकास का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है.

डेढ़ दशक बाद भी अधर में लटका है स्टेडियम निर्माण

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी जिले में अलग–अलग खेलों के कई चेहरे है, जो आने वाले दिनों में जिले ही नही बल्कि सूबे बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकते हैं. परंतु यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि ऐसी प्रतिभाओं के विकास को लेकर अब तक न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और न ही जिला प्रशासन ही गंभीर रहा है. आलम यह है कि क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबाल, फुटबॉल व एथलीट समेत अन्य खेल का विकास महज एक खानापूर्ति बन कर रहा गया है. वैसे प्रति वर्ष विभिन्न संगठनों के तत्वावधान में अंतरजिला व अंतरराज्य स्तर के बालक व बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है.

बताते चलें कि सीतामढ़ी जिले में खेल प्रतिभाओं की समस्या को सर्व प्रथम तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर ने गंभीरता से लिया था. वर्ष 1996 में कला, संस्कृति व खेल विभाग के तत्कालीन मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी के हाथों जिला मुख्यालय डुमरा स्थित परित्यक्त हवाई अड्डा मैदान के पश्चिमोत्तर में स्टेडियम निर्माण की आधारशिला रखी गयी थी. स्टेडियम निर्माण हेतु विधान पार्षद की पहल पर तत्कालीन राज्यसभा सांसद रजनी रंजन साहू ने 10 लाख रुपये अपने विकास मद से उपलब्ध कराया था. बताया जाता है कि उक्त राशि से स्टेडियम की मुख्य गैलरी का निर्माण ही कराया जा सका. पुन: वर्ष 2004 में तत्कालीन खेल मंत्री जर्नादन सिंह सिग्रीवाल ने एक बार फिर स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास कर

अर्जुन राय

देवेशचंद्र ठाकुर

डॉ. प्रतिमा

श्याम किशोर प्रसाद

मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत करीब सवा दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराये. उक्त राशि से निर्माण हेतु भवन प्रमंडल सीतामढ़ी को बतौर कार्य एजेंसी कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गयी. उपलब्ध राशि से स्टेडियम परिसर में चहार दिवारी के अलावा तीन दर्शक दीर्घा समेत अन्य कार्य कराये गये. जिसपर तकरीबन पौने 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये. जानकारों की मानें तो वर्ष 2006–07 में स्टेडियम निर्माण मद में सरकारी स्तर पर पुन: करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये जिले को उपलब्ध कराये गये, लेकिन राशि आवंटन के 5 साल तक कार्य की निविदा नहीं होने के कारण उक्त राशि वापस कर दी गयी. बावजूद इसके बताया जाता है कि नगर पंचायत डुमरा के खाते में करीब 1 करोड़ रुपये स्टेडियम निर्माण मद का अब भी पड़े हैं.

पूर्व सांसद डॉ. अर्जुन राय ने भी सीतामढ़ी जिले में खेल प्रतिभाओं के विकास की नियत से अपने सांसद कोश से राशि उपलब्ध कराई थी. बताया जाता है कि पूर्व सांसद के मद से उपलब्ध कराये गये करीब 18 लाख की लागत से स्टेडियम के पांच द्वार का निर्माण कराया गया. बताते चलें कि हालात यह हैं कि पूर्व निर्मित भवनों की समय गुजरने के साथ ही जर्जरता भी सामने आने लगी है. पूर्व की कार्य एजेंसी की मनमानी का आलम रहा कि स्टेडियम के अंदर के कमरों की दीवारों को बिजली की वायरिंग के लिए खोद तो दिया गया, परंतु वायरिंग करायी नहीं गयी. साथ ही महिला प्रतिभागियों की सुविधा के लिहाज से निर्मित शौचालयों को भी यथावत छोड़ दिया गया. वर्तमान में स्टेडियम परिसर दिन के उजाले में जहां दर्जनों भैस का चारागाह बना रहता है, वहीं शाम ढलते ही आवारा सुअरों का आरामगाह बन जाता है. नतीजतन प्रतिदिन स्टेडियम परिसर में खेल का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को भारी परेशानी का सामना करने की विवशता बनी है. सीतामढ़ी जिले में खेल के विकास की गति को बढ़ाने में अहम योगदान देने वाले श्याम किशोर प्रसाद की मानें तो जिले में वर्ष 1996 में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल तो वर्ष 2004 में अवध ठाकुर मेमोरियल राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है. इसके अलावा समय–समय पर अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता रहा है.

बता दें कि हाल ही में जिला पदाधिकारी डॉ. प्रतिमा ने सूबे के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के स्तर से मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय अथरी, बेलसंड प्रखंड के जगन्नाथ सिंह कॉलेज चंदौली एवं रीगा प्रखंड के महंत रामानुज उच्च विद्यालय परिसर में स्टेडियम निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी है. स्टेडियम निर्माण कार्य को लेकर जारी आदेश में डीएम ने कार्यपालक अभियंता से कार्य स्थल की फोटोग्राफी समय–समय पर कराने एवं गैर सरकारी व विवादित भूमि पर कार्य नहीं हो इसका ख्याल रखने को कहा है. बताया जाता है कि पूर्व में उक्त तीनों स्टेडियम के निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंपी गयी थी. परंतु जब उक्त कार्य एजेंसी ने कार्य शुरू नहीं किया तो पुनरीक्षित प्राक्कलन बना कर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को भेजा गया. जहा से स्वीकृति मिलने के साथ ही राशि भी आवंटित कर दी गयी है. अब जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल संख्या–1 के कार्यपालक अभियंता को स्टेडियम निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. बताया जाता है कि 20 लाख प्रति स्टेडियम की दर से कुल 60 लाख रुपये उक्त तीनों स्टेडियम के निर्माण में खर्च किये जायेंगे.

वहीं जिले के पुपरी अनुमंडल में दशकों से खेल प्रतिभा जिला को गौरवान्वित करता आ रहा है. जब सूबे बिहार में एनडीए–1 की सरकार बनी तो पुपरी में आयोजित एक समारोह में स्थानीय युवाओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पुपरी में स्टेडियम निर्माण की मांग की थी. इस वक्त तत्कालीन सीएम ने युवाओं से मांग पुरा करने का वादा किया था. सरकारी स्तर पर पुपरी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति भी मिली, परंतु जमीन उपलब्ध नहीं होने एवं उपलब्ध जमीन पर निर्माण नहीं कराये जाने के बीच युवाओं का सपना अधर में लटका जो अब तक यथावत है. बताया जाता है कि पुपरी अनुमंडल क्षेत्र में अलग–अलग स्थानों पर कई सरकारी जमीन मौजूद है, परंतु जानबुझ कर ऐसे जमीन का चयन किया गया, जो विवाद का केंद्र बन गई और स्टेडियम निर्माण का सपना धरा का धरा रह गया.

अब जिले में यह चर्चा जोर पकडने लगी है कि उपलब्ध राशि से निर्धारित समय सीमा के अंदर स्टेडियम निर्माण का कार्य पूर्ण होगा अथवा जिला की तरह ही कार्य एजेंसी की मनमानी का शिकार होकर प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण रह जायेगा, कहना मुश्किल है. वैसे वर्तमान जिलाधिकारी से जिले की खेल प्रतिभा को उम्मीदें हैं. तीन प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का आदेश का स्वागत करने हुए जिले के खिलाड़ियों ने पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में भी स्टेडियम निर्माण का मार्ग प्रशस्त कराने की उम्मीद लगा रखा है. वैसे चुनावी साल में विकास योजनाओं की सफलता पर लोग संदेह भी करने लगे है. इधर जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन स्टेडियम के कार्य को पूर्ण कराने की मांग भी की जाने लगी है. बताया जाता है कि अगर अविलंब निर्माण कार्य को पूर्ण नही किया गया तो अब खेल प्रतिभा चुनावी मुद्दा भी बना सकता है. अगर ऐसा होता है तो जिले की राजनीति की दिशा में बदलाव की आशंका से इनकार नही किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
05 जनवरी–11 जनवरी 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHI/2009/30467

कांग्रेस टूटने की कगार पर

लोकसभा चुनाव की हार के सदमे से कांग्रेस उबर भी नहीं पाई थी कि अलग-अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी उसे करारी हार झेलनी पड़ी. महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में हारने के बाद हाल ही में संपन्न हुए जम्मू-कश्मीर और झारखंड के चुनावों में भी उसे मुंह की खानी पड़ी है. इसके साथ ही कांग्रेस में एक दूसरे खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है. उत्तरप्रदेश में तो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह शुरू हो गया है.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

दीनबंधु कबीर

कांग्रेस के अंदर का असंतोष तमिलनाडु में पार्टी के विभाजन के बाद सतह पर आने लगा है. अब तो अंदेशा जताया जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कहीं प्रदेश में भी पार्टी की वही दशा न हो जाए जो तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन ने की. कांग्रेस के नेता स्वयं प्रकाश गोस्वामी ने पिछले दिनों जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ आवाज बुलंद की और जिस तरह चांडाल चौकड़ी से घिरे पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला, उससे भविष्य के संकेत साफ-साफ दिखने लगे हैं. गोस्वामी ने पहले इस्तीफा दिया फिर कांग्रेस नेतृत्व ने झेंप मिटाने के लिए गोस्वामी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस निष्कासन से कांग्रेस के फटे पर लगा भद्दा पैबंद और भी खुला-खुला दिखने लगा है. अब बगावत के सुर खुलेआम उठ रहे हैं. असंतुष्ट कांग्रेसियों ने जनवरी में लखनऊ में जुट कर खुलेआम विरोध जताने का ऐलान कर शीर्ष नेतृत्व को परेशानी में डाल दिया है. नए साल में असंतुष्ट कांग्रेसियों का लखनऊ में होने वाला जमावड़ा नया फ्रंट या पार्टी बनाने के संकेत दे रहा है. कांग्रेस में कार्यकर्ता बनाम नेता नारे से बदलाव की मुहिम शुरू करने के लिए महात्मा गांधी का बलिदान दिवस 30 जनवरी निश्चित किया गया है. कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मुखर तौर पर आवाज बुलंद करने वाले नेताओं में रामलाल राही भी शामिल हो गए हैं. पार्टी ने उनके खिलाफ भी तल्ख नोटिस जारी की है.

कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी ने पिछले दिनों पत्रकारों से आम कार्यकर्ताओं की पीड़ा साझा की और पार्टी नेताओं पर तमाम सवाल खड़े किए. सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के चांडाल चौकड़ी से घिरे होने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में काम करने वाले को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बना देता है और चुनाव में हारे हुए नेता को राज्यसभा में भेजने का निरंकुश फैसला लेता है. इन निर्णयों से पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत संदेश गया है. पांच रुपये और 12 रुपये में जनता को भर पेट खाना खिलाने की बात कर पार्टी को डुबोने वाले पार्टी के प्रवक्ता हो जाते हैं. लगातार बुरी तरह हारने के बावजूद आज तक उसकी समीक्षा नहीं हुई. जिम्मेदार नेताओं को हटाने के बजाए संघर्षों में लाठियां खाने वाले 30 जिला शहर अध्यक्षों को हटा दिया गया. गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल-प्रियंका या सोनिया गांधी की चाटुकारिता से नहीं, बल्कि विचारधारा को मजबूत करने से बच सकेगी. कांग्रेस को बचाने के लिए उसकी मूल विचारधारा को मजबूत किया जाए न कि केवल सोनिया गांधी के सामने ही नारे लगाने की परम्परा चलती रहे. प्रियंका को डूबती कांग्रेस को बचाने के लिए लाने के सवाल पर गोस्वामी का कहना था कि कांग्रेस को राहुल, प्रियंका नहीं, उसकी विचारधारा को मजबूत करके और आम कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान देकर बचाया जा सकता है. गोस्वामी ने नेतृत्व से यह भी पूछा कि केंद्र में दस वर्ष तक सत्ता का सुख भोगते रहे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने कितने कार्यकर्ताओं का क्या भला किया, इसे वे बाकायदा सूची दिखा कर बताएं. कांग्रेस नेतृत्व स्वयं प्रकाश के हमले से बौखला गई और कारण बताओ नोटिस के साथ ही निष्कासन का फैसला भी जारी कर दिया. हालांकि उसके पहले ही छात्र राजनीति के समय से ही कांग्रेस से जुड़े रहे स्वयं प्रकाश कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं और उनकी उपेक्षा किए जाने से क्षुब्ध गोस्वामी ने दिल्ली में यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना त्यागपत्र सौंपा था. गोस्वामी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. सोनिया गांधी को दिए गए त्यागपत्र में स्वयं प्रकाश गोस्वामी ने कहा है कि पिछले तीस वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा. यूपी की राजनीति में अनेक पदों पर रह कर मैंने पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी से कार्य किया. इसके बाद भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे और मेरे साथियों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का सदस्य बनाना भी गवारा नहीं किया. उत्तर प्रदेश में पिछले पंद्रह साल में तमाम ऐसे प्रयोग किए गए, जिससे पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया. प्रदेश की कमान ऐसे लोगों को दी गई जो दूसरे दलों से आए थे. पिछले पच्चीस साल से प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस बाहर है. लोकसभा चुनाव के बाद तो पार्टी बुरी दशा में पहुंच गई है. तबसे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और कांग्रेसियों में कुंठा व्याप्त हो रही है. इन्हीं वजहों से कांग्रेस में बगावत हो रही है. पार्टी की बुरी दशा और पराजय के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति की आज तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई. गोस्वामी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दशा देख कर दुखी मन से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में आए स्वयं प्रकाश गोस्वामी ने राजीव गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी.

स्वयं प्रकाश गोस्वामी ने पांच दिसम्बर को ही दिल्ली में सोनिया गांधी को अपना त्याग पत्र दे दिया था. इस्तीफे के चौदह दिन बाद प्रदेश कांग्रेस से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया. कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. हिलाल नकवी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी ने संगठन के प्रति घोर अनुशासनहीनता करने के आरोप में स्वयं प्रकाश गोस्वामी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. साथ ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री राम लाल राही को अनुशासन समिति के चेयरमैन ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता और अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर एक हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है. पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले कांग्रेसियों ने 30 जनवरी को लखनऊ में जुटने का ऐलान किया है. नए साल में असंतुष्ट कांग्रेसियों का लखनऊ में होने वाला जमावड़ा नया फ्रंट या पार्टी बनाने के संकेत दे रहा है. कांग्रेस के कुछ नेता इसके पीछे उन नेताओं पर भी इशारा कर रहे हैं जो कांग्रेस में लम्बे अरसे तक सत्ता सुख भोगते रहे, फिर दूसरी पार्टी में शरीक हो गए और राज्यसभा के सदस्य बन कर मौज करते रहे. जब उस पार्टी ने राज्यसभा की सदस्यता आगे बढ़ाने पर राजी नहीं हुई तो फिर पार्टी छोड़ दिया और अब प्रदेश में कांग्रेस को तोड़वाने पर लगे हैं. बहरहाल, कार्यकर्ता बनाम नेता का नारा देकर महात्मा गांधी के बलिदान दिवस 30 जनवरी पर लखनऊ में जुटने के बाद विद्रोह के सूत्रधार भी उजागर होंगे. 30 जनवरी के कार्यक्रम के लिए हर जिले में 10–15 ऐसे नेताओं से सम्पर्क किया जा रहा है जो कांग्रेस के सड़ चुके सिस्टम में आमूलचूल बदलाव चाहते हैं. गांधीजी के बलिदान दिवस पर नया फ्रंट या पार्टी बनाने जैसा फैसला भी संभव है. ■

feedback@chauthiduniya.com

...तो कांग्रेस का सपा में विलय कर दो!

लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व नौकरशाह पीएल पुनिया को राज्यसभा भेजने के आलाकमान के फैसले ने भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. पुनिया ही ऐसे कांग्रेसी रहे हैं जो लगातार राहुल-सोनिया के साथ मुलायम-अखिलेश की भी चाटुकारिता करते रहे हैं. कांग्रेस के अन्य नेता-कार्यकर्ता प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ विभिन्न मसलों पर तीखी प्रतिक्रियाएं देते रहे, लेकिन पीएल पुनिया ने इससे परहेज किया. पुनिया को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का सपा में विलय कर दिया जाना चाहिए. विवेक सिंह ने कहा कि पीएल पुनिया ने 60 साल तक आईएएस की आलीशान नौकरी की. इस दौरान वे मायावती और मुलायम दोनों के ही करीब बने रहे और अब कांग्रेस में होते हुए भी केंद्र की भाजपा सरकार की कृपा से एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष बने बैठे हैं. कांग्रेस नेतृत्व को जब मुलायम सिंह यादव से ही पूछकर राज्यसभा का टिकट देना था तो कांग्रेस का सपा में विलय ही क्यों नहीं कर दिया जाता. विवेक सिंह ने यह भी जोड़ा कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी बची है जो साम्प्रदायिकता के खिलाफ भाजपा के सामने खड़ी हो सकती है. विवेक सिंह ने कहा कि प्रदेश में 28 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन आलाकमान ने एक बार भी राज्यसभा का टिकट देने से पहले किसी से नहीं पूछा. ऐसे में हम एक तरह से बंधुआ मजदूर ही हो गए हैं. कांग्रेस विधायक विवेक सिंह ने राहुल गांधी को पत्र लिख कर कहा है कि बुंदेलखंड में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है. उन्होंने कहा कि जिन्हें बुंदेलखंड में जिलाध्यक्ष बनाया गया है वह फतेहपुर के निवासी हैं और जिन्होंने बांदा में कांग्रेस के लिए पसीना बहाया है वह बस मूकदर्शक बने हैं. विवेक कहते हैं कि यदि कोई उन्हें इस बात को लेकर बगावती समझता है तो बगावत ही सही. ■

अमेठी में संकट और बढ़ेगा

अमेठी राजघराने में बंटवारे की लड़ाई ने विचित्र किस्म का सियासी दृश्य खड़ा कर दिया है. कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह के विद्रोही पुत्र अनंत विक्रम सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में बढ़ती भाजपा दखलंदाजी भविष्य के कई संकेत दे रही है. लोकसभा चुनाव में राहुल को परेशानी में डाल कर हारने वाली स्मृति इरानी का अमेठी में लगातार बढ़ता प्रभाव और विधानसभा चुनाव के पहले अनंत विक्रम सिंह को भाजपा में शामिल करने की रणनीति साफ-साफ समझी जा सकती है. अनंत विक्रम का क्षेत्र की जनता पर खासा प्रभाव है. अमिता मोदी से रिश्ते के बाद अमेठी राजघराने का पारम्परिक प्रभाव डॉ. संजय सिंह से हट कर अनंत विक्रम सिंह और संजय सिंह की परित्यक्ता महारानी गरिमा सिंह की तरफ केंद्रित हो गया है.

कांग्रेस नेता डॉ. संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पूरे तामझाम के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई. अनंत का स्वागत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में प्रत्येक कार्यकर्ता को जुटाना होगा. भाजपा में शामिल हुए अनंत के समर्थकों को बूथ पर संगठन मजबूत करने के लिए कहा गया. अनंत ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा. पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं, लेकिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है. अनंत विक्रम सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते ही अमेठी के लोगों की पारम्परिक सहानुभूति लेने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने अमिता मोदी को कभी मां नहीं माना और न ही मानेंगे. अनंत ने सैयद मोदी हत्याकांड की जांच की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया. अनंत ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं देने के लिए अपने पिता को कोसा. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में अनंत का भाजपा से जुड़ना स्थानीय सियासत में तेजी से बदल रहे समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है. अनंत विक्रम सांसद संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह के बेटे हैं. पिछले दो दशक से संजय सिंह से अमिता मोदी को लेकर हुए विवाद के चलते अलग रह रही हैं. मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ कर आए अनंत विक्रम सिंह अपनी मां गरिमा सिंह को लेकर अमेठी राजमहल वापस आ गए हैं, जिसे लेकर दोनों पक्षों में टकराव चल रहा है. संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता मोदी सिंह अमेठी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं. अनंत के भाजपा में शामिल होने को निकट भविष्य में सौतेली मां और बेटे के बीच संभावित चुनावी संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है. लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के कारण राहुल को अमेठी सीट बचाने में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थीं. भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी का चुनाव के बाद भी अमेठी में लगातार सक्रिय बने रहना कांग्रेस की परेशानी का कारण है. अब अनंत विक्रम का भाजपा में शामिल हो जाना सियासी जंग को काफी रोचक बनाने वाला है. ■

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

आजम खान ने राज्यपाल पर बोला हमला

मर्यादा लांघ कर मर्यादा की वकालत

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार अपने वरिष्ठ मंत्री आजम खान को आगे कर भाजपा के खिलाफ राजनीति कर रही है. आजम खान कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कभी केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ तो कभी नेताओं के खिलाफ ऊल-जुलूल बयान देकर राजनीति गर्म करते रहते हैं. इस बार आजम ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ मोर्चा खोल कर राजनीति को गैर-संवैधानिक रास्ते पर बढ़ाने की दिशा दिखा दी है. राजनीति को समझने वाले यह मानते हैं कि आजम खान ऐसे बयान महज सुर्खियों में बने रहने के लिए नहीं देते, बल्कि उनका बयान समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सिखावे और उकसावे पर जारी होता है और इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ होते हैं. अभी हाल ही में उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल पर सीधा प्रहार करते हुए कहा था कि राम नाईक यूपी के राज्यपाल कम अयोध्या के पुजारी अधिक लगते हैं. अब उन्होंने राम नाईक की बर्खास्तगी की मांग करके फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है.

आजम खान ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी सीधा हमला बोला है. आजम ने कहा कि संघ बापू के हत्यारे को हीरो बनाने में लगा है. आजम ने दोहराया कि वह राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे. आजम ने राज्यपाल के प्रति बेहद तल्ख तेवर दिखाए और कहा कि राज्यपाल जिस तरह काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं, उस पर राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए. राज्यपाल संविधान की मर्यादा तोड़े तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए. राज्यपाल पर संवैधानिक मर्यादा के बाहर जाकर हमला करते हुए आजम ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए. अगर राज्यपाल संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है तो राष्ट्रपति को कार्रवाई करनी चाहिए. आजम ने कहा कि संघ ने हिन्दुस्तान में आतंकवाद की नींव डाली है, उस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए थी. आजम के मुताबिक नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था और संघ बापू के हत्यारे को हीरो बनाने में लगा है.

आजम खान ने साफ-साफ कहा कि वह राज्यपाल से छिड़े विवाद में चुप नहीं बैठेंगे. राज्यपाल के खिलाफ कड़े तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह बोल रहे हैं, उस पर राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए. अगर राज्यपाल संविधान की मर्यादा तोड़े तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए. कैबिनेट मंत्री ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को मर्यादा में रहने की भी सीख दी. आजम ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की नरेंद्र मोदी की धमकी के मसले पर कहा कि मोदी ऐसा नहीं कर सकते. वह प्रेसीडेंशियल जैसा सिस्टम चाहते हैं. मोदी संविधान को बदल देने पर तुले हैं. संघ से उनके वर्चस्व की लड़ाई

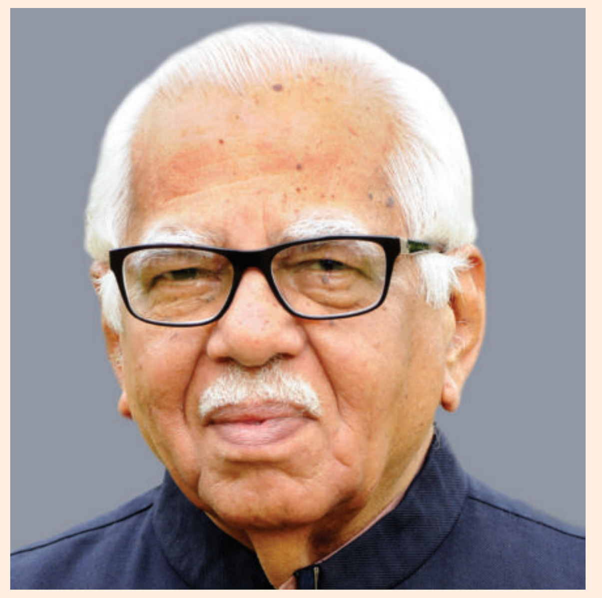

रिटायर्ड को कैसे नियुक्त कर दिया आजम ने?

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से रिटायर्ड आईएएस श्रीप्रकाश सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न विभागों के सचिव पद पर नियुक्त किए जाने को संज्ञान में लेकर उन्हें हटाए जाने की मांग की है. कागज पर श्रीप्रकाश सिंह विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) हैं, लेकिन आजम खान के दवाब में सभी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए उन्हें अल्पसंख्यक और नगर विकास विभाग के सचिव के साथ-साथ सूडा और उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बना दिया गया है. इसे अंधेरगर्दी बताते हुए कहा गया है कि एक रिटायर अफसर होने के कारण श्रीप्रकाश सिंह पर कोई सेवा नियमावली लागू नहीं होती और उनकी कोई जिम्मेदारी भी तय नहीं की जा सकती. ऐसे में जनता के सरोकारों से जुड़े इतने महत्वपूर्ण पदों पर उनके बैठने से लोकहित सीधे तौर पर प्रभावित होता है क्योंकि गलत ढंग से उपकृत होने के कारण श्रीप्रकाश सिंह जनता के प्रति नहीं, बल्कि आजम खान के प्रति विश्वासपात्र रहेंगे. लिहाजा, आईएएस कैडर नियमावली के खिलाफ जाकर की गई इस नियुक्ति को खारिज कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व का पालन करने की अपील की गई है.

में मतभेद हो गए हैं. धर्मांतरण को लेकर दिल नहीं, देश तोड़ने का काम हो रहा है. प्रधानमंत्री को साध्वी निरंजन और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के बयानों पर खामोशी तोड़नी चाहिए थी. प्रधानमंत्री खामोश हैं, इसलिए ऐसा करने वालों की हिम्मत अफजाई हो रही है. यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे चोर से कहें चोरी कर और शाह से कह जागता रह. होना तो यह चाहिए था कि जो संविधान को नहीं मान रहे, उन्हें देशद्रोही घोषित कर देते और संघ पर पाबंदी लगा देना चाहिए थी. उस संघ पर जिसने हिंदुस्तान में आतंकवाद की नींव डाली. नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था. इससे उलट संघ बापू के हत्यारों को हीरो बनाने में लगा है. दरअसल संघ ने तय कर लिया है, देश को बर्बाद कर देना है. उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि किसी भी बस्ती को जलाओगे तो आग दूसरी जगह भी लगेगी. ताली दोनों हाथ से बजती है, नुकसान सभी का होगा.

आजम के इस तरह के बयान पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हैं और विधानसभा चुनाव के आते-आते प्रदेश की राजनीति को दो ध्रुवों की तरफ केंद्रित करने के इरादे से यह सब किया जा रहा है. राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि आजम खान की बयानबाजी समाजवादी पार्टी की समझदारी है. इन बयानों का असर यह हो रहा है कि दूसरा पक्ष अदालत की शरण लेने लगा है. यह राजनीति के गरमाने और तल्ख होते जाने का ही संकेत दे रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में नगर विकास मंत्री आजम खान के बिगड़े बोल के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है. प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को आजम खान के बयान राज्यपाल कम अयोध्या के पुजारी अधिक लगते हैं राम नाईक के खिलाफ याचिका दायर की गई है. आजम खान के गैर संवैधानिक व्यवहार के खिलाफ राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से आजम खान को कोई हिदायत नहीं मिली है.

इसके पहले भी आजम खान के खिलाफ ऐसे कई मामले अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगाई और राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ को आतंकवादी संगठन कहे जाने के खिलाफ भाजपा नेता राजेंद्र वार्ष्णेय की तरफ से आजम खान के खिलाफ मुकदमा दाखिल हो चुका है. उस मुकदमे में सपा मुखिया मुलायम के शाही अंदाज में मनाए गए जन्मदिन समारोह का खर्च अंडरवर्ल्ड, तालिबान और दाऊद-सलेम की तरफ से उठाए जाने के आजम खान के विवादास्पद बयान को भी शामिल किया गया है. इसी साल नौ अक्टूबर को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगाई बताते हुए संघ को आंतकवादी संगठन करार दिया था. नाथूराम गोडसे मसले पर आजम ने फिर से संघ को आतंकवादी संगठन करार दिया. उल्लेखनीय है कि 21 नवम्बर को रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में मनाए गए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के शाही जन्मदिन के खर्चे के सवाल पर भी आजम खान ने कहा था कि सारा खर्च तालिबान और दाऊद इब्राहीम की तरफ से हो रहा है. याचिका में कहा गया है कि इस विवादित बयान से देश के लाखों लोग हतप्रभ और स्तब्ध रह गए थे.

प्रधानमंत्री, राज्यपाल और संघ को मर्यादा की सीख देने वाले आजम खान पर लाभ के दो-दो पदों पर एक साथ काम करने और फायदा उठाने का मामला अदालत में चल रहा है. आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के साथ-साथ रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति (चांसलर) के पद पर भी काम कर रहे हैं. चांसलर का पद लाभ के पद की श्रेणी में आता है. संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत लाभ के पद पर रहने वाला व्यक्ति विधायक नहीं हो सकता. अत: जिस दिन आजम चांसलर बने वह मंत्री पद के अयोग्य हो गए. इस तरह आजम खान के चुनाव को भी अवैध माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लाभ के पद पर रहते हुए विधायक का चुनाव जीता था, जो संवैधानिक रूप से गलत है. आजम खान 2006 में जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर बने थे. कानूनन चांसलर का पद लाभ का पद होता है. ऐसे में आजम खान का चांसलर रहते हुए विधायक चुना जाना भारतीय संविधान की धारा 191 का उल्लंघन है. धारा 191 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्य या केन्द्र सरकार के किसी लाभ के पद पर नियुक्त है, वह विधानसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं चुना जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो उसका चुनाव वैध नहीं होगा. ■

बड़े नाम, पर छोटे काम का महामोर्चा

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

महामोर्चा एक बार फिर आकार लेने को है. नामकरण पर सावधानी रखी गई. तीसरा मोर्चा भारतीय राजनीति में सकारात्मक छाप नहीं छोड़ सका. ऐसा लगा कि इसमें शामिल नेता अधिक दिनों तक साथ रह नहीं सकते और अधिक दूर तक साथ चल नहीं सकते. समय की कसौटी पर तीसरे मोर्चे की यह विशेषता सच साबित हुई. गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का मंसूबा भी कभी चरितार्थ नहीं हुआ. दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से किसी एक का सहयोग उन्हें पहले भी लेना पड़ा था, भविष्य में भी उन्हें इस मुद्दे पर अपना विकल्प खुला रखना होगा. यह बात अलग है कि इसके नेता सच्चाई को स्वीकार करने का साहस नहीं दिखा पाए. वह दोनों राष्ट्रीय दलों से बराबर की दूरी बनाकर चलने का दावा करें, लेकिन आमजन इतना नासमझ नहीं हैं. ऐसे में सबसे पहले इन नेताओं को सच्चाई स्वीकार करनी होगी. असत्य पर आधारित मोर्चा सिद्धांतवादी नहीं हो सकता. केवल नाम बदलने से हालात नहीं बदल जाते. बिहार और झारखंड में तो कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है. राजद और जद(यू) तथा कांग्रेस ने बिहार के उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, झारखंड विधानसभा के चुनाव में तीनों साथ रहे. ऐसे में जनता को धोखे में रखने का प्रयास क्यों हो रहा है. सच्चाई स्वीकार क्यों नहीं की जाती. यह भी नहीं चल सकता कि प्रदेश में कांग्रेस का विरोध तथा दिल्ली में उसके साथ तालमेल. इस दोहरी चाल से जनता को भ्रमित करने का प्रयास बन्द होना चाहिए. सपा और बसपा दोनों को इस नीति का खामियाजा उठाना पड़ा है. दस वर्षों तक वह लखनऊ में कांग्रेस का विरोध करती रही, नई दिल्ली में उसकी सरकार को बचाती रही. लोकसभा चुनाव परिणाम आंख खोलने वाले थे, लेकिन महामोर्चा में शामिल नेता इस पर विचार नहीं कर रहे हैं.

महामोर्चा में शामिल जद (एस) की स्थिति भी कर्नाटक में अलग नहीं है. देवगौड़ा के पुत्र कुमार स्वामी भाजपा के साथ सरकार चला चुके हैं. भविष्य में उन्हें ऐसा पुनः करने में कठिनाई नहीं होगी. उनकी पार्टी अपने प्रदेश में नम्बर तीन पर है. इतिहास को देखते हुए दावे के साथ कहा जा सकता है कि उनके विकल्प खुले रहेंगे. जरूरत पड़ने पर इस पार्टी को कांग्रेस या भाजपा के साथ जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी. इसी प्रकार बिहार में नीतीश कुमार का करिश्मा नहीं चला तो उनकी पार्टी का एक धड़ा भाजपा के साथ आ सकता है. कई नेता नरेन्द्र मोदी की समय-समय पर तारीफ भी करते रहते हैं. वाममोर्चे को भी कांग्रेस का साथ लेने में कठिनाई नहीं होगी. पश्चिम बंगाल में जिस तेजी से समीकरण बदल रहे हैं उसमें गैर भाजपा मोर्चा ही बन सकता है. गैर कांग्रेस मोर्चे की बात का खास मतलब नहीं है. उत्तर प्रदेश में सपा अवश्य गैर कांग्रेस गैर भाजपा की नीति पर अमल कर सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद समीकरणों का विकल्प यहां भी खुल सकता है. ऐसे में महामोर्चे का पहला आधार ही सही नहीं है. कम से कम इस दावे से जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता है.

दूसरा मुद्दा महामोर्चे में शामिल नेताओं के प्रभाव क्षेत्र को लेकर है. इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका प्रभाव अपने प्रदेश के बाहर तक विस्तृत हो. यह सभी अपने को राष्ट्रीय दल कहते हैं, सबके अपने-अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. लेकिन प्रदेश की सीमाएं उन्हें सीमित करती हैं. ऐसे में ये अलग रहकर लड़ें या साथ रहकर, इससे कोई लाभ संभव नहीं. नुकसान अवश्य हो सकता है. लालू यादव को साथ रखकर कोई सुशासन का दावा कैसे कर सकेगा.

इसके अलावा आपसी अविश्वास की भावना भी कम नहीं. लालू और नीतीश ने सत्रह वर्षों तक एक-दूसरे को जिस तरह नीचा दिखाया, मनोविज्ञान के अनुसार उससे पूरी मुक्ति संभव नहीं हो सकती. मुलायम भी यह बात भूल नहीं सकते कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए लालू यादव ने जमीन-आसमान एक कर दिया था. इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये नेता भविष्य में कब तक साथ रहेंगे. सत्रह वर्ष तक भाजपा के साथ रहने वाले नीतीश और शरद यादव सत्रह महीने में कैसे बदल सकते हैं. भाजपा जैसी पहले थी, वैसी ही आज है, पैंतरा तो जद (यू) के नेताओं ने बदला. क्या इन पर महामोर्चा विश्वास कर सकता है. नीतीश कुमार ने बिहार को लालू के जंगलराज से मक्त कराने के लिए जनादेश मांगा था. कल्पना कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव में पुनः लालू जीते तो नीतीश क्या करेंगे. लेकिन यह कल्पना मात्र है. महामोर्चे में दोनों नेताओं का शामिल होना दोनों का नुकसान करेगा. उप चुनाव की बात अलग थी. लेकिन जब सरकार बनाने के लिए सामान्य चुनाव होगा तो परिणाम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होंगे.

> महामोर्चा में शामिल जद (एस) की स्थिति भी कर्नाटक में अलग नहीं है. देवगौड़ा के पुत्र कुमार स्वामी भाजपा के साथ सरकार चला चुके हैं. भविष्य में उन्हें ऐसा पुनः करने में कठिनाई नहीं होगी. उनकी पार्टी अपने प्रदेश में नम्बर तीन पर है. इतिहास को देखते हुए दावे के साथ कहा जा सकता है कि उनके विकल्प खुले रहेंगे. जरूरत पड़ने पर इस पार्टी को कांग्रेस या भाजपा के साथ जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी. इसी प्रकार बिहार में नीतीश कुमार का करिश्मा नहीं चला तो उनकी पार्टी का एक धड़ा भाजपा के साथ आ सकता है.

तीसरा मुद्दा यह है कि महामोर्चा के घटक दलों की उत्तर प्रदेश व बिहार में सरकार है. उत्तर प्रदेश में सपा और बिहार में जद (यू) की राजद कांग्रेस समर्थित सरकार को चुनाव के दौरान अपने कार्यों का हिसाब देना होगा. इसी के आधार पर उन्हें चुनाव में उतरना होगा, और इसी के आधार पर मतदाता फैसला करेंगे. तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन पार्टियों ने महामोर्चा बना लिया है.

बिहार में जीतनराम मांझी के नेतृत्व में जैसी सरकार चल रही है, क्या उसके आधार पर महामोर्चा के दल विजय की उम्मीद कर सकते हैं. जीतनराम ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नीतीश जब भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे तब निवेश के बड़े प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे. जीतन राम उसे रद्द करके नीतीश को नीचा दिखा रहे हैं. नीतीश के विश्वासपात्र अधिकारियों को जीतन ने किनारे लगा दिया. इतना ही नहीं वह अति दलितों को पिछड़ों के खिलाफ लामबंद करके अपना प्रभाव बढ़ा रहे. एक तरफ महामोर्चा का मंसूबा, दूसरी तरफ जद (यू) में ही खेमाबंदी हो रही है. भविष्य में यह खेमाबंदी गुल खिला सकती है. अन्त में उन मुद्दों पर गौर कीजिए, जिन्हें मोदी सरकार को घेरने के लिए महामोर्चा द्वारा उठाया जायेगा. इसमें सबसे ऊपर कालाधान का मुद्दा है. विडम्बना देखिए इसी घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव और ओमप्रकाश चौटाला धार देंगे. महंगाई का मुद्दा भी महामोर्चा उठाएगा. लेकिन पांच वर्ष में मुद्रास्फीति न्यूनतम दर पर है. बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे. क्या छह महीने में यह मुद्दा उठाना व्यवहारिक है.

इसका दूसरा पक्ष देखिए. महामोर्चा के नेता छह महीने पुरानी मोदी सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं. क्या इन्हें एहसास है कि इससे बिना कहे उनकी प्रदेश सरकारें भी जवाबदेही होंगी. इससे बिहार में पन्द्रह वर्ष तक शासन करने वाले लालू और ग्यारह महीने तक प्रधानमंत्री देवगौड़ा भी जवाबदेह होंगे. वह छह महीने का हिसाब मांग रहे हैं. ग्यारह महीने से क्या किया था, बता सकते हैं. इसमें संदेह नहीं कि महामोर्चा चर्चा में तो बना रहेगा लेकिन इससे आगे बढ़ने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हरीश की चाल से भाजपा की बेचैनी बढ़ी

रेनू शर्मा

ईको सेंसिटिव जोन के विरोध में सूबे के मुख्यमंत्री हरीश का मोदी सरकार के विरूद्ध चल रही चाल ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है. कांग्रेस हो या भाजपा प्रदेश के सभी बड़े सियासी दल इस समय उत्तरकाशी से गंगोत्री तक ईको सेंसिटिव जोन के विरोध में जुटे हैं. मुख्यमंत्री हरीश रावत भी गाहे-बगाहे ईको सेंसिटिव जोन के विरुद्ध बयान देकर केंद्र सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ते. दोनों प्रमुख दलों के विरोध के इस शोर में यह सच छिप गया है कि दूनघाटी 1984 यानी पिछले करीब 30 वर्ष से ईको सेंसिटिव जोन घोषित है और इसकी वजह से न तो देहरादून का विकास रुका है न लोगों की आजीविका खत्म हुई है. इसके उलट देखा जाए तो ईको सेंसिटिव जोन होने की वजह से मसूरी या देहरादून यानी समूची दून घाटी का पर्यावरण काफी सुरक्षित है. ईको सेंसिटिव जोन के समर्थकों का कहना है कि जोन घोषित होने से केवल यह होगा कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह के विकास कार्य हो सकते हैं और किस तरह के नहीं. ईको सेंसिटिव जोन का समर्थन करने वालों का कहना है कि पर्यावरण की दृष्टि से अतिसंवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके उन्हें ईको सेंसिटव जोन घोषित करना चाहिए, ताकि उन्हें पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित किया जा सके और विकास कार्य को नियंत्रित किया जा सके. इको सेंसिटिव जोन से विकास बाधित नहीं होता है. केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मेगा प्रोजक्टों और मानकों के विरुद्ध होने वाला निर्माण ही प्रतिबंधित होगा है. जो मानवता के लिए आवश्यक है. इससे लोगों का संकट नहीं पैदा होने वाला है यही नहीं 20 डिग्री से अधिक ढ़लान वाले पर्वतीय ढालों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा. पहाड़ों के इन ढ़ालों पर वनीकरण भी होगा जो भूस्खलन रोकने में मददगार होगा. दिलचस्प बात यह भी है कि प्रदेश सरकार ईको सेंसिटिव जोन का विरोध तो कर रही है. साल 2013 जून की प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए 14 सितंबर 2013 को प्रदेश की कांग्रेस सरकार यानी बहुगुणा सरकार ने प्रदेश में मसूरी वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार, फूलों की घाटी, नन्दा देवी के लिए ईको सेंसिटिव प्लान तैयार कर लिया था. यही नहीं प्रदेश के छह नेशनल पार्क, बायोस्फेयर रिजर्व व दो वर्ल्ड हेरिटेज साइटों के चारों ओर के क्षेत्रों के ईको सेंसिटिव जोन का प्लान बनाने की बात तय हुई थी. इसी बैठक में कार्बेट का ईको सेंसिटिव जोन फाइनल होने तक कार्बेट पार्क के पास नए निर्माण में केवल प्रथम मंजिल तक के निर्माण की अनुमति देने की बात भी तय हुई.

क्या है ईको सेंसिटिव जोन

ईको सेंसिटिव जोन की अवधारणा 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी. वह मानते थे कि देश के विकास को टिकाऊ करना है तो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील नेशनल पार्क नदियों आदि के आसपास के कुछ क्षेत्रों में अवैज्ञानिक व अनियंत्रित विकास पर लगाम लगनी चाहिए. शुरुआत में ईको सेंसिटिव जोन की परिधि 10 किमी रखी गई थी, अब व्यवहारिकता को देखते हुए इसके लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है. भौगोलिक स्थितियों और जरूरत के मुताबिक हो सकती है.

कौन कर रहा है ईको सेंसिटिव जोन का विरोध-

दिसंबर 2012 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उत्तरकाशी से लेकर गौमुख तक के क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन घोषित किया था. केदारनाथ की आपदा से पहले तक प्रदेश में खनन व ठेकेदार लॉबी के समर्थन से ईको सेंसिटव जोन के विरुद्ध आंदोलन भी जारी थे. यह वह लॉबी है जो भाजपा व कांग्रेस जैसे बड़े सियासी दलों को चुनाव के लिए फंड मुहैया कराती और चुनाव के समय वोट बटोरने का ठेका भी लेती है. यही नहीं भाजपा व कांग्रेस के करीब दो दर्जन से ज्यादा विधायक रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं. इसी वजह से कांग्रेस व भाजपा का इस मामले में एक सा स्टैंड रहता है. माना जाता है कि इन्हीं के दबाव में ईको सेंसिटिव हर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से अधिसूचना रद्द करने या इसे संशोधित करने की अपील करती है और यह चेतावनी देती है कि वह अधिसूचना के खिलाफ अदालत भी जा सकती है. ईको सेंसिटिव जोन की वजह से न तो दून का विकास रुका है न लोगों की आजीविका खत्म हुई स्थानीय लोगों के हक के लिए व कृषि भूमि आदि पर किसी किस्म का संकट नहीं पैदा हुआ. दरअसल दोनों राजनीतिक दलों के ठेकेदार ही इस मसले में हो हल्ला मचाने के लिए अपने नेताओं को बेचैन करते रहते है. राज्य के पर्यावरण विद हिमालय की रक्षा के लिए इन नेताओं को ईश्वर सद्बुद्धि दे ऐसी कामना करते नही थक रहे हैं. ■

जुड़वा बहनों ने इतिहास रचा

चौथी दुनिया ब्यूरो

चार साल पूर्व ताशी-नुंग्शी ने जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कही थी तो पिता वीके मलिक ने बेटियों से प्रशिक्षण के कोर्स पर मन लगाने को कहा. मां अंजू मलिक तो पर्वतारोहण के सख्त खिलाफ थीं, बेटियों की जिद के आगे माता-पिता दोनों झुक गए, सिर्फ वही नहीं झुके, जुडवां बहनों ने मजबूत इरादों और जज्बे के दम पर एवरेस्ट समेत दुनिया की सात सबसे ऊंची चोटियों को अपने जीद के चलते अपने कदमों पर झुका दिया. दून की बेटियों की कामयाबी ने आज मां-पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया ही है इस पर सभी गर्व का अनुभव कर रहे है. हॉकी और एथलेटिक्स खिलाड़ी ताशी-नुंग्शी के पर्वतारोहण की शुरूआत वर्ष 2009 में उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (एनआईएम या निम) में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के दौरान हुई. पिता कर्नल वीके मलिक (रिटायर्ड) ने बताया कि दोनों बहनों ने कहा कि हमें एवरेस्ट चढ़ना है तो मैं चौंक गया. पहले लगा कि दोनों छोटी हैं. इसीलिए पहले कोर्स पूरा करने पर ध्यान देने के लिए कहा. मां अंजू मलिक ने तो साफ इनकार कर दिया. वर्ष 2010 में दोनों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग से स्कीइंग का कोर्स किया. 2012 में दयारा ग्लेशियर में 10 दिन का कोर्स किया और फिर उत्तरकाशी में सर्च एंड रेस्क्यू एडवांस के बाद प्रशिक्षक के कोर्स के लिए एडमिशन लिया. वर्ष 2012 में दोनों ने फिर एवरेस्ट चढ़ने की जिद की, मां नहीं मानी. इस बीच माता-पिता दोनों को कोर्स के लिए उत्तरकाशी छोड़ने गए तो एक प्रशिक्षक उन्हें देखते ही गेट पर लेने पहुंच गए. संस्थान के शिक्षक, प्रधानाचार्य ने भी काफी तारीफ की. इसके बाद मां अंजू ने एवरेस्ट मिशन के लिए हामी भरी और अक्टूबर 2012 से मिशन शुरू हो गया. अंटार्कटिका की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी माउंट विनसन मैसिफ पर तिरंगा फहराकर उत्तराखंड की ताशी-नुंग्शी ने नया इतिहास रच दिया है. माउंट विनसन पर फतह के साथ दोनों बहनों ने मिशन टू फॉर सेवन(दो बहनों का दुनिया की सात सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का मिशन) भी पूरा कर लिया. 23 वर्षीय ताशी और नुंग्शी सेवन समिट पूरा करने वाली दुनिया की पहली जुड़वां बहनें बन गई हैं. भारत से यह उपलब्धि हासिल करने वाली भी वे पहली पर्वतारोही हैं. खास बात यह है कि यह मिशन पूरा करने में उन्हें महज दो साल का वक्त लगा. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जोहड़ी गांव निवासी ताशी-नुंग्शी के मिशन 2 फॉर 7 का सातवां पड़ाव अंटार्कटिका का माउंट विनसन था. करीब 16045 फीट ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने के लिए ताशी-नुंग्शी ने बेस कैंप से सात दिसंबर को चढ़ाई शुरू की. पर्वतारोहण के लिए सबसे दुर्गम मानी जाने वाली इस चोटी पर चढ़ने में ताशी-नुंग्शी को दस दिन लगे. -40 (माइनस 40) डिग्री तापमान में ताशी-नुंग्शी ने अंटार्कटिका के स्थानीय समय के अनुसार 16 दिसंबर की शाम चार बजे (भारतीय समयानुसार 17 दिसंबर की रात 12.30 बजे) माउंट विनसन फतह की. थाली बजाकर खुशी का इजहार करने के साथ ही दोनों बहनों ने चोटी पर तिरंगा फहराया. दोनों बहनों का लक्ष्य 18 दिसंबर की शाम बेस कैंप पर पहुंच कर फतह किया. माउंट विनसन पर फतह के साथ ताशी-नुंग्शी सेवन समिट क्लब (दुनिया की सात चोटियां चढ़ने वालों का क्लब) के हाल ऑफ फेम में भी शामिल हो गई हैं. हाल ऑफ फेम में करीब 450 पर्वतारोही शामिल हैं. दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के 60वें एडिशन रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है. इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रसन्नता व्यक्त की है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दुर्गापाल की विधानसभा सदस्यता पर खतरा

राजकुमार शर्मा

बढ़ी सर्दी के मध्य हरीश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल कांग्रेस में की गई घर वापसी के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता लेकर बूरी तरह फंस गए हैं. राजनीति के जानकारों का मानना है कि निर्दलीय होते हुए भी कोई विधायक किसी पार्टी में शामिल होता है और उसके विरुद्ध यदि कोई अदालत जाता है तो दलबदल कानून के तहत उस विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है. हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सार्वजनिक रूप से अपने करीब 500 समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली थी और अब भाजपा इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है. विशेषज्ञ इस मामले में जो कानूनी स्थिति बता रहे हैं इससे कांग्रेस की कुनबा बढ़ाने की कवायद को करारा झटका लग सकता है. प्रदेश कांग्रेस टिहरी के निर्दलीय विधायक व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनै, देवप्रयाग से निर्दलीय विधायक व शिक्षा एवं पेयजल मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी व उत्तराखंड क्रांति दल के एकमात्र विधायक व शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके संकेत दिए थे. इतना ही नहीं कुछ अरसा पहले तो बसपा विधायक व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश व हरिदास को भी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा गरम रही थी. ये दोनों विधायक इस वक्त बसपा के निलंबित विधायक हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक निर्दलीय के अलावा उक्रांद के एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह पंवार भी किसी दल में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि दल बदल कानून के तहत किसी भी विधान मंडल दल को पार्टी संगठन से अलग करके नहीं देखा जा सकता यानी विधान मंडल दल का पार्टी संगठन से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता. दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में निर्दलीय विधायकों का दलों में शामिल होने का पुराना इतिहास रहा है.

2002 के विधान सभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत कर कुंवर प्रणव सिंह चौंपियन भी कांग्रेस विधायक हो गए थे. इसी तरह 2007 में निर्दलीय राजेंद्र सिंह भंडारी भाजपा के साथ हो गए थे. उसके बाद इन सभी को संबद्ध सदस्य बताया जाता रहा. प्रदेश की विधान सभा के पूर्व प्रमुख सचिव महेश चंद्र का कहना है कि दलबदल कानून के तहत कोई निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता. उनका मानना है कि संबद्ध सदस्य का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि कुंवर प्रणव चौंपियन व राजेंद्र सिंह भंडारी की विधानसभा की सदस्यता क्यों नहीं गई तो उन्होंने कहा कि चूंकि इन विधायकों ने तब किसी पार्टी की औपचारिकता सदस्यता नहीं ली थी, इसलिए दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि दुर्गापाल के मामले में कोई अदालत जाता है तो विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई हो सकती है. आगे भी अभी बसपा के विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जब उनमें से दो तिहाई विधायक टूटकर पार्टी के धड़े को कांग्रेस में शामिल कर लें. इस वक्त बसपा के विधानसभा में तीन विधायक हैं. देश में दलबदल विधेयक पर सख्त कानून के प्रबल पक्षधर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे जिनके दल के नेता इन दिनों दलबदल की राजनीति का सहारा ले कर सूबे में राजनीति चला रहे है.

> *भाजपा ने श्रम मंत्री दुर्गापाल के बहाने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला. हाल ही में दुर्गापाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है. भाजपा का यह मानना है कि दुर्गापाल को उनके क्षेत्र की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से नहीं, बल्कि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी बनाया है. नियम के मुताबिक ऐसे विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जानी चाहिए.*

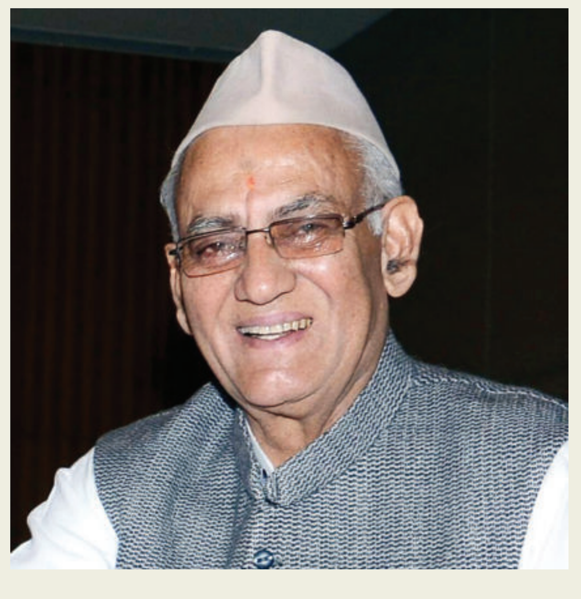

भाजपा ने श्रम मंत्री दुर्गापाल के बहाने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला. हाल ही में दुर्गापाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है. भाजपा का यह मानना है कि दुर्गापाल को उनके क्षेत्र की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से नहीं, बल्कि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी बनाया है. नियम के मुताबिक ऐसे विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जानी चाहिए. श्रम मंत्री दुर्गापाल की सदस्यता को खत्म कराने की मांग को लेकर भाजपाइयों ने विधानसभा सचिव को ज्ञापन सौंपा. भाजपा नेताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री दुर्गापाल ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा किया है. नियम के अनुसार इस तरह के जनप्रतिनिधि की सदस्यता तुरंत खत्म हो जानी चाहिए. संविधान की दसवीं अनुसूची में विघटन के आधार पर सदन का कोई निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी से अलग रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है तो वह किसी दल की सदस्यता ले लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी. इससे यह बात साफ हो जाती है कि यदि कोई सदस्य निर्दलीय निर्वाचित होकर आता है और चुनाव के बाद वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा. श्रम मंत्री की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा के सचिव को लिखित ज्ञापन सौंपा और मांग की कि निर्दलीय विधायक दुर्गापाल की विधानसभा सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए. क्षेत्र की जनता ने दुर्गापाल को बतौर निर्दलीय निर्वाचित किया है और इसे जनता के साथ धोखाधड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए. प्रदेश भाजपा के महामंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि ज्ञापन विधानसभा के सचिव को दिया गया है, इस समय स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे. भाजपा अब स्पीकर के फैसले का इंतजार करेगी. नेता पतिपक्ष अजय भट्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से न्याय की आस की है. ■

कांग्रेस ने दुर्गापाल की सदस्यता से पल्ला झाड़ा

हरीश रावत सरकार के कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल की विधायकी पर संकट को देखते हुए कांग्रेस ने दुर्गापाल को दी गई सदस्यता से पल्ला झाड़ लिया है. अपनी सरकार में मंत्री के गले में फंदा पड़ने की सम्भावना से पहले ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अब इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि दुर्गापाल को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है. उन्होंने कहा है कि विगत दिनों कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में दुर्गापाल और उनके समर्थकों को सदस्यता की 100 पुस्तिकाएं दी तो गई थीं उनकी ओर से कांग्रेस की सदस्यता के लिए आवेदन किया है या नहीं यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है. निर्दलीय विधायक व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल को मंगलवार को कांग्रेस भवन में आयोजित समारोह में सूर्य के उजाले में कांग्रेस परिवार में शामिल किया गया था. इस समारोह में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्यायक्ष व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे. कार्यक्रम में जोर-शोर से हरीश चंद्र दुर्गापाल को पुराना कांग्रेसी बताते हुए उनकी घर वापसी यानी कांग्रेस में फिर शामिल होने की घोषणा की गई थी. यही नहीं खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हरीश चंद्र दुर्गापाल को सदस्यता की पुस्तिकाएं सौंपी थीं. कैबिनेट मंत्री ने तब कहा था कि वह सदस्यता के लिए कितनी भी फीस देने को तैयार हैं. कैबिनेट मंत्री के कथित तौर पर कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया था और दुर्गापाल की विधायकी रद्द करने के लिए प्रमुख सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र के जरिए विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा था और इस मामले में दल- बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी. विधानसभा के नियम- कानूनों के जानकारों का कहना था कि हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है . इस मामले को अदालत में ले जाया जाता है तो इनके विरुद्ध दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है और इनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है. जानकारों का मानना है कि अगर भाजपा थोड़ा इंतजार कर लेती और कांग्रेस के सदस्यता अभियान के पूरा होने यानी दुर्गापाल के कांग्रेस सदस्यों की सूची में शामिल होने के बाद मुद्दा उठाती या अदालत में चली जाती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे. जानकारों का कहना है कि तब भाजपा के पास इस बात का पक्का व दस्तावेजी सबूत होता कि दुर्गापाल निर्दलीय विधायक होते हुए कांग्रेस के सदस्य बन गए हैं जो कि दल-बदल निरोधक कानून का उल्लंघन है. बहरहाल कांग्रेस को घेरने की हड़बड़ी में लगता है भाजपा की ओर से उठाया गया मुद्दा इतना पुख्ता नहीं रह गया है. हरीश रावत के सारथी किशोर ने पल्ला झाड़ कर मंत्री को साफ बचाने में सफल होते दिख रहे है. ■

feedback@chauthiduniya.com